राष्ट्रीय संस्करण

भारतीय ग्रैंडमास्टर हंपी बनीं महिलाओं की विश्व रैपिड चैंपियन

>>14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 202

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 30 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

युवाओं को नापसंद है अराजकता : मोदी

संबोधन ▸ साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री ने युवाओं को दी देश आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी

युवा सिस्टम फॉलो करते हैं और जरूरत पड़ने पर सवाल भी उठाते हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

साल के आखिरी 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और दलों की राजनीति पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का युवा अराजकता, अव्यवस्था, परिवारवाद और जातिवाद पसंद नहीं करता है। वह सिस्टम को फॉलो करना पसंद करते है और अगर सिस्टम काम न करे तो बेखौफ होकर सवाल करता है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने युवाओं की पीठ पर हाथ फेरते हुए यह बताया कि हाल के दिनों की हिंसा युवाओं का आक्रोश नहीं था बल्कि उनका दुरुपयोग किया गया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को याद भी दिलाया कि उसका परिवारवाद युवाओं को कभी नहीं भा सकता है। मोदी ने युवाओं को भी सचेत किया कि अपनी ताकत पहचान कर तय करें कि वह युवावस्था का उपयोग किस तरह करते हैं। उनकी सकारात्मक ताकत ही देश की ताकत तय करेगी।

मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)।(प्रेट्र)

स्वामी विवेकानंद से लें सीख

स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपेक्षा की कि आगामी दशक में अपने दायित्वों के बारे में चिंतन करें क्योंकि यह युवाओं का दशक साबित होने वाला है। उन्होंने खासतौर से 21वीं सदी में जन्मे युवाओं को संबोधित किया और कहा, 'ये युवा सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं, निश्चित ही देश को गति देने वालों में इनकी भूमिका अहम व सक्रिय होगी।' ध्यान रहे कि इस सदी में जन्मे युवा पहली बार 2019 में लोकसभा में वोट देने के लायक हुए थे और अब हर साल लाखों ऐसे युवा मुद्दों की समझ के साथ ही प्रतिनिधि चुनने के योग्य होंगे।

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में समृद्ध है भारत का इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत का समृद्ध इतिहास रहा है। इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान हमारी सभ्यता जितना ही प्राचीन है। मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की ओर से सूर्य के अध्ययन के लिए प्रस्तावित आदित्य सेटेलाइट का भी जिक्र किया। उन्होंने इसरो की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। मोदी ने पूर्वोत्तर के रहने वाले रिपुन का नाम भी लिया, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने का रास्ता तलाशने की अपील की है। रिपुन फिलहाल दक्षिण भारत में रहते हैं।

संसद में हुआ रिकॉर्ड काम

पीएम ने नए साल की शुभकामना देते हुए संसद में देशवासियों का भरोसा बढ़ाने का भी प्रयास किया। जनता को बधाई देते हुए कहा, आपके चुने प्रतिनिधियों ने संसद में साठ साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोनों सदनों में सौ फीसद से ज्यादा काम हुए।

यूं तो युवा वर्ग हमेशा से प्रधानमंत्री और भाजपा की प्राथमिकता में रहा है, पर 'मन की बात' की शुरुआत युवाओं से करने का खास अर्थ था। दरअसल पिछले दिनों सीएए को लेकर जिस तरह राजनीतिक दलों ने विश्वविद्यालयों को आंदोलन में शामिल किया, उस पर पीएम ने उंगली उठाई। मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह प्रदर्शन के दौरान आगजनी और अराजकता फैली वह युवाओं का काम नहीं हो सकता है। भाजपा और पीएम की ओर से पहले भी कहा जाता रहा है कि प्रदर्शन राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। मोदी ने युवाओं के इस अधिकार को स्वीकारा कि अगर सिस्टम काम न करे तो वे आवाज उठाएं। कहा, 'कभी कहीं सिस्टम रिस्पांड न कर रहा हो तो वह सवाल उठाते हैं.. यह सोशल मीडिया जनरेशन है, कुछ गलत हो रहा हो तो तत्काल वीडियो बनाकर समाज को सतर्क कर देता है, वह खुद सिस्टम का पालन पसंद करता है और दूसरों से भी यही अपेक्षा करता है।'

स्वदेशी अपनाएं, स्वरोजगार बढ़ाएं : पीएम ने स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि 2022 में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने तक सभी स्थानीय उत्पाद खरीदने का प्रयास करें ताकि स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिले। मोदी ने स्वरोजगार की दिशा में प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश के कादीपुर की महिलाओं का भी उल्लेख किया, जिन्होंने चप्पल बनाने का प्रशिक्षण लेने के बाद संयंत्र स्थापित किया है। मोदी ने फूलपुर के पुलिसकर्मियों की भी सराहना की, जिन्होंने इन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अपने व परिवार के लिए इनसे चप्पल खरीदना शुरू किया है। मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की हिमायत योजना का जिक्र करते हुए कहा, इससे प्रदेश के 18 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और अब वह आगे बढ़ रहे हैं।

गरीबों की करें मदद : प्रधानमंत्री ने लोगों से गरीबों की मदद के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कहा कि युवाओं को छोटे-छोटे समूह बनाकर समाज की प्रगति में योगदान देना चाहिए। इस संदर्भ में मोदी ने बिहार के बेतिया जिले के संकल्प-95 का जिक्र भी किया। यह पश्चिमी चंपारण के केआर हाईस्कूल के 1995 बैच के छात्रों का समूह है। इन्होंने क्षेत्र में लोगों के बीच स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में प्रयासरत हैं। बेतिया मेडिकल कॉलेज और कई अन्य संस्थान भी इनके साथ जुड़े हैं।

सात करोड़ से ज्यादा पाठकों के साथ दैनिक जागरण फिर शीर्ष पर

जेएनएन, नई दिल्ली : पाठकों के भरोसे पर लगातार खरा उतरते हुए दैनिक जागरण ने फिर खुद को देश का शीर्ष समाचार पत्र साबित किया है। 'इंडियन रीडरशिप सर्वे' (आइआरएस) के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, सात करोड़ से ज्यादा पाठकों के साथ दैनिक जागरण की लोकप्रियता और साख मजबूत बनी हुई है।

मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल (एमआरयूसी) ने 2019 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए आइआरएस के आंकड़े जारी किए हैं। एमआरयूसी के अनुसार, तीसरी तिमाही में शहरी पाठकों में अखबार की पहुंच 52 फीसद पर कायम है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 31 फीसद हो गया है। पाठकों के भरोसे के दम पर ही पिछले साल दैनिक जागरण को 'दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ न्यूज ब्रांड' का खिताब भी मिला था। विश्वसनीयता, सटीक जानकारी और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले अपने अभियानों की बदौलत दैनिक जागरण ने एक अलग पहचान बनाई है। सात करोड़ पाठकों के साथ ने इस पहचान को और मजबूती दी है।

45 लाख पूर्व सैनिकों का निजी डाटा नहीं लौटाने पर रिपोर्ट दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के लिए 45 लाख पूर्व सैनिकों की व्यक्तिगत जानकारी वाले डाटाबेस को वापस नहीं करने पर रक्षा मंत्रालय ने निजी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला आरटीआइ आवेदनों व कोमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) के पत्राचार के जरिये उजागर हुआ है। बत्रा को हाल ही में रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने ईमेल किया था जिसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (एक्स सर्विसमैन कांटिब्यूट्री हेल्थ स्कीम-ईसीएचएस) में नामांकित 45 लाख पूर्व सैनिकों के निजी डाटा को नहीं सौंपने वाली निजी कंपनी के खिलाफ 19 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। बत्रा ने आरटीआइ आवेदन के जरिये मुद्दे से संबंधित 'फाइल नोटिंग्स' मांगी थीं।

ईसीएचएस भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अफसरों और उनके आश्रितों को मेडिकल सुविधा प्रदान करती है। आरटीआइ आवेदन के जवाब में प्राप्त सूचनाओं से पता चलता है कि फर्म की ओर से 'गोपनीयता प्रमाणपत्र' के रूप में किसी भी लिखित पुष्टि के अभाव में 'पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (ईसीएचएस) के लाभार्थियों के डाटाबेस की सुरक्षा की पुष्टि नहीं की जा सकती है।'

2010 में रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ पांच साल का अनुबंध किया था पेज>>3

सरोकार

रोशन किया अमिताभ से लेकर अंबानी तक का आशियाना

कोलकाता : हुगली जिले का चंदननगर शहर जगद्धात्री पूजा व लाइटिंग के लिए विख्यात है। यहां की बत्तियों से बिग बी और मुकेश अंबानी का घर तक रोशन हो चुका है। इनके पीछे हाथ है लाइट आर्टिस्ट सुप्रीम कुमार पाल का। (पेज-11)

जागरण विशेष

बिहार में पांच बेजुबान, चला रहे हुनर की दुकान

पटना : पांच दोस्तों की जुबां तो नहीं है, मगर इनका हुनर बोलता है। सभी दोस्त चिराग टेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। इनकी दिव्यांगता कभी काबिलियत के आड़े नहीं आई। इस दुकान से ही इनका परिवार चल रहा है। (पेज-11)

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का निधन

स्वामी विश्वेश तीर्थ का फाइल फोटो। प्रेट्र

उडुपी : दक्षिण भारत के प्रमुख धर्मगुरुओं में एक पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 88 वर्षीय स्वामीजी रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कर्नाटक सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। द्वैतवाद के दार्शनिक मध्वाचार्य द्वारा स्थापित अष्ठ मठों के विश्वेश तीर्थ सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे। 19 दिसंबर को सांस लेने में दिक्कत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (पेज-7)

बेअसर होगी कश्मीर पर ओआइसी की बैठक

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- पाक के कहने पर सऊदी अरब बुला सकता है विशेष बैठक
- बैठक बाद जारी होने वाले बयान को लेकर बहुत फिक्रमंद नहीं भारत

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच भले ही कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन (ओआइसी) की विशेष बैठक बुलाने की सहमति बनी हो लेकिन इसकी वजह से भारत की सऊदी अरब या ओआइसी के अधिकांश दूसरे देशों से रिश्तों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत ओआइसी के सभी प्रमुख देशों के साथ लंबी रणनीतिक साझेदारी की नींव रख चुका है। साथ ही ओआइसी की विश्व पटल पर बेहद कमजोर होती साख भी एक वजह है कि भारत प्रतिक्रिया जताने के बजाए शांत है। वैसे पाकिस्तान की तरफ से प्रस्तावित यह बैठक कब और कहां होगी, इसकी भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊदी पिछले शुक्रवार इस्लामाबाद पहुंचे जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी व पीएम इमरान खान से हुई। भेंट के बाद पाक विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि, 'कुरैशी ने भारत के कश्मीर, सीएए व एनआरसी का मुद्दा उठाया। बातचीत में कश्मीर को लेकर ओआइसी की सक्रिय भूमिका पर चर्चा की गई है।' इस बयान के बाद ही भारत व पाक के मीडिया में यह खबरें आईं की कश्मीर पर विशेष बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि पाक के कहने पर सऊदी अरब ने ओआइसी की विशेष बैठक बुलाने की बात मान ली है। दरअसल, सऊदी अरब के कहने पर पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने मलेशिया व तुर्की की अगुवाई में इस्लामिक देशों की एक दूसरी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इसके एवज में ही पाक सरकार ने कश्मीर पर ओआइसी की विशेष बैठक बुलाने की मांग रखी थी।

वैसे कश्मीर पर ओआइसी पहले भी तल्ख टिप्पणी करता रहा है, इसके बावजूद अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। कई देश भारत को आश्वस्त करते रहे हैं कि ओआइसी का बयान उनके द्विपक्षीय रिश्तों से अलग है। पिछले वर्ष पाक के गंभीर एतराज के बावजूद ओआइसी बैठक में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसमें हिस्सा लिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया है। इन दोनों देशों ने अभी तक कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। 30 अक्टूबर, 2019 को जब मोदी रियाद की यात्रा पर थे तब दोनों देशों के बीच तीन सुरक्षा समझौते हुए जिसमें एक रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन को लेकर था। इस तरह का परिषद सऊदी अरब ने विश्व के आठ देशों के साथ करने का फैसला किया है और इसमें पाकिस्तान नहीं है। दुनिया में जब साफ व स्वच्छ ईंधन की मांग बढ़ रही है तो भारत ओआइसी के सऊदी, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, नाइजीरिया जैसे देशों का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार देश है। इन देशों में 70 लाख भारतीय काम करते हैं और कोई भी दूसरा मुल्क इतने बड़े प्रशिक्षित कामगार उपलब्ध नहीं करा सकता।

ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय सऊदी अरब के साथ रिश्तों को लेकर आश्वस्त है। देश के प्रमुख रणनीतिक व कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी कहते हैं, 'यह सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को नियंत्रण में रखने का एक संकेत है। बैठक को होने में महीनों लग जाएंगे। वैसे भी ओआइसी पहले भी कई बार कश्मीर पर बहस कर चुका है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी कोई खास अहमियत नहीं है।'

झारखंड के 11वें सीएम के रूप में हेमंत सोरेन ने ली शपथ, सरकार ने किया पहला फैसला

खत्म होंगे पत्थलगड़ी समर्थकों पर देशद्रोह के केस

राज्य ब्यूरो, रांची

- शपथग्रहण के दौरान बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे

झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले फैसले में हेमंत सोरेन ने पत्थलगड़ी समर्थकों पर से देशद्रोह के मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उनका यह फैसला चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में शुरुआत माना जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 6 से 8 जनवरी 2020 तक विधानसभा का पहला सत्र लाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने तीन फैसले और अन्यान्य के तहत सात मामलों पर विचार कर सभी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले हेमंत ने रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम के अलावा राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथग्रहण के दौरान

हेमंत सोरेन जागरण

बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मौके पर उपस्थित थे।

यह था पत्थलगड़ी आंदोलन : आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें गांव के श्मशान से लेकर गांव की सीमा तक पत्थर गाड़कर संदेश दिया जाता है। गांव और जमीन की सीमा इंगित करने, किसी व्यक्ति की स्मृति में, महत्वपूर्ण अवसरों को याद रखने तथा समाज के महत्वपूर्ण फैसले को लोगों तक पहुंचाने के लिए धरती में पत्थर गाड़ते हैं। इसका पारंपरिक महत्व किसी सरकारी दस्तावेज या सीमांकन से ज्यादा है। इसे ही पत्थलगड़ी कहा जाता है। यही पत्थलगड़ी क्षेत्रों में सरकार को नकारने तथा स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के आंदोलन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। पत्थलगड़ी अभियान के तहत आदिवासी अपने संदेश को पत्थर पर लिखकर गांव की सीमा के पास गाड़ देते हैं। इस पर लिखा होता है कि गैर आदिवासी को बिना अनुमति गांव में प्रवेश नहीं करना है।

हेमंत के बहाने एकजुट हुए भाजपा विरोधी दल

राज्य ब्यूरो, रांची : हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपा विरोधी दलों के मेगा शो के तौर पर देखा जा रहा है। एक मंच पर इससे पहले इतने ज्यादा नेताओं का जुटान बंगलुरु में हुआ था, जब जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। इस समारोह में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के कद्दावर नेता एमके स्टालिन, कनिमोझी, टीआर बालू और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर वामदलों की अग्रिम कतार के सीताराम येचुरी, डी राजा ने मौजूदगी दर्ज कराई। (पेज 4 पर)

शीर्ष 50 कंपनियों ने 59,600 करोड़ कर्ज चुकाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की शीर्ष 50 कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान 59,600 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाया है। कंपनियों ने अपनी बैलेंसशीट को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। इससे कंपनियों को बैंक से मिलने वाले कर्ज में सुधार होगा। पिछले कुछ समय के दौरान इन कंपनियों को घरेलू बैंकों से मिलने वाले कर्ज में गिरावट आई है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में कंपनियों ने 43,000 करोड़ रुपये का कर्ज घटाया था।

इस समय कंपनियां फंड जुटाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। इसके अलावा आइबीसी जैसे कानून के चलते भी कंपनियां अपना कर्ज कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस दौरान इन कंपनियों द्वारा विदेश से जुटाए जाने वाले फंड में बड़ा इजाफा हुआ है। इसी वर्ष अक्टूबर में यह 341 करोड़ डॉलर

- बैलेंसशीट सुधारने को चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनियों ने घटाया कर्ज
- बैंकों से नया कर्ज मिलने में दिक्कत देख अपनाया पिछला भुगतान करने का रास्ता

प्रतीकात्मक फोटो

(करीब 24 हजार करोड़ रुपये) रहा। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले दो गुना है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को जारी फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट में आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि आम ग्राहकों की तरफ से कर्ज की मांग बढ़ी है। लेकिन कंपनियों द्वारा कर्ज घटाने के चलते कॉरपोरेट ग्राहकों को दिए जाने वाले कर्ज पर दबाव पड़ा है।

आरबीआइ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक बैंकों द्वारा दिए कर्ज में महज 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों के कर्ज देने की विकास दर 13.3 प्रतिशत रही थी, जिसके चालू वित्त वर्ष में घटकर 6.5 से सात प्रतिशत तक रह जाने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा दिए कर्ज में 1.70 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2018-19 में यह बढ़ोतरी 5.4 लाख करोड़ रुपये की रही थी। लेकिन चालू वित्त वर्ष में छह दिसंबर तक यह बढ़ोतरी महज 80,000 करोड़ रुपये की रही है।

उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पाले ने बढ़ाई दिक्कतें

नई दिल्ली : शीतलहर के बाद पाला पड़ने से उत्तर भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के कारण 22 वर्षों के सबसे लंबे ठंड के दौर से गुजरे दिल्ली वालों को रविवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। कोहरे के कारण रेल और वायु यातायात प्रभावित है। कश्मीर के विक्षोभ व उत्तर-पश्चिम हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी, कोहरे व शीतलहर का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह औसत न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा उत्तर-पश्चिम से हवा की दिशा में तेजी से बदलाव शुरू होने से हुआ। (पेज-6)

कठघरे में कांग्रेस

तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने कहा था, एनपीआर से नहीं एनआरसी से तय होगी नागरिकता, एनपीआर और एनआरसी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही कांग्रेस सवालों के घेरे में

मनमोहन सरकार ने भी कही थी एनआरसी लाने की बात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़कर धरना प्रदर्शन और आंदोलन में जुटी कांग्रेस कठघरे में आ गई है। दरअसल सत्ता में रहते हुए वह खुद भी एनआरसी लाने की बात करती रही है। मनमोहन सरकार दो ने साफ कहा था कि वह एनआरसी लाने का इरादा रखती है और नागरिकता उसी के आधार पर तय होगी। संसद में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि एनपीआर में सभी दस उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों के निशान, फोटो आदि लिए जाएंगे और फिर कार्ड दिए जाएंगे लेकिन वह नागरिकता का सुबूत नहीं होगा। नागरिकता अधिकार उसी को मिलेगा जिसका नाम एनआरसी में होगा। यह एनपीआर के सबसेट के रूप में बाद में आएगा।

कांग्रेस ने शनिवार को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर संविधान की दुहाई देते हुए सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध किया था। विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि एनआरसी से मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में होगी। विपक्षी दलों की सरकार वाले कुछ राज्यों ने एनपीआर लागू से भी मना कर दिया है। लेकिन सत्ता में रहते हुए कांग्रेस का विचार अलग था। अगस्त 2011 में गुजरात के भाजपा सांसद सीआर पाटिल व अन्य तथा अगस्त 2012 में हरिन पाठक और योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में गृहमंत्रालय से लिखित सवाल के जरिए एनपीआर पर जवाब मांगा था। मजे की बात यह है कि दोनों ही सवालों में कहीं भी एनआरसी का जिक्र नहीं था। यह पूछा गया था कि सरकार कैसे तय करेगी कि एनपीआर के बाद जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र का गलत तरीके से नागरिकता के सुबूत के रूप में दुरुपयोग नहीं होगा।

- 2011-12 में संसद में बताया था, एनपीआर के बाद आएगा एनआरसी

मनमोहन सिंह फाइल फोटो

मनमोहन सरकार की तरफ से दिए गए दोनों सवालों के जवाब लगभग एक समान थे। इनमें बताया गया था कि पांच साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों की उंगलियों और दोनों आंखों की पुतलियों के निशान लिए जाएंगे। एनपीआर डाटा से आधार को जोड़ा जाएगा और ऐसे नामों के साथ तैयार लिस्ट को समाज, समुदाय, ग्राम सभा, वार्ड समिति के बीच जारी किया जाएगा ताकि कोई चाहे तो किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। संवेदनशील इलाकों में पड़ताल के लिए स्थानीय पुलिस की भी मदद ली जाएगी। यह भी साफ किया गया था कि एनपीआर कार्ड मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि हर कोई भारतीय नागरिक है। जितेंद्र सिंह ने साफ कहा था, 'निवास पहचान पत्र (रेजिटेंड आइडेंटिटी कार्ड) से नागरिकता नहीं मिलेगी। हर कार्ड पर साफ लिखा होगा कि यह कार्ड किसी को नागरिकता का अधिकार नहीं देता है। हर किसी की नागरिकता अलग से तय होगी जब एनआरसी की प्रक्रिया होगी। यह एनपीआर का ही अगला हिस्सा होगा।'

जाहिर है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी को मुस्लिम विरोधी और भाजपा का एजेंडा बताने वाली कांग्रेस को यह भी साफ करना होगा कि विपक्ष में रहते हुए उसके विचार क्यों बदल गए। ध्यान रहे कि शुरुआत के कुछ दिनों में कांग्रेस चुप थी लेकिन जब वाम और तृणमूल कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर लीड लिया तो कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। यह भी ध्यान रहे कि जब असम में एनआरसी लागू हुआ तो शुरुआती हिचक के बाद कांग्रेस ने प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसका समर्थन ही किया था।

कानून पर सियासत (विशेष) पेज>>5

डीडीसीए की वार्षिक आमसभा में झड़प के बाद जमकर हाथापाई

अभिषेक त्रिपाठी, नई दिल्ली

- मंच पर ही भिड़े सचिव तिहारा के समर्थक और कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश
- डीडीसीए ने न्यायमूर्ति दीपक वर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की वार्षिक आमसभा (एजीएम) रविवार को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में झड़प और हाथापाई के बीच हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगाई गई। एजीएम में झड़प होने की आशंका के चलते बैठक को कैमरे की निगरानी में कराया गया, लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। हालांकि, बैठक में डीडीसीए ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को नया लोकपाल नियुक्त किया। वर्मा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) बदर दुरेज अहमद की जगह लेंगे। न्यायमूर्ति बदर ने एक दिन पहले ही डीडीसीए सदस्यों को संयम बरतने के लिए कहा था।

थप्पड़ और घूंसे चले : एजीएम में जब मंच से डीडीसीए सचिव विनोद तिहारा प्रस्ताव पास कराने के लिए घोषणा कर रहे थे, तभी भाजपा विधायक और कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने विरोध दर्ज कराया। बात इतनी बढ़ गई कि मंच पर ही हाथापाई होने लगी। संयुक्त सचिव राजन मनचंदा उठकर आए तो उन्हें भी धक्का दे दिया गया। इस दौरान तिहारा, ओमप्रकाश को समझाते दिखे। मनचंदा गुट का आरोप है कि विरोधी गुट के मकसूद आलम ने बदतमीजी की। वहीं, तिहारा गुट का कहना है कि माहौल को विपक्ष ने जानबूझकर खराब किया। डीडीसीए के निदेशक सुधीर अग्रवाल ने कहा कि मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। बैठक के दौरान सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर को छीन लिया गया।

एजीएम में सभी प्रस्ताव पारित पेज>>14

800 सहायता केंद्र खोले जा चुके हैं भाजपा की ओर से। ये केंद्र 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकाना हक देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से कराए जा रहे पंजीकरण के लिए मदद करेंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 30 दिसंबर 2019

'भाजपा ने अनधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों से बोला झूठ'

दावा ▶ उपमुख्यमंत्री बोले, डीडीए की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि अनधिकृत कॉलोनियों और वहां बने मकान का नियमितीकरण नहीं हुआ

कहा, दिल्ली सरकार ने विकास के कार्य किए, केंद्र ने अपने हिस्से का काम केवल पोस्टर और बैनरों में किया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि भाजपा का अनधिकृत कॉलोनियों पर झूठ बेनकाब हो गया है। डीडीए की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि अनधिकृत कॉलोनियों और वहां बने मकान का नियमितीकरण नहीं हुआ है। भाजपा ने पूरी दिल्ली में इन कॉलोनियों को नियमित करने के भ्रामक होर्डिंग-बैनर लगाकर जनता को गुमराह किया है। यह दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ धोखा है। इसके लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।

सिसोदिया ने कहा कि 22 दिसंबर को रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, तब भी हमने कहा था कि वास्तव में यह धन्यवाद रैली नहीं, बल्कि धोखा रैली है। उन्होंने प्रेसवार्ता के दौरान डीडीए की वेबसाइट खोली। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि न तो यह अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण है और न ही मकानों का। लेकिन भाजपा ने पूरी दिल्ली में जगह-जगह बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बधाई दे रही है कि हमने कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया है।

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (दाएं)। जागरण

सिसोदिया ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में मुख्य रूप से दो कार्य होने थे। पहला कॉलोनियों को पक्का करने का और दूसरा कॉलोनियों में विकास का। कॉलोनियों को पक्का करने का काम केंद्र का था और कॉलोनियों में विकास करने का काम दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार ने सभी अनधिकृत कॉलोनियों में नालियां, सड़क, सीवर, पानी की पाइप लाइन बिछाने के साथ-साथ स्ट्रीट लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसे सभी विकास के कार्य किए हैं। परंतु केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का काम केवल पोस्टर और बैनरों में किया। सच्चाई यह है कि नियमितीकरण का केंद्र सरकार का कोई प्लान ही नहीं है।

सिसोदिया ने कहा कि मैं हरदीप पुरी जी का आभारी हूं कि उन्होंने चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के सामने भाजपा का झूठ बेनकाब कर दिया। सिसोदिया ने प्रेसवार्ता के दौरान अपने वर्तमान पते का नंबर वेबसाइट पर डाला, जो कि एक सरकारी कॉलोनी है। उसका भी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नंबर मनीष सिसोदिया के फोन पर आ गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह भाजपा का पूरा फर्जीवाड़ा है। इस वेबसाइट पर किसी नियमित कॉलोनी का पता भी लिख दिया जाए, तो भी आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है।

> डीडीए की वेबसाइट कहती है कि केंद्र की योजना न तो अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करेगी और न ही उनके घरों को। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि भाजपा ने लोगों से झूठ बोला और उसके बड़ी संख्या में होर्डिंग भी लगाए। धन्यवाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का, जिन्होंने डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से जनता के सामने सच रखा।
> **-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली**

अनधिकृत कॉलोनी के चक्रव्यूह में केजरीवाल को घेरेगी भाजपा

निहाल सिंह, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर 10 फीसद से भी कम काम करने का आरोप पत्र जारी करने के बाद भाजपा ने अपने चुनावी अभियान को आक्रामक रूप दे दिया है। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर व अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने इन कॉलोनियों के लोगों को जोड़ने और केंद्र सरकार के फैसले से अवगत कराने के लिए होर्डिंग अभियान चलाया है। इसके तहत 1731 कॉलोनियों में शनिवार रात से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं।

अहम बात यह है कि इन होर्डिंग पर प्रदेश भाजपा की ओर से किसी का नाम और फोटो नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के फोटो के साथ '1731 अनधिकृत कॉलोनियां अब सब नई अधिकृत कॉलोनियां' लिखा गया है।

दरअसल, भाजपा की कोशिश लोगों को यह एहसास दिलाने की है कि अब उनकी कॉलोनी से अनधिकृत कॉलोनी का ठप्पा हट गया है। रामलीला मैदान में पिछले सप्ताह हुई धन्यवाद रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। इसलिए इस होर्डिंग में उसी वाक्य को ही हथियार बनाया गया है।

भाजपा की मीडिया टीम के सह प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि कांग्रेस और आप सरकार ने इस मुद्दे को लटकाए रखा था। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया और मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले सौ दिन के भीतर दिल्ली के 40 लाख लोगों को मालिकाना हक का अधिकार दे दिया है। अब तक पांच हजार होर्डिंग लगाए जा चुके हैं। दिल्ली की करीब-करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियां या झुग्गी बस्तियां हैं। प्रमुख रूप से 22 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अनधिकृत कॉलोनियों के मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं।

भाजपा की ओर से राजीव नगर भलस्वा में लगाया गया होर्डिंग। जागरण

न्यूज गैलरी

एयरपोर्ट पर एक हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती जल्द

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए मुस्तैद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) एयरपोर्ट यूनिट से एक हजार अतिरिक्त जवान जल्द जुड़ने वाले हैं। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की स्वीकृति दे दी है। इनमें 30 महिला अधिकारी भी होंगी। आगामी महीने से चरणबद्ध तरीके से जवानों को तैनाती की जाएगी। इससे आइजीआइ एयरपोर्ट की फुलप्रूफ सुरक्षा में और बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में आइजीआइ एयरपोर्ट यूनिट में सीआइएसएफ के 4500 जवान तैनात हैं। इससे पहले वर्ष 2010 में यूनिट का विस्तार कर वहां 2500 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया था। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि अगले महीने जनवरी में 200 जवानों को तैनाती की जाएगी। (जासं)

127 किलो लाल चंदन की लकड़ी के साथ तीन दबोचे

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने लाल चंदन की 127 किलो लकड़ी के साथ तीन तस्करों को दबोचा है। सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर की रात आइजीआइ एयरपोर्ट पर तैनात सर्विलांस टीम के जवानों ने शक होने पर दो यात्रियों के बैग की जांच की तो कुछ नहीं मिला। लेकिन एक्स-रे मशीन से जब बैग गुजारे गए तो लाल चंदन की लकड़ी का पता चला। बैग में चंदन की लकड़ी पॉलीथिन में छिपाकर रखी गई थी। जांच में पता चला कि आरोपित दीपक सिंह और शेखर शर्मा भारतीय हैं और उनका एयर इंडिया के विमान से हांगकांग का टिकट बना हुआ था। पूछताछ में पता चला कि उनका एक साथी शिवाजी मेट्रो स्टेशन पर है। उसके बैग में भी लकड़ी रखी है। इसके बाद जितेन्द्र अहलावत नाम के इस तस्कर को भी जवानों ने टर्मिनल-3 के बोर्डिंग गेट क्षेत्र से दबोच लिया। (जासं)

निर्भया की याद में द्वारका में हुई श्रद्धांजलि सभा

नई दिल्ली : निर्भया की याद में द्वारका में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसमें निर्भया के माता-पिता व स्वजनों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने मांग की कि निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। इस दौरान लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इस दौरान लोगों ने उपनगरी में एक चौक का नाम निर्भया चौक रखने की मांग की। निर्भया की मां ने कहा कि उनकी बेटी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब उसके दोषियों को फंदे पर लटकाया जाएगा। (जासं)

रोड़ा अटकाने के बजाय आवेदक की मदद करे निगम : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

- बिल्डिंग-प्लान को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने की टिप्पणी
- ढाई साल बाद भी निगम ने नहीं दी स्कूल के बिल्डिंग प्लान को मंजूरी

फाइल फोटो

उत्तरी निगम द्वारा बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने में देरी करने पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि निगम के अधिकारियों को आवेदकों की मदद करनी चाहिए, लेकिन निगम का रवैया मदद करने के बजाया रोड़ा अटकाने वाला रहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकारी को 20 जनवरी तक आवेदन पर सुनवाई पूरी करके उसके बाद एक महीने में अंतरिम फैसला देने का आदेश दिया है। वहीं फैसले की रिपोर्ट अगले वर्ष 24 फरवरी को हाई कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया।

रामधारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट स्कूल की तरफ से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कामकाज के रवैये पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि किसी बिल्डिंग-प्लान की अनुमति मांगने वाले को प्राधिकारी से मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए नगर निगम में एक सहायता डेस्क हो सकती है, जो नागरिकों की मदद करे। पीठ ने कहा कि नगर निगम के इसी रवैये के कारण ही वर्ष 2017 से अब तक स्कूल के प्लान को मंजूरी नहीं मिल सकी। यही नहीं अपीलीय प्राधिकारी ने भी ट्रस्ट की अपील पर दो साल से सुनवाई नहीं की। इसके कारण ट्रस्ट नई इमारत बनाने में असमर्थ है। पीठ ने प्राधिकारी को 20 जनवरी तक सुनवाई पूरी कर एक महीने में अंतरिम फैसला देने का आदेश दिया है।

साथ ही उत्तरी निगम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता से कहा कि सहायता डेस्क बनाने के संबंध में विचार किया जाए ताकि निगम में बिल्डिंग-प्लान की अनुमति के संबंध में आने वाले आवेदन पर निर्धारित नियम के तहत तय समयसीमा के अंदर फैसला लिया जा सके।

यह है मामला : रामधारी जिंदल मेमोरियल ट्रस्ट का रोहिणी सेक्टर-28 के शाहबाद दौलतपुरा गांव में जिंदल इंटरनेशनल स्कूल है। इसमें मामूली फीस पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल का परिसर छोटा होने पर याचिकाकर्ता ने नई इमारत के बिल्डिंग-प्लान के संबंध में एनडीएमसी में बिल्डिंग-प्लान का आवेदन 14 मार्च 2017 में किया गया था। दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी का प्रमाण पत्र भी मई 2017 में दाखिल कर दिया गया। नगर निगम ने हालांकि मई 2017 में कई आपत्तियां लगाईं और याचिकाकर्ता ने इनका जवाब भी दिया। लेकिन निगम ने 27 जून 2017 को बिल्डिंग प्लान को खारिज कर दिया। उन्होंने फिर जनवरी 2018 को अपीलेट ट्रिब्यूनल में आवेदन किया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई और मामला अभी लंबित है।

व्यापारियों के साथ दिल्ली सरकार ने किया विश्वासघात : गोयल

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने रविवार को कहा कि व्यापारियों को जीएसटी जमा करने को लेकर हो रही समस्याओं पर केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। नए वित्त वर्ष में जीएसटी भरना बहुत ही आसान होगा। नए वित्त वर्ष से नया और सरल फॉर्म होगा, जिससे व्यापारी आसानी से अपना जीएसटी जमा करा सकेंगे। साथ ही अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में भी कटौती की जाएगी। सोमवार को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहे विशाल व्यापारी सम्मेलन के सिलसिले में अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में गोयल ने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने व्यापारियों के हित में बहुत कार्य किए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने व्यापारियों के साथ विश्वासघात किया है।

गोयल ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो व्यापारियों के हित में काम करने के लिए समर्पित है। विपक्ष ने कई बार तालकटोरा स्टेडियम से ही ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की कि व्यापारी भाजपा का साथ न दें, लेकिन ऐसा करने में वह असफल रहा। मोदी सरकार ने छोड़े-बड़े व्यापारियों के हित में कई अहम फैसले लिए जिससे व्यापारी खुश हैं। इसी के धन्यवाद के लिए व्यापारियों का यह विशाल सम्मेलन होगा।

बर्खास्त विधायकों वाली सीटों पर आप की स्थिति लगभग साफ

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जुट चुकी आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ता टिकट मांगने के लिए पहुंचने लगे हैं। मगर पार्टी द्वारा विधायकों को बर्खास्त किए जाने से खाली हुईं पांच सीटों के लिए टिकट मांगने वाले नहीं पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इन सीटों पर प्रत्याशी फाइनल हो चुकी है। गांधी नगर और सुल्तानपुर माजरा से अभी किसी के नाम की चर्चा नहीं है, लेकिन किसी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलने की संभावना है।

क्यों गई इन विधायकों की सदस्यता : पार्टी ने ही खुद अपने पांच विधायकों की सदस्यता रद करा दी है। ये विधायक बागी हो गए थे। इसके चलते पार्टी ने सख्त रुख अपनाया। इनमें अनिल बाजपेयी, कर्नल देवेंद्र सहरावत, कपिल मिश्रा, अलका लांबा व संदीप कुमार शामिल हैं।

दावेदार और सीट

दुर्गेश पाठक, करावल नगर : पार्टी नेतृत्व के करीबी लोगों में से एक। 2017 के पंजाब चुनाव में वहां के सह प्रभारी रह चुके हैं। इलाके के तमाम लोगों को पार्टी में शामिल करा चुके हैं।

बीएस जून, बिजवासन : पेशे से वकील हैं। पार्टी के मुकदमे लड़ते हैं। कई मामलों में पार्टी को जीत दिला चुके हैं। उन्होंने आप की उस समय भी मदद की है जब पार्टी को बगैर पैसे मुकदमे लड़ने वाले नहीं मिलते थे। कर्नल देवेंद्र सहरावत की सदस्यता समाप्त होने के बाद से बिजवासन क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के समय भाजपा छोड़ आप में शामिल हुए पूर्व निगम पार्षद कृष्ण सहरावत का भी इस सीट के लिए नाम चल चुका है।

प्रहलाद सिंह साहनी, चांदनी चौक : कांग्रेस की टिकट से लगातार चार बार चांदनी चौक सीट से विधायक रह चुके हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए हैं। चांदनी चौक सीट से दावेदारी कर रहे हैं। यह भी चर्चा है कि उन्हें या उनके बेटे को इस सीट से टिकट मिल सकता है।

45 करोड़ से बदलेगी लोकनायक के आपेरशन थियेटर की सूरत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थियेटर की सूरत बदलने वाली है। ओटी को सुविधा संपन्न बनाने के लिए जरूरी आधुनिक उपकरणों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपकरणों की खरीद पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि जनवरी में उपकरणों की खरीदारी कर ली जाएगी। इससे मरीजों की सर्जरी में सुविधा होगी।

लोकनायक अस्पताल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) से संबद्ध है। नवंबर में एमएएमसी के जनरल सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉ. पवनिंदर लाल ने एक आदेश जारी कर एक दिसंबर से ऑपरेशन थियेटर बंद करने की चेतावनी दी थी। उस आदेश पत्र में कहा गया था कि ऑपरेशन थियेटर में चिकित्सा उपकरणों की कमी है। रोशनी का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इस वजह से ऑपरेशन थियेटर में ऑपरेशन करना मरीजों के लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रबंधन को कई बार कहने के बावजूद जरूरी उपकरण नहीं खरीदे गए। यह मामला सामने आने के बाद स्वस्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का भी निर्देश दिया था।

जनरल सर्जरी के ऑपरेशन थियेटर ब्लॉक में चार टेबल हैं। डॉ. पवनिंदर लाल का कहना है कि कई बार स्टेटस रिपोर्ट भेजने के बावजूद अभी तक जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। फिर भी ऑपरेशन थियेटर में मरीजों की सर्जरी की सुविधा जारी रखी गई है। मौजूदा समय में तीन ऑपरेशन थियेटर चालू हालत में हैं, जबकि एक बंद पड़ा है। अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. किशोर सिंह ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर के लिए 45 करोड़ की लागत से उपकरणों व जरूरी सामान को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दो करोड़ रुपये के उपकरण खरीदे जा चुके हैं। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये के उपकरणों का वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है, जो जल्द उपलब्ध हो जाएंगे।

खुले में रात बिता रहे मरीजों के साथ आए तीमारदार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राजधानी में खून जमा देने वाली ठंड के बीच एम्स और सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए मरीज लेकर आने वाले तीमारदारों को खुले में रात बितानी पड़ रही है। हालांकि सरकार ने अस्पताल के पास रैन बसेरों की व्यवस्था की है। इसके बावजूद तीमारदारों की संख्या देखते हुए व्यवस्था नाकाफी नजर आती है। लोग बस स्टॉप और फुटपाथ पर अपना समय बिताने को मजबूर हो रहे हैं।

एम्स में इलाज के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मरीजों के तीमारदारों को बस स्टॉप और फुटपाथ पर अलाव के सहारे समय बिताना पड़ रहा है। बरेली से सिर में गांठ का इलाज कराने आए छोटू ने बताया कि रैन बसेरे में जगह नहीं थी। उसमें पहले से ही कई लोग थे इसलिए वह बाहर खुले में लेटे हैं। उन्होंने कई बार प्रयास किया लेकिन उन्हें रैन बसेरों में बिस्तर नहीं मिल पाया है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल के आसपास कई रैन बसेरों का निर्माण किया, लेकिन उन रैन बसेरों में स्थानीय बेघर, भिखारी और रिक्शा चालक बिस्तर ले लेते हैं। इसके कारण अस्पताल में मरीजों का इलाज कराने आए लोगों को बिस्तर की सुविधा नहीं मिल पाती है।

'सभी के इलाज पर 10 लाख खर्च कर रही सरकार'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सिरसपुर में 1164 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि महिलाओं का बस में मुफ्त सफर व 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना अगले पांच साल तक जारी रहेगी। अस्पतालों में सभी लोगों के लिए सभी तरह के टेस्ट, इलाज और ऑपरेशन मुफ्त कर दिए। अब किसी के इलाज में 10 लाख भी खर्च होगा तो उसके लिए दिल्ली सरकार है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने के लिए 1984 में जमीन ली गई थी। इस दौरान कई पार्टियों की सरकारें आकर चली गईं। सभी ने अस्पताल न बनाकर जनता को धोखा दिया। अब अस्तपाल के बनने का कार्य शुरू हुआ है। पहले चरण में 1164 बेड का अस्पताल बनेगा। इसके बाद 1500 बेड और बनाए जाएंगे। इस तरह यह 2700 बेड का अस्पताल होगा। इसके लिए सरकार ने 487 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। जनवरी में अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और यह 36 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी 650 बेड के अस्पताल पर काम शुरू होने जा रहा है। उसका भी पैसा स्वीकृत हो गया है।

सिरसपुर में नए अस्पताल के शिलान्यास समारोह पर आयोजित सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जागरण

- मुख्यमंत्री ने सिरसपुर में 1164 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की रखी आधारशिला

मुख्यमंत्री ने कहा कि बादली में जीवन पार्क, राणा सिंह पार्क, भगत सिंह पार्क और चंदन पार्क चार कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों की गलियां बन गई हैं। हमारी सरकार पिछले पांच साल से कच्ची कॉलोनियों में सड़कों के साथ सभी विकास कार्य करा रही है। जहां काम नहीं हुआ है। वहां भी अगले छह महीने में सभी कार्य करा दिए जाएंगे। हमने सभी 35 अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी कर दी।

उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए डीटीसी बस में सफर मुफ्त कर दिया। विपक्षी कह रहे हैं कि केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। हमने महिलाओं का सफर मुफ्त करने के लिए 140 करोड़ रुपये खर्च किए। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा है। हमने फिजूलखर्जी बचाकर लोगों को मुफ्त सुविधाएं दी हैं। हम 24 घंटे मुफ्त बिजली दे रहे हैं। पिछले पांच साल में हमने बहुत काम किए हैं। पिछले 70 सालों में विरोधी दलों की सरकारों ने कुछ नहीं किया।

अगले पांच साल में आपको 24 घंटे साफ पानी देने का सपना है। अभी कहीं पर एक घंटा, आधा घंटा पानी आता है। कई इलाकों में तीन-चार दिन में पानी आता है। अगले पांच साल के अंदर हर घर के अंदर नल से पानी देंगे। पांच साल में यमुना नदी को भी साफ करना है। अगले चुनाव से पहले हम यमुना को भी साफ कर देंगे।

परीक्षण

नाबी एमजी की पैदावार के अच्छे मिल रहे हैं संकेत, इसमें एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है अधिक

गाजियाबाद की माटी में बुढ़ापा दूर रखने वाला गेहूं हो रहा तैयार

हसीन शाह, गाजियाबाद

गाजियाबाद की मिट्टी में परीक्षण किए जा रहे काले गेहूं (नाबी एमजी) की पैदावार के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। विभाग के अफसरों ने कृषि वैज्ञानिक के साथ इसका जायजा लिया। एक माह पहले परीक्षण के लिए यह गेहूं भोजपुर ब्लॉक के तलहेटा गांव स्थित कृषि फार्म में लगाया गया था। इस गेहूं में एंटीऑक्सीडेंट और एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है। परीक्षण में सफलता मिलने पर किसानों को बीज भंडार में यह बीज मुहैया कराया जाएगा।

जिला कृषि अधिकारी डा. राकेश कुमार ने बताया कि गाजियाबाद की मिट्टी बलुई और दोमट है है। यहां की मिट्टी में परीक्षण के लिए मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (एनएबीआइ) से बीज का एक किलोग्राम नमूना मंगाया था। एक माह पहले बीज को कृषि फार्म हाउस में बोया गया था। शुक्रवार को कृषि वैज्ञानिक धर्मेंद्र कुमार ने पौधे की स्थिति जानने के लिए निरीक्षण किया है। इसके पौधे पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शुरुआत में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। समय और मौसम मे अनुसार इसकी लंबाई बढ़ रही है। यहां की मिट्टी और मौसम इसके अनुकूल है या नहीं, इसके उत्पादन और गेहूं की बाली आने पर इसकी सफलता का पता चल सका है।

धर्मेंद्र कुमार के अनुसार यह गेहूं बलुई मिट्टी में पैदा होता है। इसकी खेती में सामान्य गेहूं के मुकाबले 10-15 फीसद कम पैदावार होती है। प्रति हेक्टेयर करीब 40 से 45 क्विंटल की पैदावार होने का अनुमान है। इसके आटे का रंग मटमैला होगा। इसकी फसल को पकने में भी सामान्य गेहूं जितना ही समय लगेगा। मगर इसकी बुवाई अगेती की जाएगी। फसल के पकने में 30-35 डिग्री के बीच तापमान हो तो इसकी गुणवत्ता में और इजाफा होगा। इसकी रोटी भूरे रंग की होगी। सफलता मिलने पर पहली बार गाजियाबाद के किसानों के लिए बीज भंडारण में इसे रखवाया जाएगा।

काला गेहूं। सौजन्य : कृषि विभाग

> काले गेहूं से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अभी एक किलो गेहूं का नमूना बोया गया है। एक महीने बाद विभाग के अधिकारी कृषि वैज्ञानिक के साथ इसके पौधों को देखने पहुंचे। सामान्य गेहूं की तरह यह बढ़ रहा है। अभी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बाली आने और उत्पादन के बाद ही इसकी सफलता का पता चल सकेगा। सफलता मिलने पर किसानों को यह बीज मुहैया कराया जाएगा। इसकी फसल सामान्य गेहूं की तरह की तैयार होगी।
> **-डा. राकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी**

कई रोगों में फायदेमंद : जिला कृषि अधिकारी डा. राकेश कुमार ने बताया कि एनएबीआइ मोहाली द्वारा रिसर्च के बाद इस काले गेहूं की प्रजाति को विकसित किया गया। एनएबीआइ ने इस गेहूं को नाबी एमजी नाम दिया है। एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। इस प्रजाति को विकसित करने वाली एनएबीआइ की वैज्ञानिक मोनिका गर्ग के मुताबिक इस गेहूं से इंसान को कितना फायदा है, इस पर एनएबीआई ने कोई शोध नहीं किया है। हालांकि एंटीऑक्सीडेंट बुढ़ापा की गति को कम करने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, आंखों में होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के साथ कैंसर, डायबिटीज और दिल के रोग में फायदेमंद है, यह साबित हो चुका है।

इस गेहूं में एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंटट सामान्य गेहूं के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। काले गेहूं में आयरन भी ज्यादा पाया जाता है। अभी तक पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों किसान इसकी खेती कर रहे हैं।

क्या है काला गेहूं: जिला कृषि अधिकारी डा. राकेश कुमार ने बताया कि फलों, सब्जियों और अनाजों के रंग उनमें मौजूद प्लांट पिगमेंट या रंजक कणों की मात्रा पर निर्भर होते हैं। काले गेहूं में एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। एंथोसायनिन अधिकता से फलों, सब्जियों, अनाजों का रंग नीला, बैंगनी व काला हो जाता है। सामान्य गेहूं में एंथोसायनिन महज पांच पीपीएम होता है, जबकि काले गेहूं में यह 100 से 200 पीपीएम के आसपास होता है। इसमे जिंक की मात्रा भी अधिक होती है। काले गेहूं में सामान्य गेहूं की तुलना में 60 फीसद आयरन ज्यादा होता है। सामान्य गेहूं के मुकाबले इस गेहूं में एंटीऑक्सीडेंट भी कई गुना ज्यादा होता है।

राजधानी में गंभीर स्थिति में पहुंचा प्रदूषण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : शीतलहर से रविवार को हल्की राहत मिली तो राजधानी में प्रदूषण बढ़ गया। इस वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्थिति से गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। सोमवार को भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रहेगी। इसके मद्देनजर सफर-इंडिया ने रेड अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सैर सपाटा व बाहरी गतिविधियां बंद करने की सलाह दी है। साथ ही यह भी कहा है कि यदि सीने में जकड़न व सांस लेने में परेशानी हो तो हर तरह की गतिविधियां बंद कर दें। जरूरी हो तो डॉक्टर को भी दिखाएं।

एक जनवरी को बारिश होने पर प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को दिल्ली की एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 437 रहा। इस वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। हवा की गति कम होने व वातावरण में नमी के कारण प्रदूषण बढ़ा है।

95.1 फीसदी था एक से पांचवीं कक्षा के बीच सकल नामांकन दर (जीईआर), जबकि कक्षा नौ-दस में 79.3 फीसद और कक्षा 11-12 में 51 फीसद था। यू-डीआइएसई के 2016-17 के आंकड़ों से यह तथ्य सामने आए।

न्यूज गैलरी

'माईगोव' के यूजरों की संख्या एक करोड़ पार

नई दिल्ली : नागरिकों पर केंद्रित खास सरकारी वेबसाइट 'माईगोव' पर पंजीकृत यूजरों की संख्या एक करोड़ पार कर गई है। इससे प्रसन्न प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को कहा कि यह वेबसाइट आइडिया और अंतरदृष्टि का एक जीवंत केंद्र बन चुकी है। पीएमओ ने कहा कि पांच साल पहले 'माईगोव' को इसलिए विकसित किया गया था, ताकि इसके जरिये भारत की जनता अपनी आवाज और विचार सरकार के साथ साझा कर सके। पीएमओ ने ट्वीट किया, 'यह वेबसाइट आइडिया और अंतरदृष्टि का जीवंत केंद्र बन चुकी है। इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए बधाई।' इससे पहले दिन में 'माईगोव' ने ट्वीट के जरिये पंजीकृत यूजरों की संख्या के बारे में जानकारी दी। उसने ट्वीट किया, 'जैसा कि हम नए साल और नए दशक का स्वागत करने जा रहे हैं, हम इस प्लेटफार्म को बड़ा, सशक्त और बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं।' उसने इसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। (प्रेट्र)

सीपीडब्ल्यूडी राज्यों से करेगा परियोजनाओं की मांग

नई दिल्ली : केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे और अधिक आधारभूत ढांचा परियोजनाएं हासिल करने के लिए राज्य सरकारों व अन्य प्राधिकारों को पत्र लिखें। एक अधिकारी के अनुसार, 'महानिदेशक प्रभाकर सिंह के निर्देशानुसार सभी विशेष महानिदेशकों और अतिरिक्त महानिदेशकों को कहा गया है कि वे अपने राज्यों के संबंधित प्राधिकारों से संपर्क करके सीपीडब्ल्यूडी को और अधिक परियोजनाएं दिए जाने का आग्रह करें।' सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी है। उसे देशभर में सभी प्रकार की आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने का अनुभव है। लोक निर्माण विभाग केंद्र के साथ-साथ राज्य की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उसके पास अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़बंदी की भी जिम्मेदारी है। यही नहीं लोक निर्माण विभाग भारत के मित्र देशों में भी आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर काम करता है। (प्रेट्र)

पंजाब के मंत्री ने चैनल को सौ करोड़ का नोटिस भेजा

बटाला (गुरदासपुर) : पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वायरल वीडियो मामले में रविवार को एक टीवी चैनल के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। साथ ही, चैनल के प्रबंधक, रिपोर्टर व अन्य के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। रंधावा रविवार को एसएसपी उपिंदरजीत सिंह के कार्यालय पहुंचे और शिकायत पत्र और वायरल वीडियो की कॉपी सौंपा। इसमें कहा गया है कि एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर उक्त चैनल ने उन्हें बदनाम किया है। एसएसपी ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी। उन्होंने वीडियो में अपनी आवाज होने से इन्कार करते हुए कहा कि वीडियो दो साल पुरानी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर हाथ में लेकर मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। (जासं)

कोरेगांव भीमा में न करें राजनीतिक आयोजन

पुणे : महाराष्ट्र में पुणे प्रशासन ने सियासी दलों से कोरेगांव-भीमा में कोई आयोजन नहीं करने की अपील की है। ताकि क्षेत्र में तनाव न हो। रविवार को पुणे के कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा कि कोरेगांव भीमा युद्ध के वार्षिक समारोह की हमने सारी तैयारी कर ली है। हम राजनीतिक दलों और संगठनों से अपील करते हैं कि वह इस मौके पर कोई सियासी कार्यक्रम नहीं करें। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान खाने-पीने से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था रहेगी। समारोह की स्थल की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी। ध्यान रहे कि वर्ष 1818 में ऐतिहासिक युद्ध के वार्षिक समारोह के दौरान कुछ वर्ष पहले शांति और सामाजिक सौहार्द भंग हुआ था। (प्रेट्र)

सीएपीएफ की आवास सुविधा बढ़ेगी : शाह

गृहमंत्री बोले ▶ ताकि सीआरपीएफ जैसे बलों के जवान साल में 100 दिन परिवार के साथ रहें

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों और जवानों की आवास सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है और इसके लिए निधि आवंटित को लेकर आगामी बजट में कदम उठाए जाएंगे। शाह ने यहां सीआरपीएफ के मुख्यालय की नई इमारत के शिलान्यास के दौरान सीआरपीएफ को 'विश्व का सबसे बहादुर सशस्त्र बल' करार देते हुए कहा कि वह इन बलों के आवास समेत विभिन्न मामलों पर मौजूदा हालात बदलने के लिए 'दृढ़ संकल्प' हैं।

मंत्री ने कहा, 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए आवास संतुष्टि अनुपात बढ़ाना होगा। इसके लिए हमने निश्चय कर लिया है, अगले बजट में इसे लाया जाएगा।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस समय 13.75 प्रतिशत के साथ सीआरपीएफ की आवास संतुष्टि दर बहुत खराब है और करीब 10 लाख जवानों वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की यह दर करीब 25 प्रतिशत है। जिन जवानों के पास सरकारी आवास नहीं हैं, उन्हें दूरस्थ इलाकों में किराए के मकानों में रहना पड़ता है। इसके लिए उन्हें आवास किराया भत्ता (एचआरए) दिया जाता है।

नई दिल्ली में रविवार को सीआरपीएफ के महानिदेशक भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते गृहमंत्री अमित शाह। प्रेट्र

सीआरपीएफ की वीआइपी सुरक्षा इकाई के नए लोगो का अनावरण

अमित शाह ने सीआरपीएफ की वीआइपी सुरक्षा प्रकोष्ठ के लिए एक नए लोगो का अनावरण किया, जो गांधी परिवार के सदस्यों तथा कुछ केंद्रीय मंत्रियों समेत 59 ऐसे लोगों की सुरक्षा संभालता है। शाह ने कहा कि गरुड़, तलवार और कवच के साथ नया लोगो इस इकाई को अलग पहचान देगा। इसके तहत जिन 59 लोगों को सुरक्षा प्राप्त है, उनमें से 15 को 'जेड प्लस' श्रेणी की, 21 को 'जेड' श्रेणी की तथा बाकी 23 को अन्य विभिन्न श्रेणियों के तहत सुरक्षा मिली हुई है।

शाह ने कहा कि आवास को लेकर संतुष्टि का स्तर बढ़ने के बाद वह यह सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में सक्षम हो पाएंगे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आइटीबीपी, सीआइएसएफ और एसएसबी जैसे बलों का हर जवान साल के करीब 100 दिन अपने परिवार के साथ रहे। उन्होंने कहा, 'अगले साल अगस्त-सितंबर तक हमारे पास इन सभी बलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए एक निश्चित कार्य योजना होगी।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'संकल्प' लिया है कि यह सरकार ड्यूटी पर तैनात जवानों और अधिकारियों के परिवार की सुरक्षा करेगी और उनका तनाव भी कम करेगी। उन्होंने घोषणा कि सभी सीएपीएफ जवानों के परिवारों को 'ई-हेल्थ कार्ड' दिए जाएंगे ताकि नियमित आधार पर उनकी चिकित्सकीय जांच हो। शाह ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने इस 'हेल्थ कार्ड' योजना के लिए एम्स के साथ करार किया है।'

नए मुख्यालय की लागत होगी 277 करोड़ रुपये : शाह ने जवानों से कहा कि करीब 3.25 लाख जवानों वाले मजबूत बल को उसका एक अपना मुख्यालय देना बहुत जरूरी था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया मुख्यालय लोधी रोड पर 277 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2.23 एकड़ भूमि में बनेगा। सीपीडब्लूडी को 2022 तक नए भवन के निर्माण का काम सौंपा गया है। नया मुख्यालय 12 मंजिला होगा जिनमें सभागार, सम्मेलन कक्ष, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बैरक, कैंटीन, व्यायामशाला, अतिथि गृह, रसोई घर और भोजन कक्ष और 520 कारों और 15 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी।

परमाणु हमले की क्षमता वाली छह पनडुब्बियां बनाएगी नौसेना

नई दिल्ली, एजेंसियां : समुद्री क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना 24 पनडुब्बी बनाने की योजना बना रही है। इनमें 18 पारंपरिक और छह परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया है कि इस समय नौसेना के बेड़े में 15 पारंपरिक और दो परमाणु पनडुब्बियां हैं। इन दोनों परमाणु पनडुब्बियों के नाम आइएनएस अरिहंत और आइएनएस चक्र हैं। इनमें आइएनएस चक्र रूस से पट्टे पर लिया गया है।

परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही किए जाने की योजना है, जिसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी। नौसेना के मुताबिक, उसके पास ज्यादातर पनडुब्बियां 25 साल से ज्यादा पुरानी हैं। 13 पनडुब्बियों की उम्र तो 17 से 32 साल के बीच है। नौसेना ने स्थायी समिति को यह भी बताया कि पिछले 15 वर्षों में सिर्फ दो नई पारंपरिक पनडुब्बियां ही बेड़े में शामिल हुईं, जिनमें एक स्कॉर्पीन क्लास की आइएनएस कलवरी है, जबकि दूसरी आइएनएस खंडेरी।

- समुद्र में क्षमता बढ़ाने को 18 पारंपरिक पनडुब्बियां भी बनाने की है योजना
- इस समय नौसेना के बेड़े में हैं 15 पारंपरिक व दो परमाणु पनडुब्बियां

प्रतीकात्मक

उल्लेखनीय है कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों से भारत को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना अपने बुनियादी ढांचे में सुधार की योजना बना रही है। इसके तहत नए जहाजों की खरीद भी शामिल है।

नियम में बदलाव : सीडीएस के लिए अधिकतम उम्र अब 65 साल हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की नियुक्ति संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए उसकी सेवा की अधिकतम आयु बढ़ाकर 65 साल कर दी है। सेवानिवृत्ति की उम्रसीमा बढ़ाने के लिए सेना, नौसेना व वायुसेना के सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल, सीडीएस की नियुक्ति तीन साल या 62 साल की अधिकतम उम्र के लिए मान्य है।

- रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के सेवा नियमों में किया संशोधन
- फिलहाल, सीडीएस की नियुक्ति 62 साल की अधिकतम उम्र तक के लिए मान्य है

रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस : सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गत मंगलवार को चार स्टार जनरल को सीडीएस नियुक्त किए जाने की हरी झंडी दे दी है। वह तीनों सेवाओं के बीच तालमेल बैठाने और रणनीति तय करने का काम करेगा। तीनों सेनाओं के मामले में उसकी भूमिका रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार की होगी। सीडीएस के रूप में सेवानिवृत्त होने वाला सैन्य अधिकारी अन्य किसी सरकारी पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। वह सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के बाद पांच साल तक निजी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं नहीं दे सकेगा।

कमानों के पुनर्गठन व तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियानों की जिम्मेदारी : सीडीएस पर सैन्य कमानों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी होगी, ताकि सेनाओं के संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। सेनाओं के संयुक्त अभियान व संयुक्त कमानों की स्थापना भी उसके प्रमुख कार्यों में शामिल होगा। अधिकारी बताते हैं कि अभियान, रसद, परिवहन, प्रशिक्षण, सहयोगी सेवाएं, संचार एवं तीनों सेनाओं के कार्य संवर्धन की जिम्मेदारी भी सीडीएस की होगी।

एनसीए का भी सैन्य सलाहकार होगा सीडीएस : सीडीएस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (एनसीए) का भी सैन्य सलाहकार होगा। साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित तीनों सेनाओं की एजेंसियां, संगठन और कमान भी उसके अधीन काम करेंगे।

सीओएससी का चेयरमैन भी होगा : सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) का भी चेयरमैन होगा। इससे पहले तीनों सेनाओं का सबसे वरिष्ठ अधिकारी सीओएससी का चेयरमैन होता था। फिलहाल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इसके चेयरमैन हैं, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह सीओएससी के चेयरमैन का पदभार नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह सौंपने वाले थे, लेकिन शुक्रवार को इसे स्थगित कर दिया गया। माना जा रहा है कि सरकार ने सीडीएस की नियुक्त के संदर्भ में ऐसा निर्देश दिया है।

मंगलवार को हो सकती है देश के पहले सीडीएस की घोषणा : सूत्र बताते हैं कि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस हो सकते हैं। विचाराधीन नामों में रावत सबसे सशक्त दावेदार बताए जाते हैं। हालांकि, अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं है। देश के पहले सीडीएस की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को हो सकती है।

मप्र में पीडब्ल्यूडी की जमीन बेचेगी कमलनाथ सरकार

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार अब लोक निर्माण विभाग के कब्जे वाली बेशकीमती जमीनें वाणिज्यिक उपयोग के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ अफसरों की तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति विभाग की परिसंपत्तियों के निराकरण के लिए शासन द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर शासन को सौंपेगी।

मुख्यमंत्री कमलनाथ निर्माण विभागों को अपनी आमदनी के स्रोत विकसित करने को कह चुके हैं। इसके बाद लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने विभिन्न जिलों में मौजूद अपने रेस्ट हाउस की खाली जमीनों को लीज पर देने का प्रस्ताव बनाया है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर काम चल रहा है, इसके अलावा विभाग पर्यटन निगम को भी अपने कुछ रेस्ट हाउस सौंपने जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल, जबलपुर व इंदौर जैसे बड़े शहरों की व्यावसायिक जमीनों को भी चिह्नित किया गया है। प्रदेश के तीनों बड़े शहरों में ये जमीनें व्यावसायिक उपयोग की हैं और इनकी कीमत अरबों रुपये में आंकी जा रही है। लोक निर्माण विभाग इन जमीनों का ई-ऑक्शन करेगा। इसके बाद जमीन निजी संस्थाओं को पीपीपी मोड पर अनुबंध के तहत सौंपी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी की गाइडलाइन के हिसाब से तीनों शहरों की इन जमीनों की कीमत करीब 500 करोड़ आंकी जा रही है। जबलपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर सरकारी आवास और सब डिवीजन कार्यालय मौजूद हैं। ये आवास और दफ्तर जर्जर हो गए हैं इसलिए सरकार इन्हें निजी हाथों में सौंपने का निर्णय कर चुकी है।

- वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति गठित

विभाग की आय बढ़ाने के प्रयास

लोनिवि के प्रमुख अभियंता आरके मेहरा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि विभाग की आय बढ़ाने के लिए अनुपयोगी जमीनों को निजी हाथों में देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विस्तृत रूप से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जमीनों को पीपीपी मोड पर दिए जाने की तैयारी है।

2010 में पांच साल का अनुबंध किया गया था

प्रथम पृष्ठ से आगे

मंत्रालय ने कहा कि ईसीएचएस के स्मार्ट कार्ड के स्कोर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एसआइटीएल) को 2010 में पांच साल का अनुबंध दिया गया था। 2015 में अनुबंध खत्म होने पर कंपनी ने डेटाबेस, स्रोत कोड और कंप्यूटर अनुप्रयोग वापस नहीं किए। दावा किया कि एसआइटीएल ने निजी डाटा वापस नहीं किया और न ही पुष्टि की कि यह उनके पास नहीं है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सोर्स कोड भी वापस नहीं किया। एक कानूनी नोटिस के जवाब में कंपनी ने आरोपों का खंडन किया। कई स्तरों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान के बाद बत्रा ने रक्षा मंत्रालय से कंपनी के खिलाफ की कार्रवाई की जानकारी मांगी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में अवर सचिव एके कर्ण ने उनसे कहा, 'आपके ईमेल के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि मैसर्स स्कोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड व उसके निदेशकों तथा कर्मचारियों के खिलाफ केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस ने 19 दिसंबर, 2019 को पुलिस थाना, सदर बाजार, दिल्ली कैंट में प्राथमिकी दर्ज कराई है।' दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी जिले के डीसीपी देवेंद्र आर्य ने कहा कि एक्स सर्विसमेन के डाटा चोरी का कोई मामला हमारी जानकारी में नहीं है।

पाक के पूर्व एयर चीफ की बेगम की संपत्ति को सरकार लेगी कब्जे में

मुस्लेमीन, रामपुर

पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निशा की करोड़ों की संपत्ति रामपुर में है। अब यह उन्हें मिल नहीं पाएगी। दरअसल, अब्दुल रहीम नवाब खानदान के दामाद थे। मेहरुन्निशा नवाब रजा अली खान की बेटी हैं लेकिन, शादी के बाद पाकिस्तान चली गईं। अब अमेरिका में रहती हैं। ऐसे में उनकी संपत्ति को भारत सरकार शत्रु संपत्ति घोषित करेगी।

नवाब खानदान के पास बेशुमार संपत्ति है लेकिन, इसके बंटवारे को लेकर पिछले 45 साल से खानदान में ही मुकदमेबाजी चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 86 वर्षीय मेहरुन्निशा भी हिस्सेदार हैं। उनके पति का भी इंतकाल हो चुका है। नवाब खानदान की संपत्ति में ऐसे कई रिश्तेदार हैं जो विदेश में रह रहे हैं। इनकी संपत्ति भी भारत सरकार के कब्जे में आएगी लेकिन, यह सब संपत्ति के बंटवारे के बाद ही हो सकेगा।

शत्रु संपत्ति में दर्ज होगी : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि भारत-पाक बंटवारे के समय जो लोग हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे देश में चले गए या जो लोग दूसरे देश के नागरिक हैं, उनका कोई वारिस भी यहां नहीं है तो उसकी संपत्ति कस्टोडियन मानी जाएगी। नवाब खानदान के ऐसे लोगों की भी संपत्ति कस्टोडियन में दर्ज होगी।

- रामपुर में है अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरुन्निशा की करोड़ों की संपत्ति
- 45 साल से खानदान में ही चल रही थी मुकदमेबाजी

शरीयत के हिसाब से बंटेगी संपत्ति : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को शरीयत के हिसाब से बंटवारा कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया है। इसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि किसके हिस्से में कौन सी संपत्ति आई है। बंटवारे के लिए जिला जज ने दो अधिवक्ताओं को कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर बने अधिवक्ता कैलाश अग्रवाल के मुताबिक नवाब खानदान की खासबाग, लक्खी बाग, बेनजीर बाग, नवाब रेलवे स्टेशन सहित अरबों रुपये की संपत्ति है। इनमें 16 हिस्सेदार हैं।

बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल के साथ नए विवाद को दी हवा

स्वायत्त शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती सरकार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने रविवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ नए सिरे से विवाद को हवा दे दी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों पर चर्चा के लिए राज्यपाल से मुलाकात के बजाय पत्र लिख कर जवाब दिया और यहां तक कि पत्र को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर भी साझा किया है। अपने पत्र में पार्थ ने कहा है कि चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान है, इसलिए राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ट्विटर पर जवाब साझा करने को लेकर पार्थ की दलील है कि चूंकि राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री के जवाबी पत्र को ट्विटर पर साझा किया, इसलिए उन्होंने भी ऐसा करना मुनासिब समझा है। राज्यपाल ने भी पार्थ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि यह समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का नहीं है। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आशान्वित हूं कि मुख्यमंत्री के कहे अनुसार शिक्षा मंत्री उक्त मुद्दे पर बैठक कर चर्चा करेंगे।

25 दिसंबर को राज्यपाल ने राजकीय विश्वविद्यालयों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 15 दिनों के भीतर मुलाकात को लेकर पत्र लिखा था जिसका जवाब सीएम की ओर से 24 घंटे के अंदर 26 दिसंबर को राजभवन को भेजा गया। 24 घंटे के अंदर प्राप्त सीएम की जवाबी चिट्ठी को शनिवार को राज्यपाल ने ट्विटर पर साझा किया और प्रसन्नता जाहिर की। सीएम ने अपने जवाबी पत्र में कहा था कि शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी राज्यपाल से समयानुसार वार्ता करेंगे। इससे पहले कई बार अन्य मुद्दे पर राज्यपाल सीएम से मुलाकात की इच्छा को लेकर पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिल सका है।

पार्थ चटर्जी फाइल फोटो

जगदीप धनखड़ फाइल फोटो

- मंत्री ने मुलाकात के बजाय धनखड़ को ट्विटर पर दिया जवाब
- राज्यपाल ने किया रिट्वीट, यह समय ईंट का जवाब पत्थर से देने का नहीं

क्या है शिक्षा मंत्री का जवाब : शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल को भेजे जवाबी पत्र में कहा है, जैसा कि आपने (धनखड़) ने मुख्यमंत्री के जवाबी पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, इसलिए मैं भी आपको इसी तरह से जानकारी दे रहा हूं। कहा- विश्वविद्यालयों से संबंधित औपचारिक कार्यक्रमों की तारीखें कुलपति द्वारा परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती है, विश्वविद्यालय एक स्वायत्त निकाय हैं और राज्य सरकार वर्तमान कानूनी प्रावधान के मुताबिक इसमें दखल नहीं दे सकती।

जेयू विवाद के बाद कहा था बैठक के लिए

24 दिसंबर को जब राज्यपाल जादवपुर विश्वविद्यालय (जेयू) के दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे थे तो कुछ छात्रों ने उनका रास्ता रोक विरोध किया था और गो बैक के नारे लगाए थे। इसे लेकर उन्होंने 15 दिन के भीतर सीएम के साथ बैठक करने का आग्रह किया था। वहीं, जेयू को लेकर पार्थ चटर्जी ने अपने पत्र में कहा है कि उस दौरान छात्र नागरिकता कानून, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। चटर्जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्यपाल जो कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है, के साथ बातचीत को तैयार हैं बशर्ते उनका दृष्टिकोण सौहार्दपूर्ण हो क्योंकि यह शिक्षा विभाग के सर्वोत्तम हित में है।

इंतजार

देश विधि आयोग से जिस समान नागरिक संहिता के प्रारूप की उम्मीद लगाए बैठा था, वह अधर में ही लटका रहा

विधि आयोग में अध्यक्ष का पद 14 माह से खाली

माला दीक्षित, नई दिल्ली

देश कानून से चलता है और कानून विधायिका बनाती है। नए कानून की जरूरत और मौजूदा कानूनों की प्रासंगिकता की परख सतत प्रक्रिया है और यह काम करता है- विधि आयोग। विधि आयोग ऐसा करते वक्त विषय और परिस्थितियों का गहनता से अध्ययन करता है। वह नए कानून पर जनता और बुद्धिजीवियों से परामर्श भी करता है, ताकि प्रस्तावित कानून न सिर्फ संवैधानिक तौर पर चाक-चौबंद हो, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी खरा उतरे। इतनी अहम संस्था का अध्यक्ष पद पिछले 14 महीने से खाली है। 31 अगस्त 2018 को जस्टिस बीएस चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से आयोग का नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त हुआ है।

पिछला विधि आयोग समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) पर विचार करने के कारण काफी चर्चा में रहा। कानून मंत्रालय ने 17 जून 2016 को विधि आयोग को इस पर विचार करने का प्रस्ताव भेजा था। दो साल तक मंथन के बाद विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की सलाह देने की बजाय विभिन्न पारिवारिक विधियों (फैमिली लॉ) में संशोधन करने के सुझाव दिए और उस पर परामर्श पत्र जारी कर लोगों की राय भी मांगी। विधि आयोग की ओर से यह रिपोर्ट जस्टिस चौहान के कार्यकाल के अंतिम दिन 31 अगस्त 2018 को जारी हुई। देश विधि आयोग से जिस समान नागरिक संहिता के प्रारूप की उम्मीद लगाए बैठा था, वह अधर में ही लटका रहा।

ऐसा नहीं कि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर गहनता से काम नहीं किया। आयोग ने इस बारे में दो बार परामर्श पत्र जारी किए। आम लोगों और बुद्धिजीवियों की राय मांगी। सभी पहलुओं पर विचार के बाद आयोग ने पाया कि देश की विभिन्न संस्कृतियों को बनाए रखने के लिए पहले कदम के तहत विभिन्न पारिवारिक विधियों में संशोधन कर महिला और पुरुष को बराबरी पर लाना होगा। इसके लिए आयोग ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी आदि समुदायों के पर्सनल लॉ का अध्ययन किया और उसमें समुचित बदलाव करके संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबरी लाने की सलाह दी थी। जब आयोग के समक्ष समान नागरिक संहिता का मुद्दा विचाराधीन था, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों में प्रचलित तत्काल तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने का फैसला आ गया था। इसके बाद आयोग ने समान नागरिक संहिता पर विचार करने वाले प्रश्नों की सूची से तीन तलाक का सवाल हटा दिया था।

- 31 अगस्त 2018 को जस्टिस बीएस चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद नहीं हुई किसी अन्य की नियुक्ति
- कानून मंत्रालय ने 17 जून 2016 को विधि आयोग को इस पर विचार करने का प्रस्ताव भेजा था

प्रतीकात्मक

वनवासी कल्याण के लिए केंद्र सरकार संकल्पित : अर्जुन मुंडा

जासं, कानपुर : केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वनवासी कल्याण के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है। वनवासी कल्याण आश्रम जिस तरह के प्रयास कर रहा है, उसमें भी सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में 22वीं वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संस्कृति, अध्यात्म व अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। इस आयोजन में इसी रूप का दर्शन हो रहा है। भारत में 40 फीसद भूभाग पर 700 जनजातियों के साढ़े दस करोड़ लोग रहते हैं। केंद्र में मोदी सरकार ने 461 एकलव्य विद्यालय खोलकर इन बच्चों के शैक्षिक व व्यक्तित्व विकास की राह प्रशस्त की है। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि देश के दुश्मन जनजातियों को सामने रखकर धर्म परिवर्तन का खेल खेलते थे।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था शिबू सोरेन ने कद्दावर नेता बिनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर। तब महतो झामुओ के अध्यक्ष बने और सोरेन को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 30 दिसंबर 2019

झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन

संभाली कुर्सी ▶ रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

मंत्रिमंडल में कांग्रेस के आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और राजद के सत्यानंद को मिली जगह

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हेमंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड विधानसभा का सत्र छह से आठ जनवरी तक होगा। 6 जनवरी को सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 7 जनवरी को विधानसभा में स्पीकर का चयन किया जाएगा।

खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार : मुख्यमंत्री की ओर से राजभवन को तीन मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए सूची भेजी गई थी। समझा जा रहा है कि खरमास के बाद हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें सभी नामों पर फैसला होगा। फिलहाल कांग्रेस से पांच, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से छह और राजद से एक को मंत्रिमंडल में शामिल करने के फॉर्मूले पर महागठबंधन में सहमति बनी है। झामुमो विधानसभा अध्यक्ष का पद भी अपने पास

रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हेमंत सोरेन। जागरण

रखेगा। झामुमो के वरिष्ठ नेता सह विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर होंगे।

माता-पिता का लिया आशीर्वाद : शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य मंच पर सबसे पहले पहुंचने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता सह झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन शामिल थे। उनकी मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद थीं। हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के पूर्व माता-पिता का पांव छूकर आशीर्वाद लिया।

रघुवर दास भी रहे मौजूद : पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूदगी दर्ज कराई। वह मंच के बाईं तरफ अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। उनके समीप कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और डीएमके नेता टीआर बालू बैठे थे। झामुमो के वरिष्ठ नेता सह विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर होंगे। वहीं, सात जनवरी को विधानसभा में स्पीकर का चयन किया जाएगा।

शपथग्रहण के बहाने एकजुट हुए भाजपा विरोधी

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपा विरोधी दलों के मेगा शो के तौर पर देखा जा रहा है। एक मंच पर इससे पहले इतने ज्यादा नेताओं का जुटान कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था। इस समारोह में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के कद्दावर नेता एमके स्टालिन, कनिमोझी, टीआर बालू और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर वामदलों की अग्रिम कतार के सीताराम येचुरी, डी राजा ने मौजूदगी दर्ज कराई। बिहार से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और दिल्ली से आए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की उपस्थिति यह संकेत दे गई कि आने वाले दिनों में भाजपा विरोधी दलों की व्यापक एकजुटता सामने आ सकती है। दरअसल, नागरिकता संशोधन बिल, कश्मीर में अनुच्छेद-370 पर निर्णय, एनआरसी के खिलाफ कई राज्यों में माहौल गर्म है। इसे तूल देने में भाजपा विरोधी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।

दिख सकता है विस चुनावों पर असर : विरोधी दलों की एकजुटता आगामी विधानसभा चुनावों पर असर दिखा सकती है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सिर पर है। बिहार और बंगाल में भी चुनाव होंगे। ऐसे में झारखंड की जीत में गठबंधन मंत्र को आदर्श मानते हुए यहां भी प्रयोग दोहराया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा को हराना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

नहीं आईं प्रियंका, पवार, मायावती, उद्धव ठाकरे भी नदारद : कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आने को लेकर सस्पेंस बना रहा। उनका नाम अतिथियों की सूची में ऊपर में था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में व्यस्तता के कारण वह शामिल नहीं हो पाईं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेलुगु देसम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और बसपा अध्यक्ष मायावती का आगमन भी निर्धारित था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन भी अंतिम वक्त में टल गया।

शपथग्रहण समारोह में बाएं से कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, राजद नेता तेजस्वी यादव, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एएनआइ

जब मुश्किल में थे शिबू, हेमंत ने थामी थी झामुमो की कमान

प्रदीप सिंह, रांची

- 2005 में शिबू को देना पड़ा था इस्तीफा, हत्या के पुराने मामले में हो गई थी जेल
- शिबू सोरेन की समृद्ध विरासत को दिया विस्तार, इस साल अच्छा रहा प्रदर्शन

2005 में अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में अगर हेमंत सोरेन हौसला हार जाते तो आज सत्ता के शीर्ष पर कतई नहीं पहुंचते। मैकेनिकल इंजीनियर बनने की चाहत लिए हेमंत सोरेन को उस वक्त प्रतिकूल स्थिति में राजनीति में आना पड़ा, जब पिता शिबू सोरेन मुश्किल में आए। उस वक्त शिबू सोरेन केंद्र की यूपीए सरकार में कोयला मंत्री थे और हत्या के एक पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। हाथ से मंत्री की कुर्सी भी फिसल गई। बाद में वह बरी हो गए। पिता को मुश्किल में फंसा देख हेमंत सोरेन अपने अग्रज दुर्गा सोरेन का साथ देने और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कूद पड़े। शुरुआती अनुभव भी कड़वा रहा। दुमका विस सीट से पहला चुनाव हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अग्रिम संगठन छात्र मोर्चा की कमान उनके हाथ में आई और वह राजनीति की डगर पर धीमे-धीमे आगे सरकने लगे। 2009 में दुमका से विधायक चुने। विपरीत विचारधारा के बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिबू सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी जो महज चार माह चली। छह महीने बाद एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद में दोनों दलों को सफलता मिली। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने तो हेमंत सोरेन को उनकी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली। बाद में हेमंत ने समर्थन वापस ले लिया।

इसके बाद उन्होंने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाबी पाई। पहली बार वह 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 23 दिसंबर 2014 तक रहे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर कब्जा किया था।

हेमंत सोरेन को परंपरागत मानी जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा को हाईटेक बनाने का श्रेय जाता है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधार क्षेत्र को विस्तार देने में कामयाबी पाई। उन्होंने महसूस किया कि अगर सत्ता हासिल करनी है, भाजपा को परास्त करना है तो शहरी इलाकों में प्रभाव बनाना पड़ेगा। इस मुहिम में हालिया विधानसभा चुनाव में उन्होंने कामयाबी पाई। रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी।

भाजपा को घेरा : शिबू सोरेन ने कद्दावर नेता बिनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। बिनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। इस संगठन को मशहूर ट्रेड यूनियन नेता एके राय का भी साथ मिला। निर्मल महतो, टेकलाल महतो आदि प्रमुख नेताओं ने इसे और सफलता प्रदान किया। 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा में जन्मे हेमंत सोरेन ने 2014 के विस चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका धारदार तरीके से निभाई।

न्यूज गैलरी

मुलायम सिंह को मुंबई के अस्पताल से मिली छुट्टी

मुंबई: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मुंबई के एक अस्पताल में उपचार के बाद रविवार को छुट्टी दे दी गई। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यादव को तीन दिनों पहले यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के रक्षा मंत्री रह चुके सपा नेता के करीबी सहायक ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर ऐसा किया गया था। उन्होंने बताया कि उपचार पूरा होने के बाद रविवार को सपा संस्थापक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। इसके बाद वह लखनऊ लौट गए। (प्रेट्र)

देश के नक्शे पर छाई भाजपा के टुकड़े-टुकड़े हो गए : भूपेश

रायपुर: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को शपथ ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बघेल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के बीच में बैठे। कार्यक्रम के दौरान भूपेश ने ममता से एनआरसी सहित अन्य राजनीतिक हालात पर चर्चा की। रविवार को रांची रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि भाजपा जो कभी देश के नक्शे के छाई हुई थी, वो अब टुकड़े-टुकड़े हो गई है। कई राज्यों में जनता उन्हें नकार रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वहां की भाजपा सरकार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर बघेल ने कहा कि यह नया अनुभव है। इसमें सब लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देश विदेश से कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां साहित्यकार, लेखक और वरिष्ठ जानकार लोग भी आए हैं। ऐसा यह बहुत कम होता है कि एक ही मंच पर सारे आदिवासी एक साथ नजर आए। यह सफल कार्यक्रम रहा है। (नईदुनिया)

रघुवर दास के भ्रष्टाचार पर किताब लिखेंगे सरयू राय

जागरण संवाददाता, वाराणसी

झारखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा से विद्रोह कर जमशेदपुर (पूर्वी) विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय स्थायी सरकार के पक्षधर हैं। वह अस्थिर सरकार नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार को उसके गुण-दोष के आधार पर समर्थन देंगे। शनिवार को दर्शन-पूजन के क्रम में वाराणसी पहुंचे सरयू राय ने भेलूपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में जागरण से बातचीत में कहा कि वे जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के भ्रष्टाचार पर किताब लिखेंगे।

उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी पार्टी से जुड़ने या नया दल बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। वह महात्मा गांधी व डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों का प्रचार-प्रसार करेंगे। झारखंड की कमान अब तीन युवा नेताओं अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन व सुदेश महतो के हाथ में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा व क्षमतावान हैं। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में झारखंड को नई दिशा

सरयू राय। फाइल

मिलेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उन्होंने झारखंड में सीएए लागू करने के प्रश्न पर कहा कि इसे राष्ट्रहित में देखा जाना चाहिए। इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जो सुलझ जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव तो जनता ने लड़ा है। इसी का परिणाम है कि राज्य का मुख्यमंत्री निर्दलीय प्रत्याशी से हार गया। यह लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। झारखंड के पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं निर्दलीय हूं और अपनी सीमा जनता हूं, लेकिन तटस्थ नहीं रह सकता।

'खराब नेता पाना महाराष्ट्र की गलती नहीं, उसके साथ बने रहना गलती है'

- पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता का सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना
- पहले कहा था, नाम के आगे ठाकरे जोड़ देने से कोई ठाकरे नहीं हो जाता

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। अमृता ने कहा है कि खराब नेता का होना महाराष्ट्र की गलती नहीं है, लेकिन उसके साथ बने रहना गलती है।

अमृता फड़नवीस ने लगभग एक हफ्ते पहले भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर देवेंद्र फड़नवीस के ट्वीट पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा था कि अपने नाम के आगे ठाकरे जोड़ लेने से ही कोई ठाकरे नहीं हो जाता। इसको लेकर शिवसेना के साथ उनका सोशल मीडिया पर वाकयुद्ध भी चला था। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी माफी मांगने की मांग को लेकर की थी। फड़नवीस ने कहा था कि राहुल गांधी कभी सावरकर हो भी नहीं सकते।

अमृता फड़नवीस। फाइल

अमृता फड़नवीस ने शनिवार को ट्वीट किया, 'खराब नेता पाना महाराष्ट्र की गलती नहीं, लेकिन उसके साथ बने रहना गलती है, जागो महाराष्ट्र।' उन्होंने यह टिप्पणी शिवसेना के शासन वाले ठाणे नगर निगम द्वारा अपना वेतन खाता एक्सिस बैंक से हटाकर किसी सरकारी बैंक में करने के फैसले के एक दिन बाद की है। अमृता फड़नवीस एक्सिस बैंक में वरिष्ठ पद पर हैं।

अमृता ने कहा कि एक्सिस बैंक में ठाणे नगर निगम का खाता कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान खुला था, तब देवेंद्र फड़नवीस के साथ उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी कहा निजी क्षेत्र के बैंक भी भारत के ही बैंक हैं और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करते हैं।

अमृता ने कहा कि बैंक खाता हटाकर राज्य सरकार उन्हें और उनके पति को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वे चुप नहीं रहने वाले। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला भी बताया।

बता दें कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ठाकरे सरकार महाराष्ट्र पुलिस के वेतन खाते को भी एक्सिस बैंक से हटाने की तैयारी में है। इस खाते में सालाना 11,000 करोड़ से ज्यादे का लेन-देन होता है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

सोशल मीडिया पर छायी प्रियंका की सुरक्षा में तैनात महिला सीओ

जागरण संवाददाता, लखनऊ : कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की सुरक्षा में तैनात जिस महिला पुलिस अधिकारी पर शनिवार को कई आरोप लगाए गए, उनकी कर्तव्य परायणता रविवार को सोशल मीडिया पर छायी रही। अपने चचेरे भाई की मौत के बावजूद प्रियंका वाड्रा की अभेद्य सुरक्षा करने वाली सीओ डॉ. अर्चना सिंह खूब ट्रेंड हुईं। उन पर डाली गई पोस्ट को ट्विटर पर रविवार देर शाम तक 53 हजार से अधिक लाइक मिले।

मॉडर्न कंट्रोल रूम की सीओ डॉ. अर्चना शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की सुरक्षा में तैनात थीं। इसी दौरान दिल्ली में अस्पताल में भर्ती चचेरे भाई के निधन का दुखद समाचार उनको मिला। इस पर भी डॉ. अर्चना ने अपनी ड्यूटी पूरी की। प्रियंका ने डॉ. अर्चना सिंह पर गला दबाने और धक्का मारकर गिराने का आरोप लगाया था। देर शाम डॉ. अर्चना ने अपनी रिपोर्ट भी एसपी प्रोटोकॉल को सौंप दी। दैनिक जागरण में डॉ. अर्चना के फर्ज को लेकर 'भाई की मौत भी नहीं डिगा सकी फर्ज से' शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित हुई थी।

थाने में रखा गया राबड़ी की बहू का सामान

जागरण संवाददाता, पटना

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास से बहू ऐश्वर्या राय का भेजा गया सामान शास्त्री नगर थाने में सुरक्षित रख दिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सामानों की सूची बनाई गई। इसके बाद सोफा को थानाध्यक्ष कक्ष के बाहर रखा गया और बाकी सामान परिसर में रखकर तिरपाल से ढंक दिया गया। मजिस्ट्रेट ने सामान की एक सूची शनिवार रात थाने पर पहुंचे तेज प्रताप यादव के समर्थकों को थमा दी और दूसरी प्रति थाने में कानूनी प्रक्रिया के लिए रख दी गई।

इधर, तीन दिन तक दोनों परिवारों के झगड़े में पिस रहे पिकअप वैन के चालक संजय और रवि रंजन सामान उतारते ही नौ दो ग्यारह हो गए। संजय दादी के श्राद्धकर्म में शामिल होने दुल्हिनबाजार के सिंघाड़ा गांव स्थित घर चला गया। उसका भाड़ा पांच हजार रुपये अभी बाकी है, जबकि रविरंजन को नौ हजार रुपये दिए गए हैं।

शास्त्रीनगर थाना में रखा हुआ ऐश्वर्या का सामान। जागरण

तीन दिन बाद टूटी प्रशासन की नींद : पटना में बेली रोड पर तीन दिन तक फैमिली ड्रामा चलता रहा, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी। प्रोटेक्शन ऑफिसर के निर्देशानुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ऐश्वर्या राय के सामने उनके ससुराल से सामान निकाला जाना था, लेकिन राबड़ी देवी ने खुद भिजवा दिया तो विवाद बढ़ गया। गश्ती के बहाने पुलिस चंद्रिका राय के 26/10 आवास के बाहर पिकअप वैन पर लदे सामान की रखवाली करती रही। जब चंद्रिका राय के समर्थकों ने पिकअप वैन के चालकों को खदेड़ दिया, तब प्रशासन सजग हुआ और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। थाना परिसर में तिरपाल से ढंककर रखे गए सामान में आलमारी, पलंग, टेबल आदि हैं।

जिस स्कूटी पर बैठीं प्रियंका, उसका चालान

जागरण संवाददाता, लखनऊ

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पुलिस के रोकने के बावजूद जिस स्कूटी पर बिना हेलमेट पूर्व आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी के घर के लिए निकली थीं, उसका रविवार को चालान काट दिया गया। स्कूटी लखनऊ के विनीत खंड गोमतीनगर निवासी राजदीप सिंह की थी, जिसे बिना हेलमेट पहने राजस्थान के पूर्व विधायक धीरज गुर्जर चला रहे थे। लखनऊ पुलिस ने 6100 रुपये का चालान किया है। यूपी पुलिस यातायात निदेशालय की ओर से धारा-133 मोटर अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है।

पुलिस का आरोप है कि स्कूटी (संख्या यूपी 32 एचबी 8270) से प्रियंका को लेकर धीरज गुर्जर पॉलीटेक्निक चौराहे के आगे तक गए थे। इस दौरान दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस की ओर से बिना हेलमेट ड्राइविंग, ट्रैफिक नियम तोड़ने, मानक के अनुरूप नंबर प्लेट न होने, खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है। इसके तहत पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर 2500, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500, यातायात नियम तोड़ने पर 300, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट होने पर 300 रुपये और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 2500 रुपये का चालान काटा है।

लखनऊ में शनिवार को इंदिरानगर स्थित पूर्व आइपीएस दारापुरी के घर जाने के लिए इसी स्कूटी से बिना हेलमेट निकली थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। (फाइल फोटो) जागरण

शनिवार को पुलिस के रोकने के बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा समर्थकों के साथ पूर्व आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी के परिजन से मिलने गई थीं। दारापुरी 19 दिसंबर को लखनऊ हिंसा के आरोप में जेल में बंद हैं। लोहिया पथ से स्कूटी पर बैठकर पॉलीटेक्निक चौराहे के आगे तक गईं। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।

रणनीति

वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने की योजनाओं पर चर्चा, सीएए-एनआरसी संग युवा, किसान और महिलाओं के लिए होंगे आंदोलन

हर मुद्दे को पकड़कर कदम बढ़ाएगी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस अब सड़कों पर है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा की अगुआई में अब तक कई आंदोलन हो चुके हैं। एक-एक कार्यकर्ता को घर से निकालकर मैदान में उतारने के लिए रविवार को प्रियंका ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। तय हुआ कि कांग्रेस अब हर मुद्दे को पकड़कर अगले विधानसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाएगी।

प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका आईं तो शनिवार को आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के लिए, लेकिन यहां उप्र के राजनीतिक माहौल में ताप को भांपकर वह रुक गईं। शनिवार रात तक पदाधिकारियों से मेल-मुलाकात करती रहीं प्रियंका रविवार सुबह करीब 10.30 बजे फिर प्रदेश मुख्यालय पहुंच गईं। लगभग ढाई घंटे तक उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने एक-एक कर सभी से प्रदेश की प्रमुख समस्याओं के बारे में पूछा। राय ली कि इस पर कांग्रेस को क्या करना चाहिए। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि चर्चा में सीएए, एनआरसी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बेरोजगारी, अन्ना पशु, किसानों का बकाया जैसे मुद्दे ही छाए रहे।

इस पर प्रियंका ने मत दिया कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तमाम निर्दोषों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन सभी के परिवारों से संपर्क करना है। उनसे मिलकर अहसास कराना है कि कांग्रेस उनके साथ है। इसके साथ ही चरणबद्ध सभी मुद्दों पर आंदोलन करते रहना है।

संगठन में भी लगाएं दम : बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि मुद्दों को उठाने के साथ ही संगठन को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। प्रियंका ने शनिवार को हुई सभा की तरह ही यहां भी कहा कि वरिष्ठ पदाधिकारी न सिर्फ खुद सक्रिय हों, बल्कि बूथ स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा नजर आना चाहिए।

प्रियंका आज भी करेंगी बैठक

प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रियंका वाड्रा रायबरेली के लिए रवाना हो गईं। वहां से शाम को लौटकर गोखले मार्ग स्थित अपने अस्थायी आवास पर विश्राम के लिए चली गईं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह सोमवार को दोपहर तक प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी।

रायबरेली में दिवंगत नेता के स्वजनों से मिलीं

रायबरेली : शनिवार रात ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के रायबरेली आने की संभावना थी, मगर वह रविवार को आईं। यहां पार्टी के चुनिंदा नेताओं से मिलीं। वह दिवंगत नेता स्व. सुनील श्रीवास्तव के परिवारीजन को सांत्वना देने आई थीं। लगभग आधे घंटे उनके घर पर रुकने के बाद वह सीधे अपनी गाड़ी में बैठीं और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए निकल गईं। प्रियंका से मिलने यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर राहुल वाजपेयी व वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता रमेश शुक्ल भी पत्रकारपुरम पहुंचे। जैसे ही दोनों नेता पुलिसिया घेरा पार करने लगे तो एएसपी नित्यानंद राय ने उन्हें रोक लिया और वापस जाने को कहा। राहुल ने उनका विरोध किया तो पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ धक्का- मुक्की शुरू कर दी। इस पर राहुल ने पुलिसवालों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उधर, जब ये बात प्रियंका को पता चली तो उन्होंने संगठन के एक शख्स को भेजकर राहुल को अंदर बुला लिया। इस दौरान कांग्रेसियों में पुलिस को लेकर खासी नाराजगी दिखी।

फरलो पर आते ही सक्रिय हुए पूर्व सीएम चौटाला व अजय सिंह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और जननायक जनता पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला फरलो पर बाहर आने के साथ ही फील्ड में सक्रिय हो गए। इनेलो सुप्रीमो चौटाला जहां हर जिले में कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश में हैं, वहीं जजपा संरक्षक अजय सिंह कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करते हुए पार्टी विधायकों से रूबरू होंगे।

जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल में बंद ओमप्रकाश चौटाला और अजय सिंह को 14-14 दिन की फरलो मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद ओमप्रकाश चौटाला के यह पहले जिला स्तरीय दौरे होंगे। ओमप्रकाश चौटाला 31 दिसंबर को सोनीपत जिला कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र होते हुए चौटाला अपने पूर्व राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी के आवास पर पहुंचेंगे। नए साल पर 1 जनवरी को चौटाला यमुनानगर में जिला कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसी दिन अंबाला और पंचकूला के कार्यकर्ताओं से उनकी मीटिंग होगी। चौटाला 2 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित अभय सिंह चौटाला के निवास पर रहेंगे। इनेलो ने अभी ओमप्रकाश चौटाला के इन्हीं जिलों के कार्यक्रम जारी किए हैं। बाद में बाकी जिलों के कार्यक्रम भी घोषित किए जाएंगे।

उधर, अजय सिंह चौटाला की कोशिश रहेगी कि फरलो के दौरान जजपा विधायकों खासकर नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम की बगावत से उपजे माहौल को शांत किया जाए। अजय सिंह जहां रामकुमार गौतम से मुलाकात कर सकते हैं।

2830 पाकिस्तानी नागरिकों को भारत ने नागरिकता दी है पिछले छह सालों में। इस सूची में 912 अफगानिस्तानी और 172 बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें सैकड़ों ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश में बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एनआरसी भारत सरकार का आंतरिक मामला : बीजीबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) के प्रमुख ने रविवार को यहां कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बल भारत में अवैध लोगों के प्रवेश को रोकना जारी रखेगा। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बताया कि इस्लाम की अगुआई में बीजीबी का एक शिष्टमंडल महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता के लिए भारत के दौरे पर है। एनआरसी मुद्दे पर टिप्पणी मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह भारत सरकार का आंतरिक मामला है। महानिदेशक से जब बांग्लादेश समेत तीन देशों से धार्मिक प्रताड़ना झेलने वाले गैर मुस्लिमों को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता देने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। संसद से सीएए पारित होने के बाद भारत में हो रही घटनाओं पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर बीजीबी प्रमुख ने कहा, मैं कहूंगा कि दोनों बलों के बीच समन्वयन एवं संबंध बहुत अच्छे हैं।

उप्र में खंगाली जा रही बवालियों की कुंडली

कार्रवाई ▶ डेमोक्रेटिक पार्टी व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की धरपकड़ के लिए दबिश

कई जिलों में हुआ एसटीएफ का गठन, क्राइम ब्रांच के सहयोग से धरपकड़

जागरण न्यूज नेटवर्क, मेरठ

सीसीए के विरोध की आड़ में हुई हिंसा की जांच को कई जिलों में एसआइटी का गठन हो चुका है। मेरठ में एसपी क्राइम के नेतृत्व में टीम जांच कर रही है। हिंसा में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस उक्त संगठनों के सदस्यों की धरपकड़ के लिऐ दबिश दे रही है।

इस बीच, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि बवालियों को चिह्नित करने के नाम पर वसूली की जा रही है और वह चिह्नित बवालियों के घर दबिश डालने से कतरा रही है। शहर काजी का कहना है कि पुलिस की दबिश का विरोध करेंगे। मामले की मजिस्ट्रीयल जांच होनी चाहिए। उधर, शामली में शांति के बीच संवेदनशील स्थानों पर अब भी पुलिसबल तैनात है। जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था जारी है।

बिजनौर में पुलिस ने चिह्नित बवालियों के पोस्टर चस्पा किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की। एसआइटी ने जांच के लिए साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। देवबंद व कोतवाली नगर में प्रदर्शन को लेकर दर्ज हुए दो मुकदमों की जांच संबंधित थानेदार ही कर रहे हैं। बुलंदशहर में सब कुछ शांत है, लेकिन अब भी फोर्स अलर्ट पर है। एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में मुस्लिम बस्तियों में जाकर सीएए के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

पता चला है कि आरोपितों ने दूसरे शहरों में शरण ले रखी है। यहां क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस-प्रशासन सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों की तलाश में जुटा है। एसआइटी ने उपद्रव के बाद बरामद हथियार मालखाने में जमा कराए हैं। अलीगढ़ में एसपी क्राइम डॉ. अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं गोरखपुर में भी बवाल पर काबू पाने के बाद पुलिस अब इसके पीछे की साजिशों की परत-दर-परत खोलने की तैयारी कर रही है।

हिंसा के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ होने की आशंका शुरू से जताई जा रही है। एलआइयू ने बवाल शुरू होने के दिन जामा मस्जिद के आसपास बाहरी तत्वों के मौजूद होने और लोगों को उकसाने की रिपोर्ट भी दी है। दूसरे शहरों से भी बवाल के लिए उकसाने वाले फोन आने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब उन बाहरी तत्वों चिह्नित करने में जुटी है।

हाई कोर्ट में एएमयू कैंपस में लगे 51 कैमरे देंगे उपद्रव की 'गवाही'

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में 15 दिसंबर को हुए बवाल की गवाही कैंपस में लगे 51 सीसीटीवी कैमरे हाई कोर्ट में देंगे। पुलिस सुबूत के रूप में सीसीटीवी फुटेज पेश करेगी। हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका (पीआइएल) पर दो जनवरी को सुनवाई होनी है। एएमयू में सीएए का 11 दिसंबर से विरोध चल रहा है। 13 दिसंबर को शुक्रवार के दिन सड़कों पर उतरे हजारों छात्रों ने हंगामा काटा। कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस से भिड़ने की पूरी कोशिश की। अफसरों को गालियां तक दी गईं, लेकिन अधिकारियों की सूझबूझ से टकराव टल गया था। 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुए बवाल में दो छात्रों की गोली लगने की अफवाह ने एएमयू के शांत माहौल में आग लगाने का काम किया। सैकड़ों की संख्या में छात्र बाबे सैयद तोड़कर बाहर आ गए और पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले इस्तेमाल करने से कई छात्र घायल हो गए। इस मामले में पुलिस की ओर से दो और आरएएफ की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में हाई कोर्ट में पीआइएल दाखिल की गई है, जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि छात्रों पर अत्याचार किया गया है। पुलिस ने अपने बचाव में यूनिवर्सिटी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। बाबे सैयद से चुंगी गेट, डक प्वॉइंट, इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, वीसी लॉज, स्टॉफ क्लब, रजिस्ट्रार ऑफिस के आसपास लगे 51 कैमरों के फुटेज में पूरा बवाल कैद हुआ है। प्रॉक्टर कार्यालय से सभी फुटेज पुलिस ने लिए हैं।

> कैंपस के 51 सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज पुलिस को दिए गए हैं, जिनमें पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है।
> **– प्रो. अफीफुल्लाह खान, प्रॉक्टर एएमयू**

> हाई कोर्ट में दाखिल हुई पीआइएल की दो जनवरी को सुनवाई है। उसमें वीडियो फुटेज पेश किए जाएंगे। कई वीडियो ऐसे हैं, जिसमें बवाल की पूरी कहानी कैद हुई है।
> **– आकाश कुलहरि, एसएसपी, अलीगढ़**

एनपीआर के साथ स्कूल न जाने वाले बच्चों की भी होगी पहचान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर विपक्षी दल भले ही सवाल खड़े कर रहे है, लेकिन सरकार इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी और अहम जानकारियां जुटाने की तैयारी में है। फिलहाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस दिशा में एक बड़ी पहल की है। मंत्रालय ने एनपीआर के साथ स्कूल न जाने वाले बच्चों की सटीक जानकारी हासिल करने की योजना बनाई है। मौजूदा समय में मंत्रालय के पास ऐसे बच्चों का कोई प्रामाणिक ब्योरा नहीं है। हालांकि अलग-अलग स्रोतों से देश में ऐसे बच्चों की संख्या छह करोड़ के आसपास बताई जाती है।

मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्कूल न जाने वाले बच्चों की सही जानकारी मिलने से ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि मंत्रालय ने एनपीआर के साथ ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाने को लेकर भी सर्वे कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इस पर संबंधित मंत्रालय के साथ अभी चर्चा होना बाकी है, लेकिन मंत्रालय का मानना है कि यदि स्कूल न जाने वाले बच्चों के सर्वे का काम भी इसके साथ हो जाता है, तो समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी।

वैसे भी प्रस्तावित नई शिक्षा नीति में ऐसे बच्चों की चिंहित करने की भी सिफारिश की गई है। हालांकि अभी इस नीति के आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में मंत्रालय ने इस पूरी योजना को आगे बढ़ाया है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस दौरान जो प्रस्ताव किया गया है, उसमें सर्वे में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों (तीन से 18 वर्ष के बीच) की अलग से गणना शामिल है। साथ ही उनमें ऐसे कितने बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते है। फिलहाल यू-डीआइएसई (यूनिफाइड-डिस्ट्रिक इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) के 2016-17 के आंकड़ों के मुताबिक एक से पांचवीं कक्षा के बीच सकल नामांकन दर (जीईआर) 95.1 फीसद था, जबकि कक्षा नौ-दस में 79.3 फीसद और कक्षा 11-12 में 51 फीसद था। सरकार की कोशिश है कि स्कूल जाने की उम्र वाले सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ा जाए। उसका लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात को शत प्रतिशत करना है। नई शिक्षा नीति में भी वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल एनपीआर का काम देश में अप्रैल 2020 से शुरू होगा।

बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट बाड़' का काम जुलाई तक हो जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) के महानिदेशक वीके जौहरी ने रविवार को कहा कि असम में भारत-बांग्लादेश जल सीमा पर अगले साल जुलाई तक 'स्मार्ट बाड़' लगाने का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस साल क्षेत्र में भारी बारिश और फिर बाढ़ आने की वजह से इस परियोजना के पूरा होने में छह महीने की देरी हो गई। उन्होंने कहा कि पहले इसकी समय सीमा दिसंबर 2019 थी। जौहरी बांग्लादेश के अपने समकक्ष बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम के साथ प्रेस वार्ता से इतर बात कर रहे थे। बीएसएफ प्रमुख ने कहा, 'काम क्रियान्वयन करने के चरण में है और यह जुलाई 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए।' बीएसएफ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर धुब्री में 55 किलोमीटर लंबी पट्टी में 'स्मार्ट बाड़' लगाने पर काम कर रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध से पहले दलित शरणार्थियों की हालत देखें : नड्डा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बोले-मोदी के नेतृत्व में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का सपना साकार

▶ केजरीवाल पर तंज, कहा- वाई-फाई की बात करने वाले शरणार्थी कैंपों तक नहीं पहुंचा सके बिजली-पानी

तालकटोरा स्टेडियम में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वितीय स्मृति दिवस में मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा (बीच में हाथ जोड़े), भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू (दाएं) व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी (बाएं) को माला पहनाकर स्वागत करते कार्यकर्ता। संजय

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को भाजपा ने शरणार्थी कैंपों में जाकर वहां रहने वाले दलितों की स्थिति को देखने की सलाह दी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों को सीएए पर घड़ियाली आंसू बहाने से पहले देश में सालों से शरणार्थी का जीवन जी रहे उन दलितों को देखना चाहिए, जिनके जीवन में सीएए नया उजाला लाया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दिल्ली की अवैध कालोनियों को वैध करके हमने 40 लाख लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। इसके साथ ही जहां झुग्गी, वहीं मकान के सपने को भी पूरा करने का दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे स्मृति दिवस पर तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सरकार की प्रतिबद्धताओं को भी सामने रखा और कहा कि हमने जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया है। पूरे देश की जनता में सालों से एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का सपना था। यह कभी पूरा भी होगा, इसका विश्वास नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सपना भी पूरा हो गया है। अब देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है।

नड्डा ने इस दौरान दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि वह दिल्ली को फ्री-वाई-फाई बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वह भी इन शरणार्थी कैंपों में पानी और बिजली तक नहीं पहुंचा पाए। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे हैं, जिन्होंने देश की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया है और उन्हीं के नेतृत्व में देश आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र को लेकर पार्टी आगे भी इसी तरह से काम करती रहेगी।

आरोप सच तो मेरठ एसपी पर हो कार्रवाई : नकवी

मुंबई, एएनआइ : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदर्शनकारियोंको 'पाकिस्तान चले जाने' की बात कहने वाले मेरठ के एसपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नकवी ने कहा कि अगर यह सच है तो निंदनीय है। पुलिस अधिकारी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'किसी भी स्तर पर हिंसा (चाहे वह पुलिस करे या भीड़) अस्वीकार है। यह लोकतांत्रिक देश का हिस्सा नहीं हो सकता। पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो निर्दोष हैं, वे प्रताड़ित न हों।'

शनिवार को सामने आए एक वायरल वीडियो में मेरठ सीटी एसपी अखिलेश नारायण सिंह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक मुस्लिम समूह से पाकिस्तान चले जाओ, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो 20 दिसंबर का है जब मेरठ में नागरिकता कानून के विरोध में किया जा रहा प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया था।

एडीजी ने एसपी का बचाव किया : वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेरठ जोन के एडीजी ने भी मामले पर सफाई दी। एडीजी प्रशांत कुमार ने एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का बचाव करते हुए कहा, 'पत्थरबाजी की जा रही थी। भारत विरोधी और पड़ोसी देश के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। पेम्फलेट बांटे जा रहे थे।

यह सब धर्म गुरुओं और अन्य तरीकों से अपील करने के बावजूद हो रहा था।' उन्होंने कहा, 'हां, अगर स्थिति सामान्य होती तो शब्दों का चयन बेहतर होता लेकिन स्थिति काफी बिगड़ गई थी और हमारे अधिकारियों ने काफी संयम दिखाया। पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई।' बकि एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह कह चुके हैं कि जो कुछ भी वीडियो में दिखा वह प्रदर्शनकारियों के उस समूह को जवाब था, जब वे सभी पाकिस्तान के समर्थन में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगे रहे थे। उन्होंने कहा, 'प्रतिक्रियास्वरूप, मैंने यह सलाह दी कि यह बेहतर होगा कि पाकिस्तान चले जाएं जहां के समर्थन में वे नारे लगा रहे थे।' एसपी सीटी ने आगे कहा, 'मैं ऐसा मानता हूं कि जो अपने मुल्क को प्यार करता हो वो कभी भी ऐसे नारों को बर्दाश्त नहीं करेगा।'

▶ 'पाकिस्तान चले जाओ' के बयान पर केंद्रीय मंत्री खफा

▶ कहा, किसी भी स्तर पर हिंसा स्वीकार नहीं है

मुख्तार अब्बास नकवी। फाइल

एसपी के समर्थन में आए डिप्टी सीएम मौर्य

लखनऊ, एएनआइ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अफसर के सोशल मीडिया पर वायरल हुए बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए उनका बयान उचित है। मौर्या ने मीडिया को बताया कि मेरठ के पुलिस अधीक्षक का बयान उन प्रदर्शनकारियों के लिए उचित है जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।

एनआरसी और एनपीआर में कोई अंतर नहीं, वापस ले सरकार : ओवैसी

जासं, किशनगंज

असदुद्दीन ओवैसी। फाइल

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) में कोई अंतर नहीं है। एआइएमआइएम (ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन) प्रमुख ने चेतावनी दी कि 26 जनवरी तक इस काले कानून को केंद्र सरकार वापस ले। उन्होंने रविवार को बिहार के किशनगंज में आयोजित संविधान बचाओ-देश बचाओ जन आक्रोश सभा में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। उप्र के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मेरठ के सिटी एसपी पर भी निशाना साधा।

औवैसी ने कहा कि जिस कानून के बारे में संविधान रचयिता डॉ. भीमराव आंबेडकर व डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी नहीं सोचा होगा, उसे केंद्र की मोदी सरकार लागू कर रही है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के बहाने देश में काला कानून लागू कर दिया गया। कहा, हमें कोई एतराज नहीं कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगनिस्तान के हिंदुओं को भारत में रिफ्यूजी का स्टेट्स दीजिए। लेकिन देश को धर्म के नाम पर मत बांटिए।

उन्होंने कहा कि जब से सीएए बना है, भारत में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक आइपीएस का वीडियो वायरल होता है। उन्होंने कहा कि यह वहीं मेरठ है जब अंग्रेजों से मुस्लिम और हिंदु पुलिस जवानों ने विद्रोह किया था तो अंग्रेजों के सीने पर पहली गोली मुस्लिमों ने मारी थी। यह वही मेरठ है जहां पर हिंदु-मुस्लिम ने मिल कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। कहा, हमें लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, गोली खत्म हो जाएगी, लेकिन हम पकिस्तान नहीं जाएंगे। हम तब भी नहीं गए थे और अब भी नहीं जाएंगे।

'लोगों को गुमराह करने के लिए हो रही चर्चा'

राज्य ब्यूरो, पटना

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस देश में एनआरसी-एनपीआर पर बेकार की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ-साफ कहा है कि अब तक एनआरसी पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर असम के लिए एनआरसी का फैसला हुआ है। बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए व्यर्थ चर्चा की जा रही है। वह रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद सूरज नंदन कुशवाहा की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। रविशंकर ने कहा कि एनपीआर क्या है? ये आबादी का रजिस्टर है। जो इस देश में रहती है। मनमोहन सिंह की सरकार ने एनपीआर पर काम शुरू किया था। जिसका समर्थन मुलायम सिंह, लालू प्रसाद जैसे नेताओं ने किया था। उस वक्त यह तय हुआ था कि लोगों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा पर आज इसे लेकर विवाद किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में कहा, भाजपा विरोध का सम्मान करती है। लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन जो लोग देश को तोड़ने का काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। फाइल

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस मौके पर कहा कि यूपीए सरकार के दौरान 2010 में एनपीआर बनाने का काम शुरू हुआ था, तब लालू प्रसाद सरकार में शामिल थे। एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2010 तक एनपीआर का काम पूरा हुआ। 2021 की जनगणना के पूर्व अब इसे केवल अपडेट करना है। सभी राज्यों ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन कर दिया है तो कांग्रेस, राजद सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जानबूझ कर विवाद पैदा कर रही है। सुशील मोदी ने कहा कि जब यूपीए सरकार एनपीआर बनाने पर काम कर रही थी, तब लालू प्रसाद ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? अब जब पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।

लालू का सच से वास्ता होता तो चारा घोटाला न होता : सुशील मोदी

सुशील कुमार मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि यदि लालू प्रसाद का सच से वास्ता होता तो बिहार में न तो चारा घोटाला होता और न वे सजायाफ्ता होते। वह बताएं कि भागलपुर दंगा के मुख्य अभियुक्त को बचाने में किसकी भूमिका थी? उनका नया झूठ है कि सरकार जनगणना में कुत्ता-बिल्ली, सियार-सुअर की गिनती कराती है।

लालू प्रसाद या तो जनगणना और पशुगणना का अंतर नहीं जानते या आम आदमी को जानवरों के समान समझते हैं। मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण के साथ ही साफ कर दिया कि वह चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद, हेराल्ड हाउस घोटाले के अभियुक्त राहुल गांधी और शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी ममता बनर्जी के दबाव में ही सरकार चलाएंगे। यदि ऐसा न होता तो विधानसभा की एक सीट जीतने वाले राजद को पहले ही दिन मंत्रिपरिषद में शामिल न किया गया होता।

सीएए का समर्थन करने पर बसपा विधायक रामबाई पार्टी से निलंबित

नईदुनिया, भोपाल

▶ मायावती ने पार्टी लाइन से अलग जाने पर मप्र की विधायक पर की कार्रवाई

▶ विधायक ने बयान पर माफी मांगी, कहा-मायावती मेरी अभिभावक

▶ रामबाई पर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने पर भी लगा दी गई रोक

▶ विधायक को पहले भी कई बार पार्टी लाइन पर चलने की मिली है हिदायत

बसपा विधायक रामबाई। फाइल

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का समर्थन करने पर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई को बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बसपा की ओर से कहा गया है कि पार्टी लाइन से बाहर जाकर रामबाई ने अनुशासनहीनता की। उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने से भी रोक दिया गया है। कार्रवाई होते ही रामबाई अपने बयान से पलट गईं और माफी भी मांग ली। कांग्रेस ने इसे बसपा का अंदरूनी मामला बताया है।

सीएए के समर्थन में विधायक रामबाई के बयान मीडिया में आते ही मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बसपा अनुशासित पार्टी है व इसे तोड़ने पर सांसद-विधायकों के विरुद्ध भी तुरंत कार्रवाई की जाती है। बसपा विधायक रामबाई को पार्टी से निलंबित किया गया है। उन पर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा कि बसपा ने सबसे पहले सीएए को विभाजनकारी व असंवैधानिक बताकर इसका तीव्र विरोध किया, संसद में इसके विरुद्ध वोट दिया। इसकी वापसी को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया था। रामबाई ने सीएए का समर्थन किया, पहले भी उन्हें कई बार पार्टी लाइन पर चलने की चेतावनी दी जा चुकी है।

अंतिम सांस तक मायावती के साथ रहूंगी : कार्रवाई के बाद रामबाई ने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उनकी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। मैंने तो बाहर से आने वाले ऐसे लोगों का विरोध किया था, जो देश में आकर आतंकी कार्रवाई करते हैं। यदि बहनजी को लगता है कि मैंने उनका विरोध किया है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। यदि कोई बच्चा गलती कर देता है तो माता-पिता उसे घर से बाहर नहीं निकालते हैं। मैंने पहले भी कई बार गलतियां की हैं और उन्होंने माफ किया है। इस बार भी वह माफ कर देंगी। मायावती मेरी अभिभावक हैं, अंतिम सांस तक मैं उनके साथ ही रहूंगी।

यह है मामला

शनिवार को नगर पंचायत पथरिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रामबाई ने सीएए का समर्थन किया था और उसे देश हित में बताया था। शनिवार रात मीडिया को दिए इंटरव्यू में भी विधायक ने दोबारा सीएए का समर्थन किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी।

> विधायक रामबाई पर अनुशासनहीनता के चलते बसपा सुप्रीमो ने निलंबन की कार्रवाई की है। अब अनुशासन समिति उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर सफाई मांगेगी।
> **– रमाकांत पिप्पल, मप्र बसपा अध्यक्ष**

> निलंबन की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी एवं बाबा साहब आंबेडकर की मंशा के अनुरूप उनके आदेश का पालन किया है। कांग्रेस व विपक्षी दलों ने इस कानून को सांप्रदायिक रंग देने का जो प्रयास किया, वह विफल हो गया।
> **–रामेश्वर शर्मा, विधायक, भाजपा, मप्र**

'राजनीतिक केंद्र बन रहे शैक्षणिक संस्थान बर्दाश्त नहीं'

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने दी चेतावनी

▶ विपक्षी दलों पर सीएए को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया

कोलकाता में रविवार को भाजपा की शिक्षक प्रकोष्ठ के सम्मेलन के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक(बाएं) से बातचीत करते भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। एएनआइ

राजनीतिक केंद्रों में तब्दील हो रहे शैक्षणिक संस्थानों को केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने यह चेतावनी दी। वह रविवार को कोलकाता में प्रदेश भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। सम्मेलन में उन्होंने सीएए के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इससे दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि कई छात्र दूर-दूर से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उन्होंने कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है।' जवाहरलाल नेहरू विवि, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विवि, जादवपुर विवि तथा प्रेसीडेंसी विवि सहित देशभर के कई विश्वविद्यालयों के करोड़ों छात्रों ने सीएए का विरोध किया है। इसके लिए पोखरियाल ने विपक्षी दलों पर सीएए को लेकर जानबूझकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस है, जो देश के धार्मिक आधार पर विभाजन के लिए जिम्मेदार है। यह अब सीएए के बारे में गलत सूचना फैला रही है। मंत्री ने नागरिकता कानून के विरोध के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा, तृणमूल सुप्रीमो 2005 में जब एक सांसद थीं तब उन्होंने राज्य में घुसपैठ का विरोध किया था। उन्होंने संसद में यह विरोध जताया था। उन्होंने मुखर रूप से नागरिकता संशोधन विधेयक की मांग की थी। पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर काम चल रहा है। इसे देश के मूल्यों से जोड़ा जाएगा।

धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोगों की मदद को बना सीएए : 'निशंक' ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी के खिलाफ नहीं है। धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए गए लोगों की मदमद के लिए यह कानून बना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई, पारसी, तथा बौद्ध, जैन धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर अत्यचार सहना पड़ा। उन्हीं लोगों यहां की नागरिकता देने के लिए यह कानून तैयार किया गया है। इस कानून का विरोध करने वाली ममता बनर्जी एवं कांग्रेस से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सवाल किया। उन्होंने प्रश्न किया कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान में 23 फीसद गैर मुस्लिम लोग थे जो आज लगभग 3 फीसद हो गए हैं जबकि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में ये लोग 22 फीसद थे जो आज घटकर 7.8 फीसद हो गए हैं। ये बाकी लोग कहां गए?

सीएए पर पार्टी लाइन से अलग आंदोलन कर रहे जदयू विधायक

जागरण संवाददाता, किशनगंज: नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर विपक्षी दलों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का असर एनडीए गठबंधन की राजनीति पर भी पड़ा है।

जहां केंद्र के साथ लोकसभा और राज्यसभा में जदयू कदमताल करती दिखी, वहीं किशनगंज के दोनों जदयू विधायक लगातार सीएए व एनआरसी के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जदयू विधायक मुजाहिद आलम और नौशाद आलम न सिर्फ कांग्रेस, एआइएमआइएम व अन्य पार्टियों के साथ बैठकों में भाग ले रहे हैं बल्कि खुलकर यह कहते भी हैं कि वह इस मसले पर पार्टी नहीं, अवाम के साथ हैं। कई मौकों पर कोचाधामन विधायक मुजाहिद आलम व ठाकुरगंज विधायक सह विधानसभा में पार्टी के सचेतक नौशाद आलम विरोध मार्च में शामिल हो चुके हैं।

6 शिकायतें मिली हैं भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान मेडिकल कॉलेजों में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग की। पिछले सत्र में यह संख्या 13 और इससे पहले 25 थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 30 दिसंबर 2019

ठंड का कहर ▶ आखिरकार हवा ने बदला रुख, राजधानी दिल्ली में लोगों को कंपकंपी से मिली कुछ राहत

उत्तर भारत में शीतलहर जारी, पाले ने बढ़ाई दिक्कतें

श्रीनगर और माउंट आबू में न्यूनतम तापमान और गिरा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

कई दिनों से जारी सर्दी और शीतलहर के बाद पाला पड़ने से उत्तर भारत में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि हवा की दिशा में बदलाव के कारण 22 वर्षों के सबसे लंबे ठंड के दौर से गुजरे दिल्ली वालों को रविवार को थोड़ी राहत मिली, लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। कोहरे के कारण रेल और वायु यातायात प्रभावित है। कश्मीर के विक्षोभ व उत्तर-पश्चिम हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी, कोहरे व शीतलहर का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश में दो डिग्री तापमान के साथ सहारनपुर और सुल्तानपुर मसूरी से भी ठंडे रहे। 2.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बठिंडा पंजाब में सबसे ठंडा रहा।

हरियाणा के सात जिलों का न्यूनतम तापमान दो डिग्री या इससे कम रहा। राज्य के स्कूलों में 16 जनवरी तक के लिए छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरकर 1.4 डिग्री से. आ पहुंचा। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में यह माइनस तीन डिग्री पर पहुंच गया। शहर के सभी इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिली। मध्यप्रदेश के अमरकंटक में पारा शून्य पर आ गया तो पचमढ़ी में 1.2 डिग्री रहा। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह औसत न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा उत्तर-पश्चिम से हवा की दिशा में तेजी से बदलाव शुरू होने से हुआ।

डल झील जमी : जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलां के बीच श्रीनगर का पारा लगातार गिर रहा है। डल जल सहित लगभग दूसरे जलस्रोत जम गए हैं। पाला जमने के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात गुजरी। जम्मू में हल्की धूप के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। लद्दाख में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री नीचे चल रहा है। दिन में बर्फीली हवा का असर कम होने से उत्तराखंड में पारे में मामूली सुधार हुआ है।

पाले से खराब हो रहीं सब्जियां : कुछ दिनों से खेतों में पाला जम रहा है। सब्जी की फसल ठंड के कारण नष्ट हो रही है। इससे सब्जियों क दाम भी एकाएक बढ़ गई है।

बारिश से होगी नववर्ष की शुरुआत : मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर तेज हवाओं के प्रभाव से मंगलवार शाम से दिल्ली-एनसीआर में हवा की गति में वृद्धि होने की उम्मीद है। नये साल की शुरुआत बारिश से हो सकती है। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक रात के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है और 2 जनवरी को ओलावृष्टि की संभावना है।

कोहरा के कारण 100 उड़ानें प्रभावित : कोहरे के कारण उड़ानों का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। रविवार को भी दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर 100 उड़ाने देरी से उतरीं और उड़ीं। सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली आने वाली उड़ानों पर पड़ा। हालांकि न तो किसी उड़ान को रद किया गया और न ही कोई डायवर्ट हुई। एयरपोर्ट पर सामान्य दृश्यता करीब 150 मीटर थी।

जम गई डल झील : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध डल झील का पानी जमने लगा है। रविवार को बर्फ हटाकर गंतव्य की ओर जाता स्थानीय नागरिक। प्रेट्र

शहर और न्यूनतम तापमान	
श्रीनगर	-6.2
लेह	-19.0
बठिंडा	2.4
हिसार	0.2
नारनौल	1.5
दिल्ली	3.4

(डिग्री सेल्सियस में)

उप्र में ठंड से 27 लोगों की मौत

कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। रविवार को उत्तर प्रदेश में 27 लोगों की मौत हो गई। बिहार में तीन और मध्यप्रदेश में दो लोगों के ठंड से मरने की खबर है।

17 दिन बाद भी रिलकोट चौकी से नहीं निकाले जा सके आइटीबीपी के जवान

संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़: उच्च हिमालय की अग्रिम चौकी रिलकोट में 17 दिन से फंसे जवानों को रविवार को भी मुनस्यारी नहीं लाया जा सका। अब मौसम को देखते हुए सोमवार को अभियान चलाया जा सकता है।

उच्च हिमालयी क्षेत्र से निचले इलाकों में आइटीबीपी की चौकी शिफ्ट करने के दौरान 12 और 13 दिसंबर को भारी हिमपात हो गया था। तब से आठ जवान रिलकोट चौकी में हैं। जवानों के पास हथियार और सामान है। इसे देखते हुए जवानों को रिलकोट से हेलीकॉप्टर से मुनस्यारी लाया जाना है। गृह मंत्रालय को सूचना देने के बाद जवानों को हेलीकॉप्टर से लाए जाने की अनुमति भी मिल चुकी है। रविवार को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आया। 13वीं वाहिनी आइटीबीपी जाजरदेवल के सेनानी अशोक कुमार ने बताया कि रविवार को जवानों को लाने का कार्य नहीं चल सका। सोमवार को उच्च हिमालय के मौसम को देखते हुए कार्रवाई की जाएगी। मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि रिलकोट चौकी में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हिमाचल में बर्फबारी से होगा नए साल का आगाज

राज्य ब्यूरो, शिमला

हिमाचल के पहाड़ी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में इस बार नववर्ष का आगाज बर्फबारी के साथ होगा। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर को प्रदेश में हिमपात की संभावना है। ऐसे में नववर्ष की पूर्व संध्या से ही पहाड़ों की रानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्र एक बार फिर बर्फ की चादर ओढ़ सकते हैं। तीन जनवरी तक ऊंचे व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात का क्रम जारी रहेगा।

इसके अलावा निचले हिमाचल में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहली जनवरी को अधिकतर क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में नए साल पर हिमपात देखने के लिए देवभूमि के पर्यटन स्थलों शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में पर्यटकों का सैलाब उमड़ेगा।

मौसम के पूर्वानुमान को देख पर्यटकों ने नववर्ष के जश्न को आसमान से बरसने वाली चांदी के साथ मनाने के लिए बुकिंग एडवांस में करवा ली है। क्रिसमस पर धूप के खिले रहने से उन्हें मायूसी हाथ लगी थी। अब वह नववर्ष पर हिमपात की आस में फिर से हिमाचल का रुख करने वाले हैं। सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर घने कोहरे के साथ हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। रविवार को धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन शिमला के न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई।

प्रदेश में आठ स्थानों पर रात में तापमान जमाव बिंदु से नीचे है। लाहुल में इतनी ज्यादा अधिक ठंड पड़ रही है कि पानी के साथ दूध और तेल तक जम रहा है। एक ही दिन में ऊना जिले में न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इन हालात के बावजूद हिमाचल प्रदेश सैलानियों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। रोज ही यहां सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं।

3 जनवरी तक हिमपात की संभावना, लाहुल में पानी के साथ दूध और तेल तक जम रहा

31 दिसंबर से मौसम का तेवर एक बार फिर बदलेगा। ऐसे में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। तीन जनवरी तक मौसम के खराब रहने से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले हिमाचल में बारिश हो सकती है।

-मनमोहन सिंह, निदेशक, मौसम विभाग शिमला

न्यूज गैलरी

मप्र के शाजापुर में बड़ा मालगाड़ी हादसा टला

शाजापुर: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रविवार को बड़ा रेल हादसा टल गया। मुख्यालय से करीब 20 किमी दूर आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर उकावता के पास रेलवे पुल को कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर से पुल का गर्डर क्षतिग्रस्त होने के साथ पटरी भी तिरछी हो गई। पुल के नीचे फंसे कंटेनर से हाईवे पर जाम लग गया। कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ट्रैक पर ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। वहां मौजूद रेलवे विद्युतीकरण का काम करने वाले निजी कंपनी के कर्मचारी गुरबख्शसिंह निवासी चांपा (छत्तीसगढ़) ने मालगाड़ी को कपड़ा दिखाकर रुकवा दिया। (नई दुनिया)

छग में बारसूर-पल्ली मार्ग में मिला पांच किलो का बम

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दो जिलों नारायणपुर और दंतेवाड़ा को जोड़ने बारसूर-पल्ली मार्ग बनाया जा रहा है। इस मार्ग पर ग्राम बोदली के पास सीआरपीएफ के जवानों ने पांच किलो वजनी बम बरामद किया, जिसे बाद में मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया। सड़क निर्माण सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ 195 बटालियन के हवाले है। शनिवार को सहायक कमांडेंट आशीष मिश्रा के नेतृत्व में टीम सड़क निर्माण की सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र की सर्चिंग पर निकली थी। तभी एक पेड़ के नीचे स्निफर डॉग की मदद से जवानों ने पांच किलो वजनी आइइडी बरामद किया। (नईदुनिया)

गुवाहाटी एक्सप्रेस से टकराया सांड़, दिल्ली-हावड़ा ट्रैक बाधित

फीरोजाबाद: गुवाहाटी से बीकानेर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन से रविवार रात सांड़ टकरा गया। इसके बाद उसका शव दूसरे रेल ट्रैक पर जा गिरा। इससे अप एवं डाउन ट्रैक लगभग पौन घंटे तक बाधित रहा। घटना रविवार की रात 8:30 बजे की है। बीकानेर जा रही 15632 गुवाहाटी-बीकानेर एक्सप्रेस कानपुर रेलखंड के शिकोहाबाद व मक्खनपुर रेलवे स्टेशन के मध्य गुजर रही थी। तभी खेतों के रास्ते एक सांड़ ट्रेन के इंजन के आगे आ गया। इंजन से टकराने के बाद उसका शव अप ट्रैक से डाउन ट्रैक पर जाकर गिरा। इसके चलते दोनों ट्रैक बाधित हो गए। टूंडला कंट्रोल से दोनों रेल ट्रैक पर पीछे आ रही ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर रुकवा कर शव हटवाने को टीम रवाना की गई। रात सवा नौ बजे करीब दोनों ही ट्रैक साफ होने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। (जासं)

झारखंड में माओवादियों ने डायनामाइट से अस्पताल का निर्माणाधीन भवन उड़ाया

जागरण संवाददाता, खूंटी

शनिवार देर रात भाकपा माओवादियों ने झारखंड के खूंटी स्थित अड़की थानांतर्गत सेल्दा गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए निर्माणाधीन भवन को डायनामाइट से उड़ा दिया। सेल्दा गांव भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू से महज साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात बड़ी संख्या में माओवादी यहां पहुंचे और घटना को अंजाम देकर आराम से निकल गए। विस्फोट के जोरदार धमाके से ग्रामीण दहशत में आ गए और घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सुबह होने पर ग्रामीणों ने देखा कि निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन ध्वस्त हो चुका है। साथ ही, आसपास के इलाके में जगह-जगह माओवादियों का पुलिस को चेतावनी देने से संबंधित पोस्टर चिपका हुआ है। पोस्टरों में स्कूलों से पुलिस का कैंप हटाने की बात कहते हुए लिखा गया है कि स्कूल शिक्षा का केंद्र है। पुलिस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

45 लाख की लागत से हो रहा था निर्माण : स्वास्थ्य उपकेंद्र की बिल्डिंग भवन निर्माण विभाग लगभग 45 लाख रुपये की लागत से बना रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बताया जाता है कि बहुत दिनों से इन इलाकों में माओवादियों की गतिविधियां नहीं थीं, लेकिन इधर फिर से नक्सलियों ने अपनी धमक का अहसास दिलाना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले भी नक्सलियों ने बिरसा मुंडा के सेनापति गया सिंह मुंडा के पैतृक गांव एटकेडीह गांव में बन रहे सामुदायिक भवन को जिलेटिन बम से विस्फोट कर उड़ा दिया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं।

12 घंटे बाद भी नहीं पहुंची पुलिस : घटना की जानकारी मिलने के 12 घंटे बाद भी पुलिस घटनास्थल तक नहीं पहुंची थी। जबकि, तीन किलोमीटर दूर उलिहातू में एसएसबी का कैंप है।

बिहार में पुलिस का मुखबिर होने के आरोप में दो की हत्या

जासं, लखीसराय : बिहार के लखीसराय में अनुसूचित जनजाति बहुल दो गांवों में नक्सलियों ने शनिवार की पूरी रात उत्पात मचाया। गोबरदाहा एवं बासकुंड गांव में दो ग्रामीणों को घर से खींच मौत के घाट उतार दिया गया तथा कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर धमकी दी कि पुलिस का मुखबिर बनने वाले का यही अंजाम होगा। जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने शनिवार रात करीब सात बजे कुंदर पंचायत क्षेत्र के गोरधोबा गांव में प्रवेश किया। एक घंटा तक गांव में उत्पात मचाने के बाद करीब आठ बजे अपने ससुराल में रह रहे संजय कोड़ा (30) के घर में दो नक्सली घुसे और उसे घर से खींचकर ले गए। बाद में उसका हाथ पीछे की तरफ बांध कर जंगल की ओर ले जाकर उसके सीने में दो गोली दाग कर उसकी हत्या कर दी। इसके तीन घंटे बाद भलूई पंचायत के बासकुंड गांव में मोगल कोड़ा (63) को भी तीन की संख्या में आए नक्सलियों ने घर से खींचकर दस मीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बासकुंड के पास ले जाकर उसके सिर में छह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोबरदाहा में वारदात को अंजाम देने के बाद बासकुंड आने के क्रम में नक्सलियों ने रास्ते में पड़ने वाले गांव सतघरवा, कुंदरी के ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की। रविवार की दोपहर बाद चानन थानाध्यक्ष वैभव कुमार बासकुंड एवं एसआइ राजकुमार राम ने पुलिस बल के साथ गोबरदाहा पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय भेजा। बासकुंड से पुलिस ने छह खोखा एवं एक कारतूस बरामद किया है।

उधर, एएसपी (अभियान) पवन कुमार उपाध्याय ने कहा कि नक्सलियों के शिकार दोनों व्यक्ति पुलिस के मुखबिर नहीं थे। केवल दहशत बनाने के लिए नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया।

सहारनपुर में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष पथराव-फायरिंग

जासं, सहारनपुर : मामूली बात को लेकर देवबंद में सांप्रदायिक संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर फायरिंग व पथराव हुआ। इसमें तीन लोग घायल हो गए। इससे तनाव फैल गया। आरएएफ के साथ ही कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को घायल युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

रविवार दोपहर मोहल्ला कायस्थवाड़ा स्थित सफेद हवेली के निकट हेयर सैलून पर बैठे कुछ युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इसमें वाल्मीकि बस्ती निवासी गगन घायल हो गया था। इसी बात को लेकर रात में एचएवी इंटर कालेज के पास दोनों संप्रदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव व फायरिंग हुई। पथराव के दौरान एक संप्रदाय के लोगों ने सड़क किनारे लगी सब्जी आदि की कई फड़ों में तोड़फोड़ की। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। अधिकारियों ने दोनों संप्रदाय के जिम्मेदार लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को कंट्रोल किया। देर रात एसएसपी दिनेश कुमार पी ने घटना स्थल का मुआयना किया।

जम्मू कश्मीर में बेरोजगारों के लिए वरदान बनी 'हिमायत'

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए हिमायत योजना वरदान साबित हो रही है। कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने में यह योजना अहम साबित हो रही है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग हासिल कर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार हासिल कर युवाओं ने अपना भविष्य बेहतर बनाया है। यह सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में इस योजना का जिक्र किया है। हिमायत योजना कौशल विकास की ट्रेनिंग देने की योजना है। यह योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जम्मू कश्मीर में हिमायत मिशन मैनेजमेंट यूनिट चलाता है। जम्मू कश्मीर में वर्ष 2011 से हिमायत योजना चलाई जा रही है। डॉ. सी रंगराजन कमेटी ने वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद इस योजना को लागू किया गया। युवाओं को तीन महीने से 12 महीने की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी दिलवाई जाती है।

15 से 35 साल के युवाओं को कौशल विकास की दी जाती है निशुल्क ट्रेनिंग

नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र भी बांटे गए : कपिल

हिमायत योजना के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कपिल शर्मा का कहना है कि अधिक से अधिक युवाओं को हिमायत के तहत ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं। योजना के तहत रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र बांटे गए। जम्मू कश्मीर के 15 से 35 साल तक के युवाओं को कौशल विकास की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।

अक्टूबर में 220 उम्मीदवारों को मिली थी नौकरियां : जम्मू कश्मीर प्रशासन हिमायत योजना को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए काम कर रहा है। हिमायत मिशन के तहत 42 प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं, जिसके जरिए 68134 युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस समय 5815 युवा ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। अब तक 10 हजार से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

बिहार में मुखबिरी के आरोप में नक्सलियों ने की दो की हत्या

जासं, चानन (लखीसराय)

नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल दो गांवों में नक्सलियों ने शनिवार की पूरी रात उत्पात मचाया। गोबरदाहा एवं बासकुंड गांव में दो ग्रामीणों को घर से खींच मौत के घाट उतार दिया गया तथा कई ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर धमकी दी कि मुखबिरों का यही अंजाम होगा।

जानकारी के अनुसार नक्सलियों का एक जत्था शनिवार की रात करीब सात बजे कुंदर पंचायत क्षेत्र के गोरधोबा गांव में प्रवेश किया। एक घंटा तक गांव में उत्पात मचाने के बाद करीब आठ बजे अपने ससुराल में रह रहे जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया नौडिहा निवासी गोविंद कोड़ा के पुत्र संजय कोड़ा (30) के घर में दो नक्सली घुसे और उसे यह कहकर घर से खींचकर ले गए कि चलो, तुम्हें नेताजी बुला रहे हैं। बाद में उसका हाथ पीछे की तरफ बांध कर जंगल की ओर ले जाकर उसके सीने में दो गोली दाग कर उसकी हत्या कर दी। इसके तीन घंटे बाद भलूई पंचायत के बासकुंड गांव में मोगल कोड़ा (63) को भी तीन की संख्या में आए नक्सलियों ने घर से खींचकर दस मीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बासकुंड के पास ले जाकर उसके सिर में छह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोबरदाहा में वारदात को अंजाम देने के बाद बासकुंड आने के क्रम में नक्सलियों ने रास्ते में पड़ने वाले गांव सतघरवा, कुंदरी के ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की। रविवार की दोपहर बाद चानन थानाध्यक्ष वैभव कुमार बासकुंड एवं एसआइ राजकुमार राम ने पुलिस बल के साथ गोबरदाहा पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीसराय भेजा। बासकुंड से पुलिस ने छह खोखा एवं एक कारतूस बरामद किया है।

उधर, एएसपी (अभियान) पवन कुमार उपाध्याय ने कहा कि नक्सलियों के शिकार दोनों व्यक्ति पुलिस के मुखबिर नहीं थे। केवल दहशत बनाने के लिए नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया।

रणबीर सिंह ने कहा दुश्मन की हर हरकत का जवाब दें जवान

राज्य ब्यूरो, जम्मू: सेना की उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह सेना की अग्रिम चौकियों का दौरा कर जवानों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में वह रविवार को उत्तरी कश्मीर के बारामुला में एलओसी का दौरा किया। उन्होंने मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए अग्रिम चौकियों में तैनात जवानों, अधिकारियों को कड़ी सतर्कता से दुश्मन की नापाक इरादों को नाकाम बनाने को कहा।

उन्होंने अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे सेना के जवानों व अधिकारियों से बातचीत कर उनकी बहादुरी सराहना की। उनके साथ इस मौके पर सेना की चिनार कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों व कई फील्ड कमांडर भी मौजूद थे। आर्मी कमांडर ने उत्तरी कश्मीर में सक्रिय देशविरोधी तत्वों के खिलाफ मुहिम के दौरान स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने के लिए सैनिकों को बधाई भी दी।

सीमा पर बैट की बड़ी साजिश नाकाम, आइईडी निष्क्रिय

जागरण संवाददाता, राजौरी

केरी सेक्टर में अग्रिम चौकी के पास लगाई गई थी आइईडी

हीरानगर सेक्टर में पाक ने दागे गोले

अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने शनिवार की रात को भी पप्पू चक, करोल पंगा पोस्टों से भारतीय गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस दौरान मोर्टार के कुछ गोले खेतों में गिरे। मशीनगन से भी गोलाबारी की है, जिससे करोल माथरियां, करोल विद्दो तथा आसपास के गांवों में गोले गिरे। गोलाबारी के चलते लोग बंकरों में छिपे रहे। पिछले दो माह से हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है।

अखनूर से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा व नियंत्रण रेखा के बीच केरी सेक्टर में सीमा पार से रची गई बड़ी साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया। रविवार शाम नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में लगाई इंप्रूव्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) का समय रहते पता चल गया और जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। सेना के मुताबिक यह आइईडी पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीम (बैट) ने लगाई थी।

रविवार शाम चार बजे जवानों ने अग्रिम चौकी के पास संदिग्ध वस्तु देखी। उसी समय बम निरोधक दस्ते के जवानों और अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। जांच में यह आइईडी निकला, जो काफी नुकसान पहुंचा सकता था।

सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सरहद पर बड़े आतंकी हमले की साजिश को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार बैट ने रात को कोहरे की आड़ में भारतीय क्षेत्र में दाखिल होकर यह आइईडी लगाई होगी।

फेसबुक मैसेंजर उड़ा रहा लोगों की नींद

जागरण संवाददाता, लखनऊ: फेसबुक पर लोगों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी का खेल जोरों से चल रहा है। मैसेंजर के जरिए फेसबुक फ्रेंड से आकस्मिक आर्थिक सहायता की मांग कर ठग लोगों से मोटी रकम हड़प रहे हैं। जालसाजी का यह नया तरीका कुछ दिनों से तेजी पकड़ा है। ठग खासकर पढ़े लिखे वर्ग को निशान बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस को भी इसका हल नहीं सूझ रहा।

ठग फेसबुक पर अधिकांश सक्रिय रहने वाले लोगों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। वह सुबह पांच से आठ के बीच लोगों को मैसेंजर से मैसेज भेजते हैं ताकि जिसे मैसेज मिले उसे ऐसा लगे कि अगला किसी परेशानी में है।

पुलिस नहीं रोक पा रही जालसाजी: साइबर क्राइम सेल में पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामले तेजी से दर्ज किए जा रहे हैं। साइबर सेल की ओर से पीड़ितों के खाते का स्टेटमेंट लेकर एफआइआर दर्ज कराने की सलाह दी जाती है। हालांकि पीड़ित के एफआइआर कराने के बाद भी पुलिस इस पैटर्न पर हो रही ठगी की घटनाओं को रोकने में नाकाम है और जालसाजी का सिलसिला जारी है।

केस एक - कृष्णानगर के तिवारी पुरम निवासी विशाल की फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर जालसाजों ने उनके चिकित्सक मित्र डॉ. नीरज मिश्र को मैसेज किया कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और रुपये की सख्त दरकार है। झांसे में आकर डॉ. नीरज ने भेजे गए खाता नंबर में 40 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। यही नहीं, ठगों ने विशाल के एक अन्य मित्र से भी 25 हजार रुपये मंगा लिए। काफी देर बाद जब डॉ. नीरज ने विशाल को फोन कर हालचाल पूछा तो ठगी की जानकारी हुई।

केस दो- इंदिरानगर निवासी सौरभ चौहान को उनके मित्र अमित के फेसबुक मैसेंजर से मैसेज आया। मैसेज में कुछ रुपये की मांग की गई थी और फोन नहीं करने के लिए कहा गया था। सौरभ ने भेजे गए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद उन्होंने अमित को फोन किया तो पता चला कि उसकी फर्जी आइडी बनाकर ठगी की गई है।

पहल

कड़ाके की सर्दी में जीरो लाइन पर उत्साह से पहुंच रहे हैं सैलानी, दोनों मुल्कों के नागरिक मुस्कुराहट से देते हैं जवाब

नफरत की सीमाओं को उड़ा रही ऑक्ट्राय पोस्ट पर उमंग

लोकेश चंद्र मिश्र, जम्मू

भारत-पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव का माहौल है। सीमा पार से लगातार गोलाबारी की जा रही है। कई नागरिक चोटिल भी हुए हैं, लेकिन इस तनाव के बीच सुकून की भी खबर है। सुचेतगढ़ ऑक्ट्राय पोस्ट के जीरो लाइन पर दोनों देशों के नागरिक प्यार का पैगाम दे रहे हैं। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देते हैं। लगता है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ इस गर्मजोशी से अभी पिघल जाएगी।

ऑक्ट्राय पोस्ट पर पहुंचे पर्यटकों की आंखों में कौतूहल और चेहरे पर मुस्कुराहट से लगता ही नहीं कि दोनों देशों के बीच युद्ध के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। लोग खुशी-खुशी एक-दूसरे की तस्वीर और वीडियो मोबाइलों में कैद कर रहे हैं। शायद कसक लिए हुए कि हालात कैसे हो गए? पड़ोसी की तस्वीरें कैमरे में कैद करनी पड़ रही हैं।

दिल झकझोर देती है इंसानियत : मूल रूप से बिहार के रहने वाले रामबिहारी झा 19 साल से जम्मू में रहते हैं, लेकिन पहली बार रविवार को ऑक्ट्राय पोस्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के नाम से ही नफरत होती थी, लेकिन यहां जीरो लाइन पर पहुंचे पाकिस्तानी नागरिकों को देख कर खून खौला नहीं, बल्कि दिल को इंसानियत ने झकझोर दिया। उनके लिए यह एख अलग अनुभव था। पेशे से शिक्षक झा ने कहा कि सचमुच में सुचेतगढ़ ऑक्ट्राय पोस्ट ऐसा बार्डर टूरिज्म है, जहां पहुंच पड़ोसी के प्रति भी भाव कोमल हो जाता है। हालांकि वाघा बार्डर पर खून जोश से उबल उठता है।

उत्तर प्रदेश के मोहन सिंह जम्मू में किसी रिश्तेदार यहां आए तो ऑक्ट्राय पोस्ट देखने पहुंच गए। उन्होंने कहा, कितने प्यार से लोग एक-दूसरे को देखने आते हैं। कौन-सी ऐसी बला है कि दोनों मुल्कों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रखी है।

कभी हवाखोरी करने सियालकोट से जम्मू आते थे नागरिक : विभाजन से पहले ऑक्ट्राय पोस्ट वाली जगह से रेल लाइन गुजरती थी। सियालकोट और जम्मू के बीच ट्रेनें चलती थीं। सियालकोट के लोग हवाखोरी करने के लिए तवी और चिनाब दरिया के किनारे पहुंचते थे। बिक्रम चौक के पास रेलवे स्टेशन होता था, जहां अभी एसआरटीसी का वर्कशॉप और कला केंद्र है। बुजुर्ग उन दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं।

भारत-पाकिस्तान की सीमाओं पर भले ही तनाव हो, लेकिन आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू के आरएसपुरा स्थित ऑक्ट्राय पोस्ट पर भारत ही नहीं, पाकिस्तान के पर्यटक भी जीरो लाइन के पास पहुंचकर एक-दूसरे की ओर हाथ हिलाते है। यहां हर ओर ऐसा ही आत्मीय मिलन होता है। जागरण

सर्दी की छुट्टियों से बढ़ा बॉर्डर टूरिज्म

कड़ाके की सर्दी के कारण स्कूलों में छुट्टियां पड़ जाने से बॉर्डर टूरिज्म बढ़ रहा है। काफी संख्या में स्थानीय और दूसरे राज्यों से भी सैलानी सुचेतगढ़ ऑक्ट्राय पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। यहां से लोग घराना वेटलैंड भी जा रहे हैं। विदेशी मेहमान पक्षी को निहार रहे हैं। हालांकि रविवार को पक्षियों की संख्या काफी कम थी, लेकिन ऑक्ट्राय पोस्ट पर मेले जैसा दृश्य था।

1969 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार का गठन हुआ था। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं।

फाल्के पुरस्कार से नवाजे गए अमिताभ

सम्मान ▸ राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया अवार्ड

महानायक ने भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और जूरी के सदस्यों का जताया आभार

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंदी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन को रविवार को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। अमिताभ ने सम्मान पाने के बाद समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया।

अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान पिछले सोमवार को ही यह सम्मान लेना था। लेकिन अमिताभ ने कहा था कि खराब सेहत के चलते वह यात्रा नहीं कर सकते और दुर्भाग्य से वह सम्मान लेने के लिए वहां उपस्थित नहीं होंगे। यह पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके तहत एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपये नकद दिए जाते हैं। अमिताभ बच्चन को 2018 के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। अवॉर्ड लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें दादासाहेब पुरस्कार के योग्य समझने के लिए भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के जूरी के सदस्यों का आभार जताया। अमिताभ बच्चन ने कहा, 'ईश्वर की कृपा रही है, माता-पिता का आशीर्वाद रहा है, फिल्म उद्योग के निर्माता-निर्देशकों और सह-कलाकारों का भी साथ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह व निष्ठापूर्ण प्रोत्साहन दर्शकों का रहा है जिनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इस पुरस्कार को विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं।'

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्मों के लिए सबसे प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर जया बच्चन और अभिषेक भी उपस्थित रहे। प्रेट्र

अभी बहुत काम बाकी है : अमिताभ ने आगे कहा, 'अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जब मुझे यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई तो मन में संदेह उठा कि क्या कहीं ये मेरे लिए संकेत है कि भाई साहब आपने बहुत काम कर लिया अब आप घर बैठिए। लेकिन अभी बहुत काम बाकी है जिसे पूरा करना है और आगे ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी बात होगी होगी।'

1969 में 'सात हिंदुस्तानी' से शुरू हुआ फिल्मी सफर : अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में पांच दशक से सक्रिय हैं। उनका फिल्मी करियर 1969 में 'सात हिंदुस्तानी' के साथ शुरू हुआ था। दिलचस्प है कि उसी साल यानी 1969 में ही दादासाहेब फाल्के पुरस्कार का गठन हुआ था। अमिताभ ने लगातार काम किया और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। फिल्म जगत में दिए गए योगदान के लिए ही उन्हें दादासाहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया।

1973 में जंजीर से मिली सफलता : अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करना पड़ा था। मगर साल 1973 में जंजीर फिल्म उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। फिल्म से उनकी इमेज इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रूप में स्थापित हुई। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

अब तक मिले हैं कई पुरस्कार : मेगा स्टार और बिग बी के नाम से भी जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन को अब तक चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए अमिताभ को साल 1984 में 'पद्म श्री', 2001 में 'पद्म भूषण' और 2015 में 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था। एक समय था जब उनका फिल्मी करियर खत्म मान लिया गया था। दूसरी दौर में उन्होंने 'ब्लैक' और 'पा' जैसी प्रयोगधर्मी फिल्में कीं।

टीवी के शो ने संभाला : अमिताभ के करियर में एक समय ऐसा भी आया था, जब वह आर्थिक परेशानियों से घिर गए थे। उसी दौरान वो साल 2000 से टीवी पर प्रसारित होने वाले गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट बने। उसके बाद तो उन्होंने टीवी पर कामयाबी का नया इतिहास रचा।

पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

▸ कर्नाटक सरकार ने की तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा

▸ अष्ट मठों के सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे विश्वेश तीर्थ

उडुपी, प्रेट्र : दक्षिण भारत के प्रमुख धर्मगुरुओं में एक पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी का संक्षिप्त बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। 88 वर्षीय स्वामीजी रामजन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। कर्नाटक सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

द्वैतवाद के दार्शनिक मध्वाचार्य द्वारा 800 साल पहले स्थापित अष्ट मठों के विश्वेश तीर्थ सबसे वरिष्ठ धर्मगुरु थे। 19 दिसंबर को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद उनको मणिपाल के केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पेजावर मठ लाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वामीजी के पार्थिव शरीर को यहां से 800 साल पुराने उडुपी श्रीकृष्ण मठ ले जाया गया और माधव सरोवर में स्नान कराया गया। इसके बाद एक खुली जीप में उनके पार्थिव शरीर को गोविंद, गोविंद के उच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए अजरजाद स्टेडियम ले जाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पेजावर मठ के प्रमुख स्वामी विश्वेश तीर्थ की फाइल फोटो। एनएनआइ

कई मंत्री और मुख्यमंत्री समेत हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

बेंगलुरु, प्रेट्र : पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामीजी को नेशनल कॉलेज मैदान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया, उपमुख्यमंत्री गोविंद करजोल और राजस्व मंत्री आर अशोक ने भी श्रद्धांजलि दी। स्वामीजी के पार्थिव शरीर को विशेष हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज मैदान लाया गया। राज्य के सुत्तूर मठ के शिवरात्रि देशिकेंद्र स्वामीजी, श्रवण बेलगोला जैन मठ के चारुकीर्ति भट्टारक स्वामीजी समेत कई प्रमुख मठों के संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

श्री विश्वेश तीर्थ स्वामीजी लाखों लोगों के मन में बने रहेंगे, जिनके लिए वे हमेशा पथ प्रदर्शक थे। सेवा और आध्यात्मिकता के वे पावर हाउस थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। ओम शांति।
–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

छात्रा से छेड़छाड़ में आइआइटी प्रोफेसर को जबरन सेवानिवृत्ति

जागरण संवाददाता, कानपुर : आइआइटी कानपुर में तीन महीने पहले विदेशी छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर आशु जैन को जबरन सेवानिवृत्त किया जाएगा। शनिवार को आइआइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। तीन महीने चली जांच में प्रोफेसर, कर्मचारी व छात्र-छात्राओं से पूछताछ के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फैसले के बाद दोषी प्रोफेसर को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया भी आइआइटी प्रशासन ने शुरू कर दी है। आइआइटी के इतिहास में किसी प्रोफेसर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई का यह पहला मामला होगा।

आइआइटी में फ्रांस की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सितंबर में हुआ था। शिकायत के बाद भी आइआइटी प्रशासन उसे सप्ताहभर तक दबाने में लगा रहा। इस चुप्पी पर छात्रा ने संस्थान के वूमेन सेल और फ्रांसीसी दूतावास में शिकायत की। दूतावास के दबाव बनाने पर आइआइटी ने मामले की जांच शुरू कर दी। दूतावास के अफसरों ने भी आइआइटी प्रशासन से पूछताछ की थी। तीन महीने तक विदेशी छात्र-छात्राओं के अलावा प्रोफेसर व कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कई बार अलग-अलग जांच समितियों ने रिपोर्ट दी, जिसका विश्लेषण करने के बाद आखिरकार 28 दिसंबर को हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में प्रोफेसर को दोषी माना गया और जबरन सेवानिवृत्ति का फैसला सुनाया गया।

आइआइटी के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जबरन सेवानिवृत्ति को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, हालांकि उन्होंने इसकी आधिकारिक पुष्टि करने से मना कर दिया। इस मामले में कई बार निदेशक को फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पहले मामले को दबाने वाला आइआइटी प्रशासन फैसले के बाद भी किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी देने से बच रहा है।

रवीना टंडन, भारती सिंह व फराह खान पर एक और केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर

▸ टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को किया था आहत

▸ अमृतसर के अजनाला थाने में भी तीनों के खिलाफ हो चुका है केस दर्ज

टीवी शो के दौरान ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन, निर्देशक व कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह पर पंजाब पुलिस ने एक और केस दर्ज किया है। यह केस फिरोजपुर कैंट थाने में दर्ज किया गया है। इससे पहले अमृतसर के अजनाला थाने में भी केस दर्ज हो चुका है।

फिरोजपुर शहर के कंबोज नगर निवासी विजय गोरिया ने पुलिस को सौंपी शिकायत में आरोप लगाया कि टीवी शो में फराह खान ने पवित्र बाइबल के शब्द हलेलूयाह बोला और इसे ब्लैकबोर्ड पर लिखा। कॉमेडियन भारती सिंह और अभिनेत्री रवीना टंडन से इस शब्द का मतलब बताने को कहा। भारती व रवीना ने इस शब्द के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर मजाक उड़ाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि पवित्र शब्द के बारे में गलत टिप्पणियां करना शर्मनाक है। किसी विशेष समुदाय के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जांच अधिकारी एएसआइ बलविंदर सिंह का कहना है कि शिकायत पर फराह खान, भारती सिंह और रवीना टंडन के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया गया है। वहीं, ईसाई भाईचारे ने रविवार को अमृतसर के सेंट मैरी चर्च के बाहर भारती सिंह, रवीना टंडन व फराह खान के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और तीनों के पुतले फूंके। इस दौरान डॉ. सुभाष थोबा ने कहा कि तीनों ने जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं अटारी में भी तीनों के खिलाफ रोष जताया गया। तरनतारन में भी ईसाई समुदाय ने रोष प्रदर्शन किया और धरना देकर नारेबाजी की।

अमृतसर के सेंट मैरी चर्च के बाहर पुतला फूंकते ईसाई समुदाय के लोग। जागरण

राम मंदिर मॉडल में संशोधन के दावे को विहिप ने किया खारिज

जागरण संवाददाता, अयोध्या : विहिप ने राममंदिर मॉडल में संशोधन के दावे को खारिज किया है। विहिप के केंद्रीय सलाहकार पुरुषोत्तम नारायण सिंह एवं प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि इस दिशा में कोई भी निर्णय रामजन्मभूमि न्यास की बैठक के बाद ही लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, जिन कार्यशाला अधीक्षक के हवाले से यह बयान जारी किया गया है, वे अधिकृत नहीं हैं और इस तरह का बयान देने का हक न्यास अध्यक्ष और मंत्री के साथ विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों को ही है। सोशल मीडिया को दिए बयान में मंदिर निर्माण कार्यशाला के अधीक्षक अन्नू भाई सोमपुरा ने बताया था कि राममंदिर मॉडल के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का नया नक्शा तैयार किया है, जिसमें पुराने मॉडल को विस्तार दिया गया है। इसके मुताबिक प्रस्तावित मंदिर में एक मंडप तथा एक मंजिल की और शिखर में भी 33 फीट की वृद्धि संभावित है। फिलहाल रामजन्मभूमि न्यास की ओर से प्रस्तावित जिस मंदिर के लिए गत तीन दशक से पत्थरों की तराशी चल रही है, वह 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा एवं 128 फीट ऊंचा है। नृत्यमंडप, रंगमंडप, गर्भगृह के रूप में पांच प्रखंड हैं। वह दो मंजिल का है। कथित संशोधन के बाद मंदिर तीन मंजिल का, छह प्रखंड वाला और 161 फीट ऊंचा होगा।

पीएफ के 97 करोड़ रुपये जमा न करने पर एचईसी के बैंक खाते फ्रीज

मधुरेश नारायण, रांची

▸ नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर ईपीएफओ ने की कड़ी कार्रवाई

▸ बैंक खाते जब्त करने पर भी कंपनी से वसूली नहीं होने पर एचईसी की संपत्ति बेची भी जा सकती है

हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) ने 97 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने पर एचईसी के सात बैंक खाते सीज कर दिए हैं। ईपीएफओ के अधिकारी के अनुसार, नवंबर के आखिरी सप्ताह में एचईसी को वर्षों पुराने बकाये के भुगतान के लिए नोटिस दिया गया था। इसमें साफ-साफ कहा गया था कि अगर कंपनी भविष्य निधि के पैसे का भुगतान नहीं करती है तो एचईसी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। वहीं, एचईसी की निदेशक (वित्त) अरुंधति पांडा ने कहा है कि ईपीएफओ ने नवंबर में जो नोटिस दिया था उसका जवाब देने की तैयारी प्रबंधन की ओर से की जा रही है। पांडा वर्तमान में एचईसी की सीपीएफ ट्रस्टी हैं।

भुगतान नहीं तो संपत्ति बेच कर जुटाई जाएगी राशि : ईपीएफओ के अनुसार, अगर बैंक खाते जब्त करने के बाद भी देय राशि कंपनी से वसूल नहीं हो पाती है तो वो एचईसी की संपत्ति को जब्त कर बेच सकती है। इधर, कंपनी की आर्थिक हालत काफी नाजुक है। ऐसे में कंपनी के लिए 97 करोड़ का भुगतान करना बहुत मुश्किल है।

क्या है मामला : एचईसी की ओर से कर्मियों का पीएफ वर्ष 1976 से लेकर 1999 तक निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया था। इसके भुगतान के लिए ईपीएफओ ने वर्ष 2003 में एचईसी को नोटिस दिया था। तब कंपनी ने घाटे में होने की बात कही और पैसे देने में असमर्थता जाहिर की थी। वर्ष 2007 में कंपनी ने केंद्र सरकार से मिले पुनरुद्धार पैकेज से बकाया और ब्याज की राशि का कुछ पैसे का भुगतान किया था। इसके बाद भी ईपीएफओ के 97 करोड़ रुपये बाकी रह गए। मामला हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर स्टे लगा दिया। बाद में ईपीएफओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (स्पेशल लीव पीटिशन) दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया जिसके बाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 के पहले हफ्ते में एचईसी की आपत्ति को मेरिट पर नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

रांची के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2 विकास आनंद ने इस बारे में बात करने पर कहा, नवंबर के अंतिम सप्ताह में एचईसी को 15 दिन के अंदर बकाया पैसे जमा करने को लेकर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन एचईसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एचईसी के सात बैंक खाते अटैच किए गए हैं। अगर इन खातों के माध्यम से रिकवरी नहीं होती है तो एचईसी के अन्य स्रोतों से रिकवरी की जाएगी।

सुरक्षा

आतंकियों की घुसपैठ रोकने के साथ विस्फोटक सामग्री को भी खोज रहे सेना के कुत्ते, प्राकृतिक आपदा के बारे में जवानों को पहले से सचेत करने में भी निभा रहे भूमिका

एलओसी पर दुश्मनों को पस्त कर रहा श्वान दस्ता

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सेना के श्वान दस्ते के सदस्य कश्मीर में बर्फ से घिरी नियंत्रण रेखा पर जवानों के साथ कदम मिलाते हुए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। विपरीत हालात में भी सेना के ये कुत्ते आतंकियों की घुसपैठ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये खामोश प्रहरी सरहद पर हर आफत का सामना करते हुए जवानों को सचेत भी कर रहे हैं।

उत्तरी कश्मीर में सेना के श्वान दस्ते के सदस्य बूजो किसी हीरो से कम नहीं है। बूजो ने गत दिनों क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। बूजो के साथ सेना के श्वान दस्ते के रोमा, डेविल भी अग्रिम चौकियों पर डेरा डालने वाले ऐसे कुत्ते हैं जो बर्फ की आड़ में घुसने वाले दुश्मन की दूर से पहचान कर सैनिकों को सचेत कर देते हैं।

डेढ़ सौ से अधिक हैं प्रशिक्षित कुत्ते : नियंत्रण रेखा की सुरक्षा को पुख्ता करने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सेना के श्वान दस्ते में 150 से अधिक प्रशिक्षित कुत्ते हैं। वे दुश्मन पर हमला कर उसे काबू में करने, दुश्मन को ट्रैक करने व विस्फोटक, अन्य संदिग्ध वस्तुओं को तलाशने में विशेष भूमिका निभाते हैं। इनमें अधिकतर डबल फर वाले जर्मन शैफर्ड नस्ल के कुत्ते हैं। ये अग्रिम इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं।

लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते भी कमाल के : लैब्राडोर नस्ल के कुत्ते पिछले इलाकों में आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सक्रिय हैं। वे दुश्मन को ट्रैक करने व विस्फोटक, अन्य संदिग्ध वस्तुओं को खोज निकालने में महारत रखते हैं। एलओसी पर उनकी सूचना को पूरी गंभीरता से लेते हुए सेना के जवान कार्रवाई करते हैं।

मीना ने नाकाम की थी पुलवामा दोहराने की साजिश : इस वर्ष कश्मीर में पुलवामा दोहराने के लिए आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश साजिश को सेना की लैब्राडोर मीना ने नाकाम बनाया था। आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर में हाईवे पर 25 किलो आइईडी लगाई थी। मीना ने इसे तलाश लिया। इससे एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई।

रोमा ने हिमस्खलन से बचाया सैनिकों को : सेना के श्वान दस्ते की रोमा ने हिमस्खलन होने से पहले ही कश्मीर में सैनिकों को सतर्क कर दिया। रोमा के संकेतों को गंभीरता से लेते हुए सैनिक अस्थायी आश्रय स्थल से हट गए थे।

मानसी की शहादत रहेगी याद : सेना श्वान दस्ते की सदस्य मानसी की शहादत को हमेशा याद करती है। चार साल की लैब्राडोर को बहादुरी के लिए मेंशन इन डिस्पैच सर्टिफिकेट मिला था। उसका नाम भारत के गैजेट में आएगा।

जेम ने खोजा निकाला था आतंकवादी

सेना के श्वान दस्ते के सदस्य जेम ने उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़ स्थल से भाग निकले आतंकवादी को तलाश लिया था। मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मार गिराए गए थे। तीसरा भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद जेम ने उस मकान को तलाश लिया, जहां तीसरा आतंकी छिपा था। इसके बाद तीसरे आतंकी को भी मार गिराया गया।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
... 20,13,441.37/- ...
अचल संपत्ति का विवरण
...
दिनांक: 26.12.2019
स्थान: गाजियाबाद
श्री जयंत कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
...
अचल संपत्ति का विवरण
...
दिनांक: 26.12.2019
स्थान: गाजियाबाद
श्री जयंत कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: बी-6, गामा शॉपिंग काम्प्लेक्स, ब्लॉक ई, गामा-1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201308
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)
...
अचल संपत्ति का विवरण
...
दिनांक: 26.12.2019
स्थान: गाजियाबाद
श्री जयंत कुमार गुप्ता, मुख्य प्रबंधक
अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 30 दिसंबर 2019

दैनिक जागरण

जीवन में रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन रिश्तों में जीवन हो

युवाओं की भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में जो कुछ कहा उससे और खासकर इस बात से असहमत नहीं हुआ जा सकता कि आज के युवा सिस्टम को पसंद करते हैं और वे न केवल उसका पालन करते हैं, बल्कि यदि सिस्टम ढंग से काम न करे तो सवाल भी करते हैं। वास्तव में हम सब भारत की उस युवा पीढ़ी का उभार देख भी सकते हैं जो न केवल नियम-कायदों के हिसाब से चलना पसंद कर रही है, बल्कि यह भी चाह रही है कि अन्य सभी ऐसा करें। किसी भी देश की ऐसी युवा पीढ़ी व्यवस्था को बदलने के साथ ही उस माहौल का निर्माण करने में भी सहायक बनती है, जो पुराने ढर्रे को बदलने के लिए आवश्यक होता है। विडंबना यह है कि कुछ लोग और खासकर नेताओं का एक वर्ग अभी भी पुराने ढर्रे पर चलना पसंद कर रहा है। यही कारण है कि व्यवस्था में बदलाव और सुधार की कोशिशों का विरोध होते हुए दिखता है। यह विरोध वे लोग करते हैं जो भाई-भतीजावाद, परिवारवाद और अपारदर्शी व्यवस्था के पोषक हैं। इनका बस चले तो वे शायद कोटा-परमिट वाली व्यवस्था को फिर से लागू करने की वकालत करने लगें। सच तो यह है दबे-छिपे स्वरों में यह वकालत होती भी है।

प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि आने वाले दशक को गति देने में वे लोग ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। इससे इन्कार नहीं कि बीते वर्षों में व्यवस्था के स्तर पर काफी कुछ बदला है, लेकिन यह भी सही है कि अभी बहुत कुछ बदले जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति में सजग और अनुशासनप्रिय युवाओं की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। संभवतः उनकी इसी भूमिका को रेखांकित करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश के युवाओं को अराजकता, अव्यवस्था आदि से चिढ़ है और वे परिवारवाद, जातिवाद को पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री ने यह बात हाल के दिनों में नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों का उल्लेख किए बगैर कही। इसके पीछे उनका मंतव्य कुछ भी हो, न तो इस हिंसा की अनदेखी की जा सकती है और न ही इसकी कि युवाओं को किस तरह भड़काकर सड़कों पर उतारा गया। सबसे खराब बात यह रही कि इस दौरान संसद से पारित कानून को सड़क पर खारिज करने की जिद की गई। इसका सीधा मतलब है कि युवाओं को अराजकता से दूर रहने के साथ ही उन शक्तियों से सतर्क रहने की भी जरूरत है जो उन्हें गुमराह करती हैं। ध्यान रहे कि इसी की जरूरत चंद दिन पहले सेना प्रमुख ने भी जताई थी।

शिक्षक सिर्फ पढ़ाएं

बिहार के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील के लिए इंतजाम करना, रोज बच्चों की गिनती कर उतना खाना तैयार करवाना, सुरक्षित ढंग से बच्चों को खिलाना और फिर हर चीज का हिसाब रखना...। स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रभारी शिक्षक की यह रोज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें गड़बड़ी भी होती है। अक्सर मध्याह्न भोजन को लेकर गड़बड़ी, हंगामा या दुर्घटना की खबरें आती हैं। अब सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि शिक्षकों के जिम्मे मध्याह्न भोजन का काम नहीं रहेगा। सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की ही जवाबदेही रहेगी। शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि मिड डे मील से शिक्षकों को मुक्त करने पर स्कूली शिक्षा में सुधार लाने की गति और तेज होगी। केंद्र ने इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। कई अन्य राज्य भी यही चाहते हैं। दरअसल स्कूली शिक्षा को लेकर कई सर्वे आए हैं। उनके नतीजे स्कूली शिक्षा की गड़बड़ी को दिखाते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। योग्य शिक्षकों का अभाव भी है। नियोजन या पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहाली की गई, ताकि इस कमी को दूर किया जा सके, लेकिन बहाली की प्रक्रिया और अधिसंख्य शिक्षकों की योग्यता हमेशा सवालों के घेरे में रही। शिक्षा का अधिकार कानून में तय अनुपात के तहत 25 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। विभिन्न विद्यालयों से सूचनाएं आती हैं कि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा शिक्षकों के जिम्मे और भी कई कार्य हैं। छात्रवृत्ति, पोशाक योजना, साइकिल योजना के स्कूल से जुड़े तमाम कार्य भी शिक्षकों को करने पड़ते हैं। प्रधानाचार्य स्कूल भवन की मरम्मत, रंगाई और नए भवन के निर्माण संबंधित कार्य भी देखते हैं। शिक्षक अगर ऐसे कार्य करेंगे, तो पढ़ाएंगे कैसे? वैसे भी शिक्षक तो पठन-पाठन का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। भोजन से लेकर भवन तक के कुछ कार्य उनके जिम्मे दिए जाएंगे, तो वह कुशलतापूर्वक कर पाएंगे कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। होना यह चाहिए कि स्कूलों में योग्य शिक्षक बहाल हों और वह सिर्फ पठन-पाठन से जुड़े कार्य करें। अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए सरकार स्कूल स्तर पर प्रबंधक नियुक्त कर सकती है। इससे शिक्षकों का बोझ घटेगा और स्कूल संचालन की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।

शिक्षकों के जिम्मे पढ़ाने के अलावा अन्य कई कार्य रहते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन पढ़ाई के रास्ते में बड़ी रुकावट है। इससे छुटकारा मिलने से पढ़ाई की स्थिति सुधर जाएगी। इससे शिक्षकों का बोझ घटेगा और स्कूल संचालन की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।

संवैधानिक मूल्यों को बचाने का समय

पी चिदंबरम

एनआरसी–सीएए–एनपीआर की कवायद संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यही वजह है कि तमाम लोग विशेषकर छात्र इनका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं

पहले कार्यकाल में तमाम नाकामियों के बावजूद मोदी सरकार इस साल और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। ऐसे में उसके शासन में देश के सूरतेहाल की पड़ताल करना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो आर्थिक मोर्चे की चर्चा आवश्यक होगी जहां रोजाना बुरी खबरों की भरमार दिखती है। विनिर्माण उत्पादन 3.8 प्रतिशत तक सिकुड़ गया, निर्यात पस्त है, आयात सुस्त है, कर्ज की वृद्धि मंद है और निवेश में गिरावट का रुख है। वहीं महंगाई लगातार बढ़ने पर है। मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने मौजूदा आर्थिक सुस्ती को असाधारण बताया है। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था आइसीयू में जाने के कगार पर है।

वहीं राजव्यवस्था की बात करें तो दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने उन मोर्चों पर ही कदम उठाया जिनका आम आदमी से कोई खास सरोकार नहीं था, मगर ये मुद्दे दक्षिणपंथी राजनीति के अगुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। इनमें तत्काल तीन तलाक कानून, असम से शुरू हुई एनआरसी की कवायद, अनुच्छेद 370 की समाप्ति एवं जम्मू-कश्मीर का विभाजन और जल्दबाजी में पारित कराए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके चलते आज भारतीय राजनीतिक परिदृश्य साल भर पहले की तुलना में अधिक विखंडित और अस्थिर हो गया है। सामाजिक सौहार्द एवं शांति को भी गहरा आघात पहुंचा। रोजाना हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। चिंतित करने वाली बात यही है कि पूरी दुनिया ने अब इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने भी आईना दिखाने से परहेज नहीं किया।

मोदी सरकार के दौरान संस्थानों का पराभव भी देखने को मिला है। तमाम संस्थान अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संस्थान सबसे आगे हैं। सूचना आयोग भी अपने अर्थ खोता जा रहा है। तमाम अन्य संस्थाएं भी सिर्फ सरकार की खुशामद में लगी हैं। फिर भी ऐसे स्याह दौर में कुछ अपवाद जरूर हैं। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भी मोदी सरकार के दौर में कोई बहुत अच्छी नहीं है। आए दिन देश के तमाम हिस्सों से भयावह आपराधिक मामलों की खबरें आती रहती हैं। तिस पर कुछ हिंसक मामलों पर सत्तासीनों की चुप्पी और सालती है।

इन सबसे इतर एक हालिया मुद्दे की पड़ताल बहुत जरूरी होगी और वह मुद्दा है एनआरसी, सीएए एवं उनके परिणामों का। इसमें सबसे पहले तो यही देखना होगा कि अगर सीएए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी के साथ लागू किया तब क्या होगा? सीएए में 31 दिसंबर, 2014 की मियाद तय की गई है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह धार्मिक समूहों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों को शामिल किया गया है। वास्तव में यह पक्षपातपूर्ण एवं असंवैधानिक है। आखिर इसमें इन तीन देशों को ही क्यों शामिल किया गया और श्रीलंका, म्यांमार, भूटान को क्यों छोड़ा गया? फिर इन तीन देशों के मुस्लिम नागरिकों को बाहर क्यों रखा गया? दक्षिण एशिया के सर्वाधिक प्रताड़ित अल्पसंख्यकों में श्रीलंका के तमिल सबसे ऊपर आएंगे जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। म्यांमार के रोहिंग्या, पाक के अहमदिया, शिया, बलूची और सिंधी के अलावा भूटान के ईसाइयों की स्थिति भी ऐसी ही है। सीएए में उन्हें क्यों छोड़ा गया? सीएए के पक्षपातपूर्ण प्रावधान को ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन देशों के हिंदुओं को तो भारत में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन श्रीलंकाई तमिल हिंदुओं को नहीं। इसी तरह भूटान के ईसाई भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों? चयन का ऐसा पैमाना समझ से परे है।

सीएए में यह भी स्पष्ट नहीं कि अवैध नागरिक माने जाने वालों का क्या होगा? उन्हें कैंपों में भेजे जाने की चर्चा है। असम के ग्वालपाड़ा जिले में 46 करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसे कैंप का निर्माण हो रहा है जिसमें 3,000 लोग रखे जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं। जैसे इसमें यदि लाखों लोग चिन्हित हुए तब ऐसे कितने कैंप बनाए जाएंगे? सरकार उनके निर्माण के लिए संसाधन कहां से लाएगी? क्या अवैध आव्रजक जीवनपर्यंत इन कैंपों में रहेंगे? भारत में जन्मे उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें भी कैंपों में रखा जाएगा? ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिले।

एनआरसी भारत को विभाजित करने वाली भयावह और शातिर योजना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के सुबूत देने होंगे। उदार लोकतंत्रों में यही व्यवस्था है कि नागरिकता पर संदेह की स्थिति में उसकी जांच राज्य का दायित्व है। इसके उलट एनआरसी में यह संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। यदि यह दुराग्रही पैमाना असम में लागू हो तो वहां 19,06,657 लोग अवैध आव्रजक माने गए। उनमें से अधिकांश बेहद गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं। कोई नहीं जानता कि उनका क्या भविष्य होगा।

बहरहाल एनआरसी और सीएए की जुगलबंदी से सबसे ज्यादा भारतीय मुसलमान प्रभावित होंगे। बाकी धार्मिक समूह अगर एनआरसी के तहत बाहर हो जाएंगे तो उन्हें सीएए के जरिये जोड़ लिया जाएगा। इसकी गाज केवल मुस्लिमों पर गिरेगी जो अगर एनआरसी में अवैध आव्रजक पाए गए तो उन्हें सीएए का सहारा भी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि भारतीय मुसलमानों में इसे लेकर इतने भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

इस पर हुए व्यापक विरोध-प्रदर्शन ने सरकार को फिलहाल कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया जबकि गृहमंत्री और अन्य मंत्री अतीत में इसकी ताल ठोंकते आए हैं। ऐसे में सरकार अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर लेकर आ रही है जिसे 2010 में हुई जनगणना से जोड़ने का प्रयास भी किया। वैसे 2010 के एनपीआर और 2020 के एनपीआर में जमीन-आसमान का अंतर है। एनपीआर 2010 चुनिंदा राज्यों में ही कराया गया था जिसमें न तो कहीं कोई विवाद हुआ और न ही असम जैसा कोई विषम अनुभव। उसमें सीएए जैसी कोई आशंका भी नहीं थी। साथ ही एनपीआर 2010 में केवल 15 क्षेत्रों के आंकड़ों को शामिल किया गया था। इसके उलट एनपीआर 2020 पूरे देश में कराया जाएगा। यह असम एनआरसी और सीएए के अनर्थकारी अनुभव की पृष्ठभूमि के साथ संपन्न होगा। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में भी तमाम अन्य सूचनाएं मांगी जाएंगी जिनका जनगणना से कोई लेनादेना नहीं होगा। यह एक तरह से एनआरसी जैसी कवायद होगी जिसका पुरजोर विरोध बेहद जरूरी है।

एनआरसी-सीएए-एनपीआर की कवायद असल में आरएसएस-भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के उपकरण हैं। भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक देशभक्त भारतीय का दायित्व है कि वह हिंदू राष्ट्र की घातक अवधारणा का विरोध करे। यही वजह है कि भारतीयता के विचार और संविधान की रक्षा के लिए तमाम लोग विशेषकर छात्र सड़कों पर विरोध के लिए उतरे हैं।

(लेखक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

response@jagran.com

सामाजिक तानेबाने पर प्रहार का प्रयास

हरदीप एस पुरी

कुछ लोग नागरिकता कानून की आड़ में दुष्प्रचार से भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने की जुगत में लगे हैं

पिछले कई दिनों से विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून, 2019 यानी सीएए को लेकर सरकार विरोधी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कानून के बारे में लोगों को जानबूझकर गलत जानकारी देने, उन्हें डराने, उनकी भावनाएं भड़काने और देशहित के विरुद्ध उकसाने तथा हिंसा भड़काने का काम किया। झूठा प्रचार करते हुए इन लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों के गांधीवादी सिद्धांतों के विपरीत पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, आगजनी और पुलिस बलों पर हमला करने के प्रयास किए। इनमें से कुछ तो विदेशी हस्तक्षेप की हिमायत करने की सीमा तक भी चले गए।

हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों सीएए पर सरकार के रुख के बारे में लोगों विशेषकर युवाओं की गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी तरीके से सभी बातों को समझाया। इसके बाद से देश भर में लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित विपक्षी सक्रियता और देश-विदेश में उनके द्वारा किए जा रहे भ्रामक प्रचार के बावजूद भी शांतिपूर्ण रैलियों के माध्यम से सीएए की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है।

दरअसल सीएए लगभग सात हजार साल पुरानी विविध और समावेशी भारतीय सभ्यता की पुष्टि करता है। संवैधानिक गणराज्य के रूप में हमारे आधुनिक राष्ट्र का अस्तित्व हमारे इतिहास के केवल एक प्रतिशत हिस्से को ही दर्शाता है। हमारी सभ्यता की विरासत का समावेशी चरित्र इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि मालाबार के यहूदी, सीरिया के ईसाई, पूर्ववर्ती फारस के पारसी या मेरे माता-पिता जो विभाजन की हिंसा के दौरान देश छोड़कर चले गए थे, सभी को हमारे देश में सुरक्षित स्थान मिला है। सीएए हमारी सभ्यता से जुड़े मूल्यों की निरंतरता है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक सच्चाई है। वहां इन तबके के लोगों को सिर्फ इसलिए तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि वे अपने धर्म का पालन करना चाहते थे। सीएए वहां से पलायन कर भारत आने वाले ऐसे सभी पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

सीएए में जिन चीजों का प्रावधान नहीं है, वे भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, जातीयता या नस्ल के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को न तो चुनौती देता है और न ही इसमें कोई बदलाव करता है। अधिनियम के संबंध में यह दुष्प्रचार कि भारतीय मुसलमानों को खतरा है, अज्ञानता से भरा और उनके साथ छल करने के समान है। इसे लेकर धार्मिक आधार पर नागरिकों के मन में डर पैदा करना और युवाओं को भड़काना राजनीति का सबसे निचला स्तर है, जो ब्रिटिश राज की याद दिलाता है।

सीएए भारत के तीन पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए देश की नागरिकता प्रदान करने का 'खुला निमंत्रण' भी नहीं है, जैसा कि विपक्षी दल दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह केवल उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा, जो 31 दिसंबर, 2014 की निर्धारित तिथि के पहले से भारत में हैं, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। यह नई दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के समान है।

सीएए में एक समुदाय विशेष को शामिल नहीं किए जाने के बारे में भी जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। यह कहा जा रहा है कि यह इन तीनों देशों में उत्पीड़न का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी) के लिए ही है। यह भी झूठ है। दरअसल ये देश इस्लामी गणराज्य हैं। इसलिए इस्लामिक देशों में धार्मिक आधार पर मुस्लिम उत्पीड़न का सवाल नहीं उठना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मुसलमान इन देशों में अन्य कारणों से प्रताड़ित किए जाते हैं, वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वास्तव में पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार ने इन देशों के ही 600 मुसलमानों को नागरिकता प्रदान की है। इसलिए सीएए पर विपक्ष का यह प्रचार कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है तथा भारत की धर्मनिरपेक्ष साख को खोखला करता है, सरासर झूठा है।

सीएए के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देने का प्रयास भी किया गया है। अनुच्छेद 14 का व्यापक अध्ययन यह बताता है कि सीएए जैसे अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसमें उचित वर्गीकरण का प्रावधान किया गया है। इस कानून को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के शिकार हुए लोगों को उनका अधिकार देता है। आधुनिक भारत में तिब्बत, श्रीलंका, युगांडा या बांग्लादेश के सभी शरणार्थियों को शरण दी गई है। सीएए मानवाधिकारों के प्रति इस प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं करता, बल्कि यह भारत की ओर से मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की पुष्टि करता है। सीएए को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के साथ जोड़ने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि सरकार ने एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केवल असम तक ही सीमित है। सीएए और एनआरसी के बीच रहस्यमय जुड़ाव के पीछे कांग्रेस और उसके तथाकथित 'धर्मनिरपेक्ष सहयोगी दलों' की वोट बैंक की मानसिकता है। वोट बैंक की इस राजनीति को लोगों ने सबसे पहले 2014 में नकारा और 2019 में इसकी और बुरी पराजय हुई।

स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन में कहा था कि 'मुझे ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है, जिसने सभी धर्मों और दुनिया के सभी देशों के शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है।' मोदी सरकार ने भारत की इसी विरासत पर आधारित कानून बनाया है। सीएए देश में पहले से ही रहने वाले लोगों की सुरक्षा की पुनःपुष्टि करता है। झूठे प्रचारों से प्रभावित हो कुछ लोग भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीयों की जिम्मेदारी है कि इन ाक्तियों को नकारें और अपनी विरासत के मूल्यों को सहेज कर रखें।

(लेखक केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वयं को देखें

व्यक्ति को व्यथित एवं बेचैन करने वाली मनोवृत्ति अभावरूप में नहीं, भावरूप है। भाव की उत्तेजित अवस्था प्रायः इसलिए होती है कि अन्य लोग क्यों इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? जबकि वह वस्तु उसके पास नहीं है। प्रायः मनुष्य इसलिए दुखी नहीं रहता कि उसके पास भवन, वस्त्र एवं सुविधायुक्त वस्तुएं क्यों नहीं हैं? दूसरों के पास ऐसी वस्तुएं क्यों उपलब्ध हैं, इस तथ्य से व्यक्ति अधिक परेशान रहता है। कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति अधिक विकसित होती है। किसी को नया वस्त्र, आभूषण चाहिए। ऐसी अनेकानेक बातें निरंतर उसके मन में अशांति उत्पन्न किए रहती हैं।

मेरे एक रिश्तेदार के यहां एक शिक्षित महिला आई। रिश्तेदार की पत्नी अशिक्षित थी। उसके पास कोई ऊंचा विषय बात करने के लिए नहीं था। वह बोली, 'आपके हाथ खाली हैं? चूड़ियां क्यों नहीं पहनतीं? मेरी चूड़ियां छह तोले की हैं, सुंदर लगती हैं ना?' सुशिक्षित महिला बोली, 'आजकल इन चूड़ियों का प्रचलन नहीं है। मेरी घड़ी दो सौ पैंतीस रुपये की है, समय सही देती है, देखो! कितनी अच्छी है?' धनी महिला के मन में बात बैठ गई। शिक्षित महिला के हाथ घड़ी और वह बिना घड़ी। दूसरे ही दिन उससे भी अच्छी घड़ी उसके हाथ में थी। समय देखना तो आता नहीं था। फिर भी अति प्रसन्न थी। उसका अहं शांत हो चुका था। 'दूसरों से अच्छे रहें'-यह भाव मनुष्य की अशांति, आंतरिक दुख और ईर्ष्या का कारण होता है। मन बेचैन रहता है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अतृप्त रहता है। ईर्ष्या एक छूत से फैलने वाले रोग के सदृश शीघ्र ही विकसित होने वाला मनोभाव है।

याद रखिए, आप चाहे सब कुछ पा लें, परंतु फिर भी किसी-न-किसी वस्तु का अभाव सदा बना ही रहता है। अभाव मानव-मस्तिष्क की प्रबलतम कमजोरी है। उत्तम मनुष्य वही है, जो कल्पना के मायाजाल एवं ईर्ष्या जैसे मनोविकार के वश में न होकर अपनी प्राप्त वस्तुओं का ही सबसे उत्तम उपयोग करता है। स्वयं में काने बनकर दूसरे को अंधा देखना अनर्थकारी है। अपने साथ भी ईमानदारी से कार्य कीजिए। अपनी ओर भी निहारिए।

डॉ. विजय प्रकाश त्रिपाठी

बच्चों की सेहत का सवाल

अनीश कुमार

खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर देश में एक मानक तय होने चाहिए, ताकि बच्चों की सेहत पर ये भारी न पड़ें

क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में आयात किए जाने वाले 67 प्रतिशत खिलौने सुरक्षा मानकों की सभी जांच में खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में आयातित खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर सोचा जाना जरूरी है, क्योंकि देश में बिकने वाले लगभग 85 प्रतिशत खिलौने दूसरे देशों से आते हैं। यह सच है कि खिलौने बच्चों की खुशी से जुड़े होते हैं। ये उनके दिन-रात के साथी होते हैं। छोटे बच्चे तो खिलौनों को मुंह में भी डालते हैं, लेकिन इनमें मौजूद खतरनाक रसायनों और धातुओं से उनकी सेहत को सहेजने के साथ ही सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी सोचा जाना जरूरी है। इन हानिकारक चीजों का असर बच्चों के मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एलर्जी और थॉयरायड सिस्टम को प्रभावित करने से लेकर कैंसर तक की वजह बन सकता है।

भारत ही नहीं दुनियाभर में खिलौनों का बड़ा कारोबार है। आंकड़े बताते हैं कि भारत का घरेलू खिलौना उद्योग करीब 5000 करोड़ रुपये का है। प्लास्टिक खिलौनों ने बाजार पर कब्जा जमाया हुआ है। प्लास्टिक के नरम खिलौनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन थायलेट मासूम बच्चों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के अनुसार थायलेट से बच्चों में कई तरह की बीमारियां होती हैं। इस हानिकारक रसायन से बच्चों की किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ने के साथ ही हड्डियों के विकास में कमी आती है। चिंतनीय है कि कई खिलौने दोबारा इस्तेमाल की गई प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक री-साइकिल प्लास्टिक से बने खिलौनों में सेहत के लिए बेहद हानिकारक रसायन डायोक्सिन काफी मात्रा में पाया जाता है। डायोक्सिन की खिलौनों में मौजूदगी बच्चों को गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। अफसोस कि हमारे यहां सस्ते, सुंदर और टिकाऊ के फेर में री-साइकिल प्लास्टिक से बने खिलौने खूब खरीदे भी जाते हैं। कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन आइपैन ने भी खिलौनों में जहर पर एक अध्ययन जारी किया था। कई देशों से खिलौनों के नमूने लेकर की गई जांच में पाया गया था कि करीब 32 प्रतिशत खिलौनों में आर्सेनिक, लेड और पारा चिंताजनक स्तर से भी ज्यादा होते हैं। गौरतलब है कि इस अध्ययन के लिए नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देशों से खिलौनों के नमूने लिए गए थे। ऐसे में भारत में खिलौनों की गुणवत्ता की स्थिति समझना मुश्किल नहीं है।

हमारे यहां अधिकतर खिलौने चीन से आते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 60 फीसद खिलौने चीन से आयात किए जाते हैं। गुणवत्ता के मामले में अधिकतर चीनी वस्तुएं हमेशा सवालों के घेरे में ही रहती हैं। ऐसे में अभिभावकों का जागरूक होना आवश्यक है। बच्चों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। इसीलिए खिलौनों की गुणवत्ता को लेकर हमारे अपने देश में मानक तय होने चाहिए, ताकि खिलौनों से खेलना मासूम बच्चों को खुशहाल बचपन दे न कि बीमारियां।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विपक्षी राजनीति को समझने की जरूरत

संजय गुप्त द्वारा अपने आलेख 'भाजपा के सबक सीखने का समय' में झारखंड की हार के लिए क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा को ही प्रमुख वजह मान लेना, इस हार की हकीकत का एक पक्ष भर है। इसका दूसरा स्याह पक्ष ये है कि मोदी के पराक्रम से हाशिये पर पहुंच चुकी कांग्रेस अब पुनः भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपनी शक्ति को संजोने में कामयाब होने लगी है। इस तथ्य की अनदेखी करना भी चकित कर देने वाली झारखंड पराजय की एक वजह बन गई। ऐसे में अब भाजपा को इस विपक्षी राजनीति को ठीक से समझने की जरूरत है। कांग्रेस द्वारा संघ और भाजपा के लिए की जाने वाली भ्रामक बयानबाजी और नागरिकता कानून की ओट लेकर पूरे देश में अराजक स्थिति पैदा करने वाली घातक चाल को हल्की राजनीति मान लेना भी भाजपा के लिए नुकसानदेय साबित हो रहा है। हालांकि नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष द्वारा भड़काए गए मुस्लिम वर्ग को थामने के लिए जहां एक ओर भाजपा शासित राज्यों में उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर उप्र की योगी सरकार द्वारा तीन तलाक से उत्पीड़ित महिलाओं के लिए छह हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद की घोषणा करके मुस्लिम महिलाओं को अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम वर्ग को अपना निजी वोटबैंक मानने वाली कांग्रेस की राजनीतिक चालों को नाकामयाब करने के लिए भाजपा द्वारा देश के मुस्लिम वर्ग को यह संदेश देना जरूरी है कि वह राष्ट्रघाती उपद्रव को भी प्रच्छन्न आतंकवाद मानकर दंगाइयों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन इससे देश के शांतिप्रिय मुस्लिम वर्ग को विचलित होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रभावी और निष्पक्ष शासन के लिए देश के अपराधियों और शांतिप्रिय नागरिकों में भेद करना जरूरी है। इसके साथ ही भाजपा को यह भी समझना होगा कि राज्यों में पर्याप्त जनाधार होने के बाद भी क्षेत्रीय दलों के साथ ठीक से समन्वय स्थापित न कर पाने की उसकी अपनी कमजोरी से भी विपक्ष मजबूत हो रहा है।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

मेलबाक्स

मोदी-शाह के भरोसे पार्टी

दैनिक जागरण के 26 दिसंबर के अंक में प्रदीप सिंह का लेख, भाजपा के सामने चुनौती और अवसर, पढ़ा। लेखक ने सही विश्लेषण किया है। भाजपा के सांसद और विधायक यही मान रहे हैं कि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नही है, सब कुछ मोदी और शाह करेंगे। यह सोच इस पार्टी में हावी है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब-जब धर्म की हानि होती है, मैं साधुजनों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेता हूं। यह बात तो भाजपा के लोगों ने गांठ बांध ली, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बार-बार शस्त्र उठा कर युद्ध करने को भी कहा है। गीता का सबसे बड़ा संदेश ही कर्म करने में ही छुपा है। मोदी और शाह तो देश व पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के वे लोग जो सत्ता में हैं वे कुछ करना नहीं चाहते। अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो हरियाणा और झारखंड की तरह अन्य चुनाव भी हारते चले जाएंगे। अभी दिल्ली का चुनाव आ रहा है, लेकिन दिल्ली में पार्टी का सर्वमान्य नेता कौन है यह आपसी खींचतान की वजह से तय नहीं हो सका है। सभी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता को अराजकता में बदलने में देर नहीं लगती है। हर देश, हर पार्टी, हर घर, हर समाज किन्हीं नियम कायदों से ही चलता है। यह बात सभी पार्टियों पर लागू होती है, लेकिन यह भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें भले ही पार्टी हाईकमान के प्रति नाराजगी न हो, लेकिन आपस में समन्वय बहुत अच्छा नहीं है।

ओपी जैन, सूरजमल विहार, दिल्ली

झारखंड में भाजपा की हार

झारखंड में भाजपा की हार की मुख्य बड़ी वजह झामुमो, कांग्रेस और राजद का एक मजबूत गठबंधन बनना है। झामुमो ने अपने लिए ग्रामीण और कांग्रेस को शहरी सीटें देकर अच्छा रणनीतिक प्रयोग किया। आजसू से भाजपा का गठबंधन टूटना भी ठीक नहीं रहा। हरियाणा व महाराष्ट्र की तरह यहां भी बागियों ने भाजपा को हरवाया। आखिर इतनी संख्या में बागी क्यों खड़े हुए। पार्टी में इतने व्यापक असंतोष के क्या कारण थे?

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

60 प्रतिशत योगदान हो गया है सेवा क्षेत्र का, देश की जीडीपी में, जो वर्ष 1950 में महज 15 प्रतिशत के आसपास ही था। इस प्रकार सेवा क्षेत्र देश में सबसे तेज बढ़ने वाले क्षेत्र रूप में उभरा है।

आजकल

पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य में तमाम चुनौतियां

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने हाल में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को वर्ष 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तमाम किस्म की चुनौतियों से भरा है। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। पिछले छह वर्षों में भारत का जीडीपी औसतन छह प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा है, लेकिन उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसमें 10 .5 प्रतिशत बढ़ोतरी की आवश्यकता प्रतिवर्ष के हिसाब से अगले पांच वर्षों तक करनी होगी जो देश-दुनिया के मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए बड़ी चुनौती है

प्रो. लल्लन प्रसाद
पूर्व विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रतीकात्मक

भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भले ही चुनौतियां भरा हो, फिर भी इसे साकार करने के लिए देश में मांग में आई गिरावट को रोकना होगा और उत्पादकता व रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने होंगे। अर्थव्यवस्था में आधारभूत सुधारों के लिए भी यह अच्छा समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जब उन्होंने सत्ता संभाली भारतीय आर्थव्यवस्था का आकार 1.85 ट्रिलियन डॉलर था जो बढ़कर 2.7 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। अगले पांच वर्षों में पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्ति के लिए देश सक्षम है।

भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से 2018 के मध्य तक लगभग आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है, जिसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। इसके मुख्य कारण हैं विश्वव्यापी मंदी, देश के अंदर मांग की कमी, निर्यात में गिरावट, कारखानों में घटता उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का धीमा विकास आदि। नवंबर 2016 में नोटबंदी एवं जुलाई 2017 में जीएसटी के निर्णय सैद्धांतिक रूप से सही थे, किंतु कार्यान्वयन की कमियों के कारण उतना लाभ नहीं हुआ, जितना अपेक्षित था। अर्थव्यवस्था पर ये निर्णय भारी पड़े। इनका दूरगामी लाभ संभव है, किंतु तात्कालिक असर प्रतिकूल होने से आर्थिक सुस्ती के हालात बने।

जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही में विकास दर 4.5 प्रतिशत पर आ गया जिसे लेकर सभी रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2017-20 के लिए किए गए सात प्रतिशत के विकास के अनुमान को घटाकर 5.8 प्रतिशत के करीब ला दिया। मूडी इनवेस्टर सर्विस के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में विकास दर 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, अगले दो वर्षों में यह 6.6 प्रतिशत एवं 6.7 प्रतिशत संभावित है।

मांग में कमी से उत्पादन पर असर : मांग में कमी के कारण कारखानों में उत्पादन घटा है। इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में क्रमशः 4.3 एवं 3.8 प्रतिशत की गिरावट हुई, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में कारखानों का उत्पादन 8.4 प्रतिशत बढ़ा था। पूंजीगत उद्योगों जैसे ऊर्जा, माइनिंग, कच्चा तेल आदि में कम निवेश हुआ। मंदी का सबसे अधिक प्रभाव ऑटोमोटिव उद्योग पर पड़ा। सितंबर 2018 की तुलना में सितंबर 2019 में सवारी गाड़ियों की बिक्री में 18 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री में 75 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए बीएस 4 से बीएस 6 के 'एमिशन नार्म' अप्रैल 2020 तक अपनाने के आदेश से कारों की बिक्री में कमी हुई। सरकार इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन पर भी जोर दे रही है। कारों की मांग में कमी उबर और ओला जैसी कंपनियों के कारण भी हुई। सड़कों पर जाम लगने, पार्किंग महंगा होने एवं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त होने से बहुत से संभावित खरीदार किराए के कार में जाना पसंद करने लगे। इधर दो पहिया वाहनों की बिक्री में भी गिरावट आई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी एवं निम्न मध्यम वर्गीय शहरियों के पास नकदी की कमी इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। ऑटो उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने अपने विभागों पर नई गाड़ियां खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाए थे उन्हें हटा दिया है। मार्च 2020 तक कारों के डिप्रिसिएशन की छूट दर 15 प्रतिशत कर दी गई है।

बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर सरकार जोर दे रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, बंदरगाहों, टेलीकॉम, रेलवे, पावर जेनरेशन आदि के विकास में तेजी आई है, किंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश आवश्यक है, उतना हो नहीं रहा है। इस क्षेत्र में 6.8 से 7.5 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष लगाया जा रहा है, जबकि आवश्यकता 13.6 लाख करोड़ के लगभग की है। इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआइ लगाने की अनुमति सरकार ने पहले ही दे दी है। क्षेत्र का वार्षिक विकास दर 10.5 प्रतिशत के करीब है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। वर्ष 2018 में 167 देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारत का 44वां स्थान था। वर्ष 2000 से 2019 के बीच इस क्षेत्र में 25 बिलियन डॉलर का सीधा निवेश हुआ।

रीयल इस्टेट में बूम और गड़बड़ी : भवन निर्माण (रीयल इस्टेट) सेक्टर जीडीपी के विकास एवं रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। विगत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है। वर्ष 2005 में यह क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोला गया। तब से शहरों में बहुमंजिले इमारतों के निर्माण में तेजी आई, बिल्डर्स को पूंजी की कमी नहीं रही। लोग सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, निवेश करके पूंजी और आय बढ़ाने के लिए भी इस क्षेत्र में धन लगाने लगे। यह क्षेत्र कालेधन का भी बड़ा सोख्ता बन गया। सरकार की विमुद्रीकरण नीति, जीएसटी रीयल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एवं इनसॉल्वैंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ने इस क्षेत्र पर कुछ लगाम लगाई। इसकी आवश्यकता इसलिए हो गई थी, क्योंकि बहुत से बिल्डर्स ने लोगों से एडवांस पेमेंट लेने और बैंकों से भी कर्ज लेने के बावजूद निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया। वर्षों तक इंतजार के बाद भी लोगों को मकान नहीं मिला, जबकि वे भुगतान कर चुके थे, बैंकों का कर्ज उनके सिर पर था।

एक अनुमान के अनुसार देश के सात बड़े शहरों में 5.6 लाख मकान अधूरे बने पड़े हैं, जिनमें 65 बिलियन डॉलर का निवेश फसा है। नॉन बैंकिंग कंपनी- इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाईनांस कंपनी जिसने इस क्षेत्र में भारी लोन दिए थे, दिवालिया हो गई, क्योंकि लोन का बड़ा अंश वापस नहीं आया। सरकारी और निजी बैंकों को भी दिए हुए कर्ज की उगाही में कठिनाई हो गई। बहुत सारी बिल्डर्स कंपनियों का मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को रेफर किया जा चुका है, किंतु निर्णय बहुत कम मामलों में आया है। इस क्षेत्र को मुश्किलों से उबारने के लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया है, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके।

संसाधनों के विकास के साथ-साथ मानव विकास भी जीडीपी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। आबादी की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लगभग 135 करोड़ की आबादी में 65 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में अच्छा प्रयास हुआ जिसे विश्व बैंक ने सराहा है। प्रति व्यक्ति आमदनी की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत अब निम्न मध्यम आय ग्रुप में आ गया है, बहुत वर्षों तक निम्न ग्रुप में रहने के बाद।

शिक्षा के अवसर देश में तेजी से बढ़े है, किंतु गुणवत्ता में वृद्धि की आवश्यकता है। विश्व स्तर की शिक्षा, अनुसंधान एवं कौशल विकास के संसाधन बहुत कम हैं, सरकार नई शिक्षा नीति का प्रारूप लेकर आई है जिसमें सभी स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर है, समन्वित सोच के पाठयक्रम विकसित किए जाएंगे। शोध अनुसंधान पर खास जोर दिया जाएगा, शिक्षा पर होने वाला खर्च जीडीपी के 3.5 प्रतिशत से बढ़ा कर छह प्रतिशत किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई है।

वर्तमान अवस्था में जो सुस्ती आई है इससे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए सरकार ने जो तत्काल उपाय किए हैं, उनमें प्रमुख हैं- लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा लोन मेलों का आयोजन जिसके तहत अक्टूबर एवं नवंबर 2019 में 4.91 लाख करोड़ रुपये आम उपभोक्ताओं, छोटे कारोबारियों, नॉन बैंकिंग संस्थानों और किसानों को दिए गए एवं कॉरपोरेट टैक्स की दर 400 करोड़ रुपये के आकार तक की कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत एवं नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दी गई है। बैंकों को कम ब्याज पर कर्ज मिल सके, ताकि उद्योग-धंधों व कंपनियों और होम लोन लेने वालों को बैंक कम ब्याज पर लोन दे सकें इसके लिए रिजर्व बैंक ने रेपोरेट में इस वर्ष छह बार कमी की है। वर्तमान रेपोरेट 5.15 प्रतिशत है जो वर्ष के आरंभ में 6.5 प्रतिशत था। मंदी के कारण अर्थव्यवस्था को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे कुछ महीनों में दूर हो जाएंगी और पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर देश तेजी से बढ़ सकेगा।

एमएसएमई पर देना होगा जोर

लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) का देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला यह क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 38 प्रतिशत का योगदान करता है। कारखानों के कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत एवं निर्यात का 40 प्रतिशत इस क्षेत्र द्वारा होता है। चीन की डंपिंग नीति से इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। चीन से आयातित चीजों की कीमत इतनी कम होती है, जिन पर भारतीय उद्योग उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। छोटे उद्योगों को जीएसटी फॉर्म भरने और रिफंड में देर होने से जो कठिनाइयां आई हैं, उन पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस क्षेत्र के लिए कर्ज की सुविधा प्रदान की गई है। बिना किसी जमानत के कर्ज की सुविधा सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत की है।

कृषि क्षेत्र को दिया जाए बढ़ावा

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जीडीपी में उसका योगदान 15 प्रतिशत के लगभग ही है, किंतु देश की आधी से अधिक आबादी उस पर निर्भर है। सरकार किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लिए कृत संकल्प है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में जो कठिनाइयां हैं, उनके मूल में छोटे किसानों के पास दो एकड़ से कम भूमि होना, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, गरीबी और कर्ज, उत्पादकता में कमी एवं कृषि उपज का उचित मूल्य न मिलना आदि हैं। इस वर्ष देश के 12 राज्यों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनमें कृषि पदार्थों की सरकारी खरीद की कीमतों में वृद्धि, किसान सम्मान निधि, किसान पेंशन योजना, नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना, पशु बीमा योजना आदि शामिल हैं जिनका लाभ गांव के लोगों को मिलेगा।

सेवा क्षेत्र को मिले प्रोत्साहन

सेवा क्षेत्र देश में सबसे तेज बढ़ने वाला क्षेत्र है। जीडीपी में इसका योगदान वर्ष 1950 के 15 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019 में 60 प्रतिशत हो गया है। बैंकिंग, फाइनांस, बीमा, होटल, टूरिज्म, यातायात, मीडिया एवं मनोरंजन, आइटी, व्यापार एवं व्यक्तिगत सेवाएं इस क्षेत्र में आती हैं। वर्ष 2000 से 2018 के बीच इस क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर का सीधा निवेश हुआ। सॉफ्टवेयर सेवाओं में भारत की भागीदारी 55 प्रतिशत के लगभग है। मोबाइल फोन धारकों की संख्या 80 करोड़ से भी अधिक हो गई है। बैंकिंग सेक्टर में अदेय ऋणों (एनपीए) के कारण जो शिथिलता आई उसे दूर करने के लिए सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में 70 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। सेवाओं के निर्यात के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता रहा है उसमें दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

खरी-खरी

बहुत कुछ कह जाती हैं चरण पादुकाएं

बी एल आच्छा

यों लोग कह जाते हैं- कुछ नैनन से, तो कुछ सैनन से। जमाना बॉडी लैंग्वेज का है। तो थिरकते कपोलों और बालों में उलझी उंगलियों से ही कह जाते हैं। रही-सही जबानी भी। मगर जबान की अपनी मुश्किल। रहीम जानते थे- 'जिव्हा बावरी से जूती खात कपाल तक।' मुझे लगा चरण पादुकाओं उर्फ जूतों में भाषा की सी जान है। पूरी कहानी कह जाती हैं वे।

कतार में जमे जूते घरेलू संस्कारों का अंदाजा दे जाते हैं। मगर अभिव्यक्ति की आंदोलनी जबान के दिन हैं। सड़कों-चौराहों पर बेतरतीब बिखरी चरण पादुकाएं कुछ और ही कह जाती हैं। निर्जीव जूते बदहवासी की व्यथा कह जाते हैं। धारा के बाद लाठीचार्ज। आगजनी और आंसू गैस। हवाई फायर और गोलियां।

हालांकि चरण पादुकाओं के दृश्य और भी हैं। अगरचे मंच से मंत्री-मुख्यमंत्री के जूते चोरी चले जाएं, तो चार जोड़ी का बंदोबस्त तत्काल। मगर शादी या मंदिर से जूते चोरी चले जाएं तो पैदल मार्च शर्मिंदगी से लथपथ कर देता है। आंदोलनों में सड़कों पर बिखरीं चरण पादुकाएं किसी नेता को जूतों सहित कुर्सी पर पहुंचा देती हैं। आखिर बिखरे जूतों से कुर्सी हथियाने का भी आंदोलनी इतिहास है। यह अलग बात है कि चरण पादुकाओं को नमन कर राज चलाने का भी अपना इतिहास है। लोग कहते हैं कि जहां-जहां तक जूते जाते हैं, वहीं-वहीं तक पुलिस जाती है। मगर अभिव्यक्ति के लोकतंत्र में पुलिस धर्मस्थलों में जाने को भी मजबूर है।

चरण पादुकाओं का अपना रोमानी अंदाज भी है। दीदी तेरा देवर दीवाना और सालियों की जूता-छुपाऊ शरारतें रसरंग घोल देती हैं। शरारतें चेहरे पर तैरने लगती हैं और हंसी के भंवर पड़ जाते हैं। इसके ठीक उलट कवि धूमिल की 'मोचीराम' कविता की चुभती कील सूटबूट वाले बाबूजी पर ही वार कर जाती है।

मर्द के जूतों में जितनी मर्दानगी नहीं होती, उतनी मौका-ए-वारदात पर जनानी चप्पल में। खुली खिड़कियों जैसी चप्पल, और दे दनादन। भारी भरकम जूते चप्पल से बेदम। अब देखिए न! क्या नहीं कहती जूता-भाषा। पिटाई-विमर्श से लेकर नारी-विमर्श तक। बदहवास जनता से लेकर कुर्सी के लोकतंत्र तक।

ट्वीट-ट्वीट

जितना उपहास सनातन धर्म, संस्कृति, चिकित्सा पद्धति, मूल्यों व दर्शन का उड़ाया गया, उतना विश्व में किसी अन्य धर्म या संस्कृति के साथ नहीं किया गया। बीएचयू में भूत विद्या पाठ्यक्रम का समाचार इसका उदाहरण है। यह बात अलग है कि अपने अल्पज्ञान के चलते उपहास उड़ाने वाले ही उपहास का पात्र बन गए।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

यह साल भारतीय न्यायपालिका के लिए अच्छा नहीं रहा। मसलन न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। अनुच्छेद 370, कश्मीर गतिरोध, सीएए और उस पर विरोध प्रदर्शन, एनकाउंटर किलिंग और अयोध्या जैसे मामलों के रूप में यह सूची अंतहीन होती जाएगी।
मनीष छिब्बर@maneeshchhibber

एक वामपंथी का दर्द। अगर अदालतें उनकी पसंद के खिलाफ फैसले सुनाएं तो वे उनकी आंखों में खटकने लगती हैं। अदालतों के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं जबकि भारतीय न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है।
मोहनदास पई@TVMohandasPai

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रेलवे बोर्ड के स्वरूप में प्रस्तावित बदलाव से रेल सेवाओं में सुधार होगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फैले भ्रम को दूर करने में मोदी सरकार सफल रही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दानिश के संग पाक में हुआ वही व्यवहार,
जिससे आंखें मूंद तुम करते हाहाकार।
करते हाहाकार सड़क पर शोर मचाते,
लेकर पत्थर हाथ देश में आग लगाते।
बात-बात पर आप उगलते रहते हैं विष,
दानिश पर दो शब्द बोलिए अहले दानिश!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

सियासत ने उत्तर प्रदेश को बना दिया प्रश्न प्रदेश

सद्‌गुरु शरण
स्थानीय संपादक, लखनऊ

सियासत जब अपनी परिभाषित भूमिका बदलकर युद्ध में तब्दील हो जाए तो सब कुछ शायद उसी तरह जायज हो जाता है, जैसा इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तीन तलाक, फिर अनुच्छेद 370 और अंततः राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वसमाज, खासकर युवाओं ने जिस समझदारी, संवेदनशीलता और देशभक्ति का शालीन जज्बा दिखाया, उसने सामाजिक वर्गों को महज वोटबैंक मानने वाले सियासी दलों और संगठनों को बेइंतिहा बेचैन कर दिया। सियासत भला यह कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि हिंदू-मुसलमान सद्‌भावपूर्वक रहना सीख लें? फिर सियासत का धंधा-पानी कैसे चलेगा? फिर क्या था, रणनीति बनी और साजिश को अमली जामा पहनाने की तैयारी। इस बार दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश को रणभूमि बनाया गया। शुरुआत लखनऊ से हुई और आग की लपटें कई शहरों तक पहुंचीं। सरकारी संपत्तियों की होली जलाई गई। पुलिस पर पत्थर वर्षा हुई और हिंदुस्तान मुर्दाबाद- पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने कुछ वैसा ही दृश्य पैदा किया, जैसा कुछ साल पहले एक रात जेएनयू परिसर में हिंदुस्तान को टुकड़े-टुकड़े करने का संकल्प लिए जाते वक्त दिखा था। संयोग है कि उस रात राहुल गांधी जेएनयू पहुंचे थे तो इस बार प्रियंका गांधी लखनऊ।

सियासत का धर्म होता है कि समस्याओं का समाधान करे और प्रश्नों के जवाब दे। उत्तर प्रदेश में सियासत ठीक विपरीत राह पर चल रही है। खुद समस्याएं पैदा कर रही है और प्रश्नों के जवाब देने से मुंह चुरा रही है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ उसी तरह सक्रिय दिख रही हैं, जैसे 2012 चुनाव से पहले राहुल गांधी बाहें चढ़ाते दिखते थे। पिछले तीन दशक से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं द्वारा उपेक्षित कांग्रेस को खुद से यह सवाल करना चाहिए कि उसकी यह गति क्यों? ऐसा नहीं कि 1989 के बाद गैर भाजपा दल हाशिये पर ही रहे। इस दरम्यान सपा और बसपा कई बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचीं, पर कांग्रेस पर मतदाताओं ने भरोसा नहीं किया। क्यों? कांग्रेस नेतृत्व को इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए। पार्टी को देखना चाहिए कि जो अमेठी गांधी-नेहरू परिवार के साथ अपने रिश्ते पर इतराती थी, उसने राहुल गांधी को किस मनोदशा में पराजित कर दिया? जिन प्रियंका गांधी को पार्टी ट्रंप कार्ड मानकर मैदान में लाई थी, वे उत्तर प्रदेश में प्रभावहीन क्यों साबित हुईं? कांग्रेस के सामने ऐसे प्रश्नों की लंबी कतार है, पर पार्टी का नेतृत्व लखनऊ में उन लोगों के घर जाने की जिद कर रहा है जिन पर पिछले दिनों शहर को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रचने के पुख्ता आरोप हैं। मायावती तो विपक्ष की ही नेता हैं। वह बिल्कुल वाजिब सवाल कर रहीं कि कांग्रेस को सत्ता में रहने पर संविधान की याद क्यों नहीं आती? कांग्रेस इसका भी जवाब नहीं दे रही। उसके नेता मेरठ के एसपी सिटी के पीछे पड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे लोगों से कह दिया कि यहां की रोटी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद करने से अच्छा है, पाकिस्तान ही चले जाओ। बावर्दी ड्यूटी कर रहे एक पुलिस अधिकारी को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, पर इस अधिकारी के पीछे पड़ी कांग्रेस और बाकी आलोचकों के सामने जनता के दो बड़े सवाल हैं। पहला, जब कुछ लोग सामने आकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हों, उस वक्त एक देशभक्त पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? मूकदर्शक बने रहकर हिंदुस्तान की बेइज्जती बर्दाश्त करनी चाहिए? दूसरा सवाल यह कि जो लोग हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, उनके बारे में कांग्रेस और अन्य दलों की क्या राय है? सियासत के सामने सवाल और भी हैं। मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और सबके लिए प्रगतिशील शिक्षा एवं समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर सियासी दलों का नजरिया क्या है? मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की यातना से मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं? मुस्लिम समाज के बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्राप्त कर विकसित होने का हक मिलना चाहिए या नहीं?

प्रियंका गांधी। फाइल फोटो।

बड़े सवाल उत्तर प्रदेश से उठ रहे हैं तो इसकी ठोस वजह है। वर्ष 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव स्पष्ट संकेत देगा कि जनता क्या चाहती है। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव के जनादेश में जाति-धर्म की दीवारें जिस तरह ध्वस्त हुईं, उससे वोटबैंक राजनीति के आदी दलों की घबराहट स्वाभाविक है, पर इन दलों के सामने यह बदलाव स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ विरोध की राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। जनता सकारात्मकता चाहती है, शांति और सद्‌भाव के साथ विकास। राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रति सम्मान जताकर मुस्लिम समाज ने भी यही संदेश दिया है। सभी धर्म-जाति के लोगों को विकसित हो रहे मुल्क में अपनी भागीदारी चाहिए। सबको शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए। भाजपा के एजेंडे पर सहमति-असहमति हो सकती है, पर उसमें कुछ भी छुपा नहीं है। जब तक जनता इसे पसंद कर रही, कोई क्या कर सकता है। बाकी दलों को यह भी बताना चाहिए कि उनके पास वैकल्पिक एजेंडा क्या है। यदि विपक्षी दलों को लगता है कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक के विषय जनमत के विपरीत हैं तो ऐसे दलों के प्रति सहानुभूति ही जताई जा सकती है। सभी दलों को आम आदमी के करीब जाकर उनका मन पढ़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में समान नागरिक संहिता का सवाल भी खड़ा हो रहा है। सभी दल जनता के प्रश्नों का जवाब देने का साहस जुटाएं अन्यथा उत्तर प्रदेश के प्रश्न प्रदेश बने रहने तक इन दलों को कुछ खास हासिल नहीं होने वाला।

चिंताजनक

उत्तर भारत में सर्दी का सितम

दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप भयावह स्तर पर है और आगामी एक सप्ताह तक इसके जारी रहने की संभावना है। ऐसे में इसके कारणों व परिणामों को जानना जरूरी है

महेश पलावत
मौसम वैज्ञानिक (स्काईमेट)

प्रतीकात्मक

पिछले करीब एक पखवाड़े से दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अनेक इलाकों में तापमान दो डिग्री से भी नीचे तक जा चुका है। उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तो ठंड कहर बरपा रही ही है।

वर्ष 1901 के बाद से 2019 का दिसंबर माह सबसे ज्यादा ठंडा है। सवाल है आखिरकार दिल्ली में इस कदर पड़ रही ठंड का कारण क्या है? इसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। 20 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, अब इसके बाद यह 30 या 31 दिसंबर को आएगा। यह जो 10 दिनों का अंतराल है, इस दौरान लगातार उत्तर दिशा से बर्फीली हवाएं आ रही हैं। पहाड़ों से ये जो सर्द हवाएं आ रही हैं, वास्तव में दिल्ली सहित उत्तर भारत और मध्य भारत से लेकर तेलंगाना तक पड़ रही कड़ाके की सर्दी का मुख्य कारण है। वर्ष 1997 के बाद से यह सबसे ज्यादा सर्द मौसम है, इसके पीछे कारण यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में आया लंबा गैप है। तात्कालिक रूप से इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण आदि से नहीं है। हां, कड़ाके की सर्दी के कारण हवा की गति में जो कमी आई है, उसके कारण पहले से मौजूद प्रदूषण परेशान कर रहा है।

सर्दी के मौसम में जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बड़ा अंतराल पैदा होता है तो उस दौरान चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होती रहती है, नतीजन ठंड बढ़ जाती है। दिल्ली में इस समय जो ठंड पड़ रही है, उसमें 31 दिसंबर तक कोई कमी नहीं आती दिख रही। 31 दिसंबर से दो दिनों तक दिल्ली में बारिश की संभावना है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हरियाणा, पंजाब, यूपी में बारिश हो सकती है। इससे तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन तीन जनवरी के बाद चूंकि स्नो फॉल हो चुका होगा इसलिए एक बार फिर से तापमान में गिरावट शुरू होगी, जो कई दिनों तक जारी रहेगी यानी दिल्ली एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ जाएगा।

जहां तक इस कड़ाके की ठंड से होने वाले नुकसान की बात है तो इससे कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि इससे फायदा ही होता है। खासकर गेहूं की फसल के लिए यह कड़ाके की ठंड काफी फायदेमंद होती है। मगर इस ठंड के चलते जो फॉग है उससे एक्सीडेंट की आशंकाएं काफी बढ़ जाती हैं, क्योंकि फॉग के कारण दृश्यता घट जाती है। हां, इस सर्दी का एक नुकसान इसके चलते पड़ने वाला पाला है। पाला से फसलें बरबाद होती हैं। इन दिनों इस कड़ाके की ठंड के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी ज्यादा पाला गिर रहा है, जो फसलों के लिए नुकसानदायक है। जहां तक इस साल ठंडी के मौसम के लंबे होने की आशंका की बात है तो उसे इस समय की ठंड से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए तात्कालिक रूप से यह कह पाना संभव नहीं है कि क्या इस साल हाल के वर्षों के मुकाबले ठंड ज्यादा दिनों तक रहेगी? हां, अगर बर्फबारी ज्यादा होती है या लंबे समय तक जारी रहती है तो निश्चित रूप से ठंड का समय अनुमान से ज्यादा लंबा हो सकता है।

वैसे इस साल दिसंबर के महीने में 1997 के बाद से जो बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आमतौर पर बर्फबारी दिसंबर के पहले नहीं होती है। लेकिन इस वर्ष नवंबर में ही, बल्कि कहना चाहिए नवंबर में भी बिल्कुल शुरू में पहाड़ों में जो जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, उससे तभी यह लग रहा था कि इस साल ठंड ज्यादा पड़ेगी। जब भी नवंबर माह में बर्फबारी ज्यादा होती है तो दिसंबर ज्यादा ठंडा हो जाता है। क्योंकि बर्फ जब जम जाती है और हवाएं लगातार चलती हैं तो तापमान गिर जाता है। इस साल वास्तव में यही हुआ है। जब दिसंबर के पहले काफी ज्यादा बर्फ गिरती है तो पूरे उत्तर भारत का तापमान गिर जाता है।

जहां तक इस बर्फबारी से पिघले हुए ग्लेशियरों की भरपाई की बात है तो ऐसा अनुमान लगाना सही नहीं होगा। हां, इस तरह की बर्फबारी से इतना जरूर होता है कि इस तरह की बर्फबारी से कुछ महीनों के लिए ग्लेशियरों के पिघलने में कमी आ जाती है। चूंकि धरती का समग्रता में तापमान बढ़ रहा है, इसलिए इस तरह की बर्फबारी से ग्लेशियरों के पिघलने का सिलसिला बंद नहीं होता। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें तथा और कई वजहें जिम्मेदार हैं, जब तक उन पर लगाम नहीं लगता, धरती के बढ़ते हुए तापमान में कमी नहीं होगी और जब तक धरती के तापमान में कमी नहीं होगी, तब तक ग्लेशियरों का पिघलना भी बंद नहीं होगा। इसलिए इस बर्फबारी से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यह पिघले हुए ग्लेशियरों की भरपाई कर सकती है। हां, इसके चलते कुछ महीने तक अवश्य ग्लेशियरों के पिघलने में कमी आ सकती है। लेकिन स्थायी रूप से यह कमी तभी होगी, जब धरती के तापमान में कमी होगी, जो कि लगातार बढ़ ही रहा है। (ईआरसी)

पंजाब

अगर ठान लें तो कोई काम असंभव नहीं

पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में गत दिवस आयोजित शहीदी जोड़ मेल में लंगर कमेटियों और श्रद्धालुओं ने प्लास्टिक से दूरी बनाकर एक अच्छी पहल का आगाज किया है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और अन्य मामलों में भी इसे नजीर की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जिला प्रशासन ने प्लास्टिक के बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का प्रयोग न करने की अपील की थी और 450 लंगर कमेटियों ने इस अपील को मूर्त रूप देने की ठान ली। परिणाम सबके सामने है। इतनी बड़ी संगत को यदि प्लास्टिक के एक भी बर्तन और लिफाफे का प्रयोग किए बिना लंगर बरताया जा सकता है तो यह स्पष्ट है कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। पंजाब न सिर्फ प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से त्रस्त है, अपितु यहां नशे का सेवन, पराली जलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन और गंदगी जैसी कई कुरीतियां भी अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, जिनसे शीघ्र निजात पाने की सख्त आवश्यकता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिला प्रशासन, समाजसेवी संगठन और धार्मिक संगठनों को लोगों को जागरूक करना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार लोगों ने मात्र एक अपील पर प्लास्टिक से तौबा कर ली उसी तरह अन्य मामलों में भी ऐसी अपील का इतना ही प्रभावी असर हो। खासकर नशे के मामले में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश की युवा पीढ़ी बुरी तरह से इसके दलदल में फंसी हुई है।

यह प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार लोगों ने मात्र एक अपील पर प्लास्टिक से तौबा कर ली उसी तरह अन्य मामलों में भी ऐसी अपील का प्रभावी असर हो।

दुख की बात है कि जिस पंजाब को पांच नदियों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है, उसी राज्य को अब उसकी एक बड़ी आबादी के नशे की गिरफ्त में पड़ने के लिए जाना जा रहा है। एम्स की मानें तो पंजाब की 2.77 करोड़ की आबादी में से करीब 0.84 फीसद (2.3 लाख) लोग नशीले पदार्थों के आदी हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। यानी कि नशे की समस्या ने राज्य के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है। पंजाब में आने वाले ड्रग्स का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान से तस्करी के जरिये पहुंचता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ पंजाब की सीमा से भारत में आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश करती है। कहा जाता है कि सीमापार से होने वाली इस ड्रग्स स्मगलिंग के खेल में राज्य के ड्रग्स माफिया से लेकर कुछ ताकतवर नेता और अधिकारी भी शामिल हैं।

जाहिर है कि पंजाब जैसे समृद्ध राज्य को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए ऐसी ही दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। यदि प्रदेश के युवा जागरूक हो गए और स्वयं नशे से दूरी बनाने की ठान ली तो वह दिन दूर नहीं जब राज्य को इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। पराली, गंदगी, शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के मामलों में भी किसान, समाज और आम लोगों को स्वयं चाहिए कि सबसे पहले स्वयं से सुधार की शुरुआत करें और नए साल में यह संकल्प लें कि वह प्रदेश को तमाम विसंगतियों से छुटकारा दिलाकर पूरे देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

जम्मू- कश्मीर

टीबी मुक्त जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर को साल 2025 तक टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई क्षय रोग उन्मूलन कार्य योजना से उम्मीद बंधी है। निःसंदेह अगर इस पर गंभीरता से काम होगा तो टीबी को खत्म करना मुश्किल काम नहीं है। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि राज्य में इस रोग के मामले लगातार आ रहे हैं। इसी साल जम्मू संभाग में सात हजार नए मामले दर्ज हुए हैं। यही नहीं राज्य में हर साल औसतन टीबी से दौ सौ से तीन सौ मरीजों की मौत हो जाती है। विडंबना यह रही कि अब तक इस रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर कभी भी कोई अभियान नहीं चलाया गया।

यही सही है कि 15 वर्ष पूर्व पहल राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम और फिर संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाकर मरीजों को अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई, मगर इसे खत्म करने के लिए कभी भी किसी ने संकल्प नहीं लिया। अब वैश्विक स्तर पर इस रोग को 2030 तक खत्म करने के संकल्प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत से 2025 तक टीबी को खत्म करने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य टीबी के नए मामलों के जल्द पता लगाने और रोकथाम के लिए समुदाय स्तर पर विभिन्न हितधारकों के माध्यम से रोगी केंद्रित देखभाल सुनिश्चित करना है।

लोगों को यह समझाना जरूरी है कि अगर किसी

प्रतीकात्मक।

को तीन सप्ताह से अधिक खांसी है और थूक में खून आ रहा है तथा वजन भी कम हो रहा है तो इसे हल्के से न लें। यह ट्यूबरक्यूलोसिस भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जो कमियां हैं, उन्हें भी दूर करने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर में दस साल पहले बने आठ जिलों में आज तक सरकार टीबी के इलाज के लिए अलग से यूनिट तक नहीं बना पाई है। अभी भी इन जिलों में दस साल पहले वाले सिस्टम से ही काम हो रहा है। वर्ष 2007 में जम्मू में रियासी, रामबन, सांबा और किश्तवाड़ तथा कश्मीर में बांडीपोरा, कुलगाम, शोपियां और गांदरबल जिले बने थे। इन जिलों में अन्य जिला अधिकारी तो बिठा दिए गए, लेकिन जिला टीबी अधिकारी के पद आज तक सृजित नहीं हुए। अगर प्रशासन इन कमियों को दूर करता है तो जम्मू-कश्मीर को टीबी मुक्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

भारत विश्व में टीबी रोग से सबसे अधिक प्रभावित देश है। विश्व में इसका हर चौथा मरीज भारतीय होता है। विश्व में प्रतिवर्ष 14 लाख मौतें टीबी से होती हैं। इनमें से एक चौथाई से अधिक अर्थात चार लाख 80 हजार मौतें अकेले भारत में होती हैं। टीबी से मरने वाला हर पांचवां व्यक्ति भारतीय होता है। भारत में हर तीन मिनट में इससे दो मौतें होती हैं। करीब एक हजार प्रतिदिन। इसीलिए टीबी अत्यधिक जानलेवा बीमारी मानी जाती है। डब्ल्यूएचओ ने टीबी नियंत्रण को इस तरह परिभाषित किया है कि टीबी की व्यापकता 0-14 साल के लोगों के समूह में एक फीसद से कम हो जो भारत में 40 फीसद है।

टीबी जैसे भयानक रोग से मुक्ति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से लेकर सामाजिक जागरूकता में बदलाव की जरूरत है। यह जरूरी है कि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान टीबी की बीमारी को उचित प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यह सिर्फ एक चिकित्सकीय बीमारी नहीं है, बल्कि सामाजिक समस्या भी है।

बंगाल

तीस्ता समझौते की कठिन राह

भारत-बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौता पिछले कई दशकों से अटका हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समझौते का खुला विरोध कर चुकी हैं। इस समझौते में तीन पक्ष हैं। पहला भारत, दूसरा बंगाल और तीसरा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ममता का कहना है कि वे अपने राज्य की जनता का हित देखकर ही समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। आखिर इस समझौते की राह कहां से खुलेगी? यह सवाल वर्षों से बना हुआ है। इस बीच विशेषज्ञों ने समझौते की राह दिखाई है, जिससे उम्मीद की किरण दिखाई दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को शुष्क मौसम के दौरान नदी घाटी क्षेत्र में पानी की कम खपत वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर समझौते को मूर्त रूप दिया जा सकता है और दोनों देशों के लोग खुश हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने धान की एक किस्म 'बोरो' का उदाहरण देते हुए कहा कि सूखे अनाज की अन्य किस्मों के लिए आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित कर इसकी खेती को हतोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे में किसान कम पानी की खपत वाली फसलों की ओर जाएंगे और पानी की मांग में कमी आएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच सितंबर, 2011 में तीस्ता समझौता होने वाला था, लेकिन अंतिम क्षण में ममता की आपत्ति के बाद इसे टाल दिया गया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (कोलकाता) के निदेशक नीलांजन घोष का कहना है कि तीस्ता जल क्षेत्र से सटे इलाकों में सिंचाई पर आधारित धान की फसल का रकबा कई गुना बढ़ने के चलते पानी की मांग काफी बढ़ी है। जल प्रवाह में कमी आने के साथ ही पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ने लगता है। 'बोरो' धान के लिए लगभग 1,800-2,800 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो सोरघम या रागी जैसे सूखे अनाज की तुलना में 10 गुना अधिक है। नदी घाटी के कुल क्षेत्र 1,24,040 वर्ग किलोमीटर का लगभग 83 प्रतिशत भारत में है। नदी विशेषज्ञ जयंत बनर्जी का मानना है कि अगर किसानों ने संसाधनों को समझे बिना अधिक पानी वाली फसलों की खेती जारी रखी तो इससे विवाद बढ़ेगा इस मामले में वोट बैंक की राजनीति भी है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकार बोरो धान की खेती को हतोत्साहित नहीं करना चाहती हैं। ऐसे में बंगाल और बांग्लादेश दोनों के लिए आवश्यक है कि इस विवाद के निपटारे के लिए इस राह पर अमल करके देखें।

किसानों को शुष्क मौसम के दौरान नदी घाटी क्षेत्र में पानी की कम खपत वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करके तीस्ता समझौते को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

तीस्ता नदी जल बंटवारा समझौते के पीछे भारत के सामरिक हित भी हैं। यदि यह संधि असफल रहती है तो बांग्लोदश की नीतियां और कृत्य इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। बांग्लादेश की आर्थिक विपन्नता भारत में शरणार्थी और अवैध घुसपैठ की समस्या को भी बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त यदि बांग्लादेश की शेख हसीना नेतृत्व वाली सरकार यह समझौता करने में सफल रहती है तो वहां कट्टरपंथी समूह की आवाज दब जाएगी। जाहिर है दोनों देशों के मध्य यह करार एक दीर्घकालीन मधुर संबंधों को स्थापित कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश

जानवरों की संभाल पर भी हो जोर

पहाड़ी प्रदेश हिमाचल को पर्यटन राज्य के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं। उन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल के गोपालपुर में धौलाधार प्रकृति उद्यान केंद्र भी है। यहां पर कई प्रजातियों के जानवर रखे गए हैं। पिछले दिनों यहां पर जानवर आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत हरियाणा के भिवानी से तीन साल का नर चिंकारा पवन और तीन साल की मादा चिंकारा वर्षा को लाया गया था। इसके बदले यहां से भालुओं का जोड़ा वहां भेजा गया था। यहां लाए गए चिंकारा को कुछ दिन पिंजरे में रखने के बाद खुले में छोड़ा गया, लेकिन खुले में छोड़ने के करीब एक सप्ताह के बाद नर चिंकारा अपने बाड़े में मृत पाया गया। बेशक इसकी मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि अत्यधिक सर्दी के कारण ही इसकी मौत हुई है।

जानवरों के जानकार बताते हैं कि चिंकारा बहुत ही

प्रतीकात्मक।

शर्मिला जानवर होता है जो गर्म इलाके में झुंड में रहना पसंद करता है। जानकार भी मानते हैं कि इनके लिए हिमाचल में लाने का समय उपयुक्त नहीं था। अगर सर्दियों में ही इन्हें लाया जाना था तो इससे पहले वे तमाम इंतजाम किए जाने चाहिए थे जिससे इन्हें ठंड से बचाया जा सकता था। अभी पिछले दिनों गुजरात से शेरों के जोड़े भी यहां लाए गए थे। शेरों के इन जोड़ों को भी पहली सर्दियों में बचाया जाना बहुत जरूरी है। इनके लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए।

दरअसल कांगड़ा जिला के गोपालपुर स्थित धौलाधार प्रकृति उद्यान केंद्र में पशु-पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियां हैं। शेर, घोरल, मोर, भालू, जंगली सुअर और सांभर इत्यादि पर्यटकों को लुभाते हैं। करीब 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस चिड़ियाघर में जानवरों की प्रजातियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यहां पर जानवरों के लिए उनके अनुकूल वातावरण भी तैयार किया जाए। जो जानवर गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उनके लिए ऐसे बाड़े तैयार किए जाने चाहिए जहां पर तापमान उनके अनुकूल हो। इसके अलावा इन जानवरों का समय-समय पर चेकअप भी किया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि चिंकारा की मौत के बाद जानवरों की संभाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

डाटागीरी

भारत में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के बढ़ रहे मामले

भारत में कैंसर के हर साल लगभग 15 लाख नए मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यह दर अमेरिका की तुलना में कम है। भारत में जहां एक लाख लोगों में से 100 लोगों में कैंसर पाया जाता है। वहीं, अमेरिका में यह आंकड़ा 300 पहुंच जाता है। लेकिन भारत में पूरी दुनिया से उलट पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कैंसर ज्यादा पाया जाता है।

प्रतीकात्मक

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

दुनियाभर में आर्थिक रूप से संपन्न देशों में पुरुष कैंसर के ज्यादा शिकार होते हैं, लेकिन भारत में आंकड़े बिल्कुल उलट हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहां महिलाएं अधिकतर स्तन, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं।

इसकी वजह से जहां दुनियाभर में महिलाओं के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक पुरुषों में कैंसर पाया जाता है। वहीं, भारत में यह आंकड़ा बदलकर महिलाओं की तरफ चला जाता है। हालांकि, कैंसर से होने वाली मौतों की तुलना करें तो भारत में कैंसर की वजह से पुरुषों की ही ज्यादा मृत्यु होती है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्तन कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी आई है। 2016 में जहां देशभर में इसके 1.42 लाख मामले सामने आए थे। वहीं, 2018 में यह छह प्रतिशत बढ़कर 1.6 लाख हो गए। पिछले ससंद सत्र में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई थी। इन्हीं तीन सालों में सर्वाइकल कैंसर के मामले 99,000 से बढ़कर एक लाख और फिर 1.01 हो गए। सरकार ने यह जानकारी इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के डाटा के हवाले से दी है।

सबसे ज्यादा स्तन कैंसर के मामले

राज्य	2016	2017	2018
उत्तर प्रदेश	21,376	22,737	24,181
महाराष्ट्र	14,726	15,522	16,358
बंगाल	10,902	11,550	12,234
तमिलनाडु	9,486	9,870	10,269
मध्य प्रदेश	8,334	8,858	9,414
कर्नाटक	8,029	8,527	9,055
गुजरात	8,001	8,504	9,039
राजस्थान	7,536	7,996	8,483
केरल	5,682	6,189	6,748
आंध्र प्रदेश	5,901	6,251	6,620
कुल	1,42,283	1,50,842	1,59,924

सर्वाइकल कैंसर के अधिकतम मामले

राज्य	2016	2017	2018
उत्तर प्रदेश	17,156	17,420	17,687
बिहार	9,454	9,638	9,824
महाराष्ट्र	8,741	8,811	8,882
बंगाल	7,450	7,509	7,568
मध्य प्रदेश	6,222	6,322	6,423
राजस्थान	5,791	5,861	5,933
तमिलनाडु	5,452	5,443	5,432
कर्नाटक	5,020	5,074	5,130
गुजरात	4,810	4,868	4,928
आंध्र प्रदेश	4,124	4,149	4,173
कुल	99,099	1,00,306	1,01,536

पीडब्ल्यूडी के ठेकों में होगा आरक्षण : केशव

जागरण संवाददाता, मीरजापुर

- उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले, ठेकों में काकस तोड़ने को होगी आरक्षण व्यवस्था
- समाज के हर वर्ग को विकास प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व का मिलेगा अवसर

उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। फाइल

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार लोक निर्माण विभाग के ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। वे रविवार को जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के ठेकों में बने काकस को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार यह व्यवस्था लागू करेगी और इसका सकारात्मक परिणाम सामने आएगा।

उन्होंने कहा कि विभाग से ठेका निकलता है तो कुछ लोगों को ही मिल पाता है। यह सिस्टम अब खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इसका प्रारूप सामने होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी ठेकों में आरक्षण लागू करने से समाज के हर वर्ग को विकास प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि योजना के अनुसार पीडब्ल्यूडी के ठेकों में पिछड़े वर्ग को 27 फीसद, अनुसूचित जाति को 21 फीसद, अनुसूचित जनजाति को दो फीसद और सवर्णों को मिलने वाला 10 फीसद का आरक्षण शामिल होगा। उन्होंने कहा कि कोई सिविल इंजीनियरिंग करके बैठा है तो हम उन्हें ई-टेंडरिंग के माध्यम से विकल्प मुहैया कराएंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना है कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश के 20 टॉपर्स के घर तक पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगा। इस सड़क का नाम भी टॉपर के नाम पर होगा और इसका उद्घाटन भी वही करेंगे।

झूठ बोलने की ऑटोमैटिक मशीन का नाम है कांग्रेस : केशव प्रसाद मौर्य ने सीएए और एनआरसी पर हुए विरोध के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमैटिक मशीन है। देश में अफवाह फैला रही है। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों को भी आगाह किया कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया।

प्रियंका वाड्रा पर कसा तंज

कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की ट्विटर पर सक्रियता को लेकर तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्या ने उन्हें प्रियंका ट्विटर वाड्रा की उपाधि दे दी। बोले कि वे कुछ करें न करें, रोज ट्विटर पर जरूर लिखती हैं। उन्होंने प्रियंका पर हमला करते हुए कहा कि वे एक दिन कहती हैं कि पुलिस ने उनका गला दबाया, दूसरे दिन कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ।

17 योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण, एक अरब की सौगात

उपमुख्यमंत्री ने जिले में आठ योजनाओं का लोकार्पण किया और नौ योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सात करोड़ की लागत से अकोढ़ी गांव में कर्णावती नदी का पुल प्रमुख है। इसके साथ ही जिले की तीन महत्वपूर्ण सड़कों के लिए उपमुख्यमंत्री ने करीब 100 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है।

...तो क्या सक्रिय राजनीति को अलविदा कहेंगे हरीश रावत

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया में मार्मिक संदेश

हरीश रावत। फाइल

सोशल मीडिया पर अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की एक पोस्ट फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस पोस्ट की शुरुआत उन्होंने जिस तरह से की है, उसके कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं।

उन्होंने लिखा है 'हां, समय आ गया है। सक्रिय राजनीति में बने रहना कोई सामान्य निर्णय नहीं होता है। यदि आप 70 वर्ष की लक्ष्मण रेखा को पार चुके हैं तो, इस रेखा से आगे बढ़कर सक्रिय राजनीति करना सामान्य निर्णय नहीं है।' इसी पोस्ट में एक जगह उन्होंने पार्टी में युवाओं को लगातार अवसर देने का जिक्र किया है और एक अन्य जगह लोकसभा चुनावों में अपने स्थान पर अपने पुत्र का नाम प्रस्तावित करने की बात भी लिखी है। इससे उनके सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों और फिर लोकसभा चुनाव में मिली हार उन्हें कहीं न कहीं कचोटती रही है। यही कारण है कि सोशल मीडिया में लिखी पोस्ट में उन्होंने इन पराजयों का भी जिक्र किया है।

उन्होंने अपनी पोस्ट में उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि बढ़ती उम्र के साथ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति में बने रहना अत्याधिक कठिन कार्य है। उम्र के साथ आपका दायरा और आपसे अपेक्षाएं दोनों ही बढ़ जाती हैं। जबकि वास्तविकता में उम्र के साथ काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अधिक भाग दौड़ नहीं होती और आप आक्रमक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका अपवाद हैं, अनेक नाम ऐसे हैं जो ओल्ड इज गोल्ड की कहावत को सही रूप में चरितार्थ कर रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे लोगों के लिए कट ऑफ लाइन होनी चाहिए।

पहाड़ लौटे लोग दिखाएंगे उत्तराखंड सरकार को राह

केदार दत्त, देहरादून

- रिवर्स पलायन कर मिसाल पेश करने वालों से फीडबैक लेगी सरकार
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलायन आयोग मार्च में करेगा इनका सम्मेलन

पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड से दशकभर पहले जो लोग जड़ों से दूर चले गए थे, अब वापस पहाड़ लौटे वही लोग सरकार को राह दिखाएंगे। रिवर्स पलायन कर मिसाल पेश करने वालों से सरकार फीडबैक लेगी, ताकि अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने के साथ ही गांवों के विकास का खाका खींचा जा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर पलायन आयोग अगले वर्ष मार्च में उन लोगों का सम्मेलन करने जा रहा है, जिन्होंने पहाड़ लौटकर तरक्की की इबारत लिखी है।

उत्तराखंड से हो रहे पलायन की भयावहता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1702 गांव अब तक निर्जन हो चुके हैं। ऐसे गांवों की भी बड़ी तादाद है, जहां आबादी अंगुलियों में गिनने लायक रह गई है। बेहतर भविष्य की आस में पलायन का सिलसिला अभी भी नहीं थमा है।

बावजूद इसके ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों से न सिर्फ वापस लौटे, बल्कि खुद के बूते पहाड़ में रोजगार भी कर रहे हैं। पहाड़ लौटे इन लोगों उस धारणा को तोड़ने का काम किया है, जिसमें कहा जाता था कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता।

लंबे इंतजार के सरकार का ध्यान इनकी तरफ गया है और उसने इनके अनुभवों का लाभ उठाने की ठानी है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.एसएस नेगी बताते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिवर्स पलायन कर पहाड़ लौटे लोगों का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अगले साल मार्च में होने वाले इस सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

डॉ.नेगी के अनुसार अभी तक ऐसे 150 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है, जो एक दशक पहले पलायन कर गए थे और अब वापस लौटे हैं। इनमें कुछ ऐसे भी है, जो विदेश से वापस आए हैं। सम्मेलन में ये सभी अपने अनुभव साझा करेंगे। फिर इनके अनुभव व सुझावों को लेकर आगे की कार्ययोजना का खाका खींचा जाएगा। यही नहीं, इनकी सफलता की कहानी भी लोगों से साझा की जाएगी।

अभद्रता मामले में केरल के राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब किया

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : भारतीय इतिहास कांग्रेस (आइएचसी) में अपने साथ हुई अभद्रता के एक दिन बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने राज्य के मुख्य सचिव टॉम जोस को राजभवन तलब किया। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि रविवार को मुख्य सचिव ने राज्यपाल से मुलाकात की। हालांकि, उनके बीच क्या बात हुई, इसके बारे में जानकारी नहीं पाई है। इस बीच, माकपा ने राज्यपाल पर आइएचसी में राजनीतिक भाषण देने का आरोप लगाया है।

राज्यपाल ने शनिवार को आइएचसी का उद्घाटन किया था। अपने संबोधन में जब उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर पहले के वक्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना शुरू किया तो जाने-माने इतिहासकार इरफान हबीब समेत कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। इरफान हबीब मंच पर उठकर उनके पास चले आए थे और उन्हें जबरन बोलने से रोकने की कोशिश की थी। राज्यपाल के एडीसी और सुरक्षा अधिकारी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें धक्का भी दे दिया था। राज्यपाल ने खुद ट्वीट कर हबीब के व्यवहार के बारे में बताया था।

आइएचसी का आयोजन कन्नूर विश्वविद्यालय में हुआ था। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गोपीनाथ रविंद्रन ने माना है कि राज्यपाल के खिलाफ हुए प्रदर्शन में प्रोटोकाल का उल्लंघन हुआ था। उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले वक्ताओं में इरफान हबीब का नाम नहीं था।

हालांकि, हबीब ने प्रोटोकाल के उल्लंघन के आरोपों को नकारा है। उन्होंने प्रतिनिधियों और छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिए राज्य की माकपा नीत सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच, सत्तारूढ़ माकपा ने राज्यपाल पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तरह बर्ताव नहीं करने का आरोप लगाया है।

माकपा के राज्य सचिव के. बालाकृष्णन ने कहा कि हर व्यक्ति को राजनीति गतिविधियों में शामिल होने का हक है। अगर राज्यपाल जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा को नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें पद छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में उतर जाना चाहिए। माकपा नेता ने कहा कि राज्यपाल ने आइएचसी में पहले से तैयार अपने भाषण को पढ़ने की जगह राजनीतिक भाषण दिया था।

- कन्नूर विवि के कुलपति ने मानी प्रोटोकाल उल्लंघन की बात, हबीब ने नकारा
- राज्यपाल ने खुद ट्वीट कर हबीब के व्यवहार के बारे में बताया था
- सत्तारूढ़ माकपा ने आरिफ मुहम्मद खान पर राजनीतिक भाषण देने का लगाया आरोप

आरिफ मुहम्मद खान। फाइल

70 करोड़ लोगों को पूरी दुनिया में 2030 तक सिर्फ पानी की कमी की वजह से विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल 78.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है।

रोशन किया अमिताभ से लेकर अंबानी तक का आशियाना

हुगली के चंदननगर स्थित अपने वर्कशाप में बाबूपाल। जागरण

विनय कुमार, कोलकाता

जनसंख्या नियोजन

- चंदननगर के लाइट आर्टिस्ट बाबू पाल की आलोक-सज्जा
- अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी में भी दिखाई थी बत्तियों की अद्भुत कारीगरी
- अपने बूते खड़ा किया कारोबार, दे रहे 40 लोगों को रोजगार

बंगाल के हुगली जिले का छोटा सा शहर चंदननगर। एक समय फ्रांसीसी उपनिवेश रहा चंदननगर आज अपनी जगद्धात्री पूजा व प्रकाश-सज्जा (लाइटिंग) के लिए देश-दुनिया में मशहूर है। यहां की बत्तियों से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के आशियाना 'जलसा' से लेकर देश के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी का गगनचुंबी आवास तक खास मौकों पर रोशन हो चुका है। यही नहीं, बॉलीवुड की चर्चित अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने 2018 में जब जोधपुर में शादी रचाई थी, तब चंदननगर की बत्तियों से ही उम्मेद भवन पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया था।

यह अद्भुत जगमगाहट लाइट आर्टिस्ट सुप्रीम कुमार पाल उर्फ बाबू पाल के बूते ही संभव हो पाई थी। चंदननगर के लोगों के लिए उनके अपने बाबू दा। उन्होंने अपने बूते यह मुकाम बनाया और आज 40 लोगों को रोजगार मुहैया कर रहे हैं।

जब भी चंदननगर की बत्तियों की चर्चा होती है तो पहला नाम सुप्रीम कुमार पाल का ही आता है। बाबू पाल के वर्कशाप में तैयार बत्तियों का वाकई जवाब नहीं है, तभी तो देश-विदेश में इसकी आपूर्ति होती है। कोलकाता में दुर्गा पूजा से लेकर पार्क स्ट्रीट में क्रिसमस के मौके पर अद्भुत थीम वाली बत्तियों की जो जगमगाहट दिखती है, वह बाबू पाल की ही देन है।

2016 की दीपावली में बिग बी के घर में बिखेरी थी रोशनी: 58 साल के बाबू पाल ने बताया कि 'मैंने 2016 की दीपावली में अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को मांगलिक थीम से सजाया था। 2017 में मुकेश अंबानी के निवास स्थल 'एंटीलिया' के गलियारे की प्रकाश-सज्जा की। इसके बाद अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की शादी में भी बत्तियों की कारीगरी दिखाने का मौका मिला।'

उन्होंने आगे कहा 'यह ऐसा काम है, जिसमें रचनात्मकता बहुत जरूरी है। बत्तियों से थीम तैयार करने पर काफी ध्यान देना पड़ता है। मेरी अपनी एक क्रिएटिव टीम है। हम किसी भी थीम पर काम शुरू करने से पहले काफी विचार-विमर्श करते हैं ताकि कुछ अलग किया जा सके।'

विदेश में भी बिखेर रहे रोशनी

बाबू पाल की रोशनी का जलवा विदेश में भी है। 1998 में उन्हें दुबई में हुए शॉपिंग फेस्टिवल के लिए काम करने मौका मिला। उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति की थीम पर प्रकाश-सज्जा की थी। इसी तरह इटली के दूतावास को भी आलोकित किया। दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया है। अब केन्या से ऑफर मिला है।

यूं आ गए प्रकाश-सज्जा की दुनिया में: बाबू पाल का प्रकाश-सज्जा की दुनिया में आना महज संयोग था। उन्होंने बताया कि मेरी तीन पीढ़ी लोहा व्यवसाय से जुड़ी थी। मेरी अपने खानदानी कारोबार में दिलचस्पी नहीं थी। मैं कुछ नया करना चाहता था।

मेरे एक मित्र ने मुझे इस पेशे से अवगत कराया। यह हुनर मुझे विरासत में नहीं मिला। इसे सीखने और इस क्षेत्र में कदम जमाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में परेशानियां भी आईं लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

रोशनी के शहर के 'सुप्रीम': चंदननगर के बोरो चापातल्ला इलाके के रहने वाले सुप्रीम कुमार पाल का घर के पास एक बीघा में फैला वर्कशाप है, जहां वह 40 लोगों की टीम के साथ काम करते हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। चंदननगर में 150 से अधिक पंजीकृत लाइट आर्टिस्ट हैं। यहां सालभर में लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि पहले बरात में प्रयोग में लाए जाने वाली गैस लाइट की उत्पत्ति यहीं हुई थी।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

पांच बेजुबान अपने हुनर के चिराग से चला रहे दुकान

जागरण विशेष

सैयद नकी इमाम, पटना

- बिहार में फुलवारीशरीफ में है चिराग टेलर्स नाम से दुकान
- बोलने में असमर्थ होने से शुरू में कपड़े का नाप लेने व बातचीत में आती थी दिक्कत

फुलवारीशरीफ (पटना) के पांच दोस्तों की जुबां तो नहीं है, मगर इनका हुनर बोलता है। पांचों यहां चिराग टेलर्स नाम से दुकान चलाते हैं। इनकी दिव्यांगता कभी इनकी काबिलियत के आड़े नहीं आई। इस दुकान से ही इनका परिवार चल रहा है। ये पांच दोस्त- मुनव्वर, शमशेर, अरमान, गोल्डेन और आमिर हैं। इनमें सबसे पहले सिलाई का काम मुनव्वर ने सीखा। वह फुलवारीशरीफ के ही किसी टेलर के यहां काम करते थे। कुछ दिन में यहां शमशेर भी उनका हाथ बंटाने लगे। दोनों ने जब काम सीख लिया तो चांद कॉलोनी में एक दुकान खोल ली। बोलने में असमर्थ थे, इसलिए कपड़े का नाप लेने और बातचीत में दिक्कत आती थी। ऐसे में इन्होंने आसपास के टेलर से संपर्क किया। यह सभी नामचीन टेलर की दुकान से कटा हुआ पैंट-शर्ट ले कर आते और आराम से उसकी सिलाई कर फिर पहुंचा देते। इन दोनों बेजुबां दोस्तों के कपड़े सिलने की बात सुनकर फुलवारीशरीफ के ही अरमान, गोल्डेन और आमिर भी इनके साथ आ गए। धीरे-धीरे इनका काम बढ़ने लगा और चर्चा दूर-दूर तक होने लगी। ऐसे में सभी ने दुकान का नाम चिराग टेलर्स रख लिया और ग्राहकों से सीधे काम लेने लगे।

घर के काम में भी बंटाते हैं हाथ : शमशेर की पत्नी बेबी कहती हैं, वह बोल नहीं सकते मगर कामकाज में कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। सिलाई के अलावा घर के काम में भी हाथ बंटाते हैं। बच्चों को स्कूल लाने से लेकर बाजार जाने तक सारा काम करते हैं। मुनव्वर की पत्नी रानी कहती हैं, खुदा ने आवाज नहीं दी मगर सोचने समझने की क्षमता तो आम लोगों से ज्यादा है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

इकबाल नाप लेकर काटते हैं कपड़े

इन पांच दोस्तों की दुकान पिछले एक दशक से चल रही है। ये सभी सिलाई-कढ़ाई में तो मास्टर हैं, मगर एक समस्या ग्राहकों से संवाद करने की आ रही थी। इसका समाधान बनकर आए- नया टोला के मास्टर इकबाल अहमद। इकबाल बोल-सुन सकते हैं और इन पांचों दोस्तों की दुकान पर ही रहते हैं। इनका काम ग्राहकों से बातचीत करना, उनके कपड़े की नाप लेना और फिर उस हिसाब से कपड़े काटना है। तय नाप के हिसाब से कटे हुए कपड़े मिलने के बाद ये पांचों दोस्त उसे सिलने का काम करते हैं। इकबाल कहते हैं, इन सभी के पास स्मार्टफोन भी है। कभी किसी ग्राहक को खास डिजाइन बताना होता है तो वे वाट्सएप पर तस्वीर भेज देते हैं।

दुकान में सिलाई करता आमिर(दाएं), मुनव्वर आलम(बाएं)। पीछे कपड़ा लेकर खड़े अरमान और शमशेर। जागरण

विरोधाभास ▶ टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद भी मध्य प्रदेश में नहीं सुधरे हालात

सवालों के घेरे में बाघों की सुरक्षा

जागरण पड़ताल

इस वर्ष ही राज्य में 28 बाघों की हुई मौत, सात का हुआ शिकार

मनोज तिवारी, भोपाल

टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार बाघों की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं हो पाई है। राज्य में इस वर्ष एक जनवरी से 25 दिसंबर तक 28 बाघों की मौत हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें सिर्फ सात बाघों की सामान्य मौत हुई। सात बाघों का शिकार हुआ, जबकि 14 बाघों की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं।

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाघों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए भरोसा दिया था कि अब अनदेखी या लापरवाही से बाघों की मौत नहीं होगी। इसके बाद राज्य में आठ बाघों की मौत हो चुकी है। टाइगर इस्टीमेशन-2018 के तहत गिनती में देश में सर्वाधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए। इसके बाद इसे टाइगर स्टेट का तमगा तो मिल गया, लेकिन बाघों की मौत का सिलसिला नहीं थमा।

जंगल में आराम फरमाता बाघ (फाइल फोटो) सौजन्य : एमपीटूरिज्म

देश में मप्र अकेला राज्य है, जो प्रत्येक बाघ, तेंदुआ और भालू की मौत की सूचना तत्काल देता है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता इसलिए वहां के आंकड़े कम आ रहे हैं। हमने सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया है। इसी का नतीजा है टाइगर स्टेट का तमगा।

डॉ. यू. प्रकाश, वन बल प्रमुख एवं चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन, मप्र

चार साल में प्रदेशों में बाघों की मौत का विवरण

प्रदेश	2016	2017	2018	2019	2018 में बाघ
मध्य प्रदेश	30	28	24	28	526
कर्नाटक	15	14	16	11	524
उत्तराखंड	06	15	08	06	442
महाराष्ट्र	14	17	17	18	312
तमिलनाडु	07	03	06	07	264
केरल	00	02	05	01	190
उत्तर प्रदेश	00	07	07	04	173
ओडिशा	00	01	02	00	028

लगातार चौथे साल देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत मप्र में हुई है। इसके पहले आठ साल तक टाइगर स्टेट रहे कर्नाटक में इस साल 11 बाघ मरे। यहां 2018 की गणना में 524 बाघ पाए गए हैं।

अफसरों के तर्कों से सहमत नहीं विशेषज्ञ

बाघ विशेषज्ञ वन विभाग के अफसरों के तर्क से सहमत नहीं हैं। वह कहते हैं कि पिछले आठ साल कर्नाटक टाइगर स्टेट रहा, लेकिन हर साल वहां बाघों की मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश से कम रहा है। ऐसे में अफसरों का यह तर्क कि बाघ ज्यादा होंगे, तो मौत का आंकड़ा भी ज्यादा रहेगा, उचित नहीं है।

सरकार का पर्यटन पर फोकस : वन विहार और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के निदेशक रह चुके सेवानिवृत्त आइएफएस जगदीश चंद्रा कहते हैं कि सरकार बड़े व्यावसायिक घरानों के हितों की पूर्ति कर रही है। उसकी प्राथमिकताओं में पर्यटन है, वन्यप्राणियों की सुरक्षा नहीं। इसलिए सिर्फ पर्यटन की बात हो रही है। बाघ शिकार के मामलों में सजा का प्रतिशत कम है। मास्टरमाइंड पकड़ में नहीं आते। कोर्ट में मजबूती से केस पेश नहीं होते। लोग जहर देकर, करंट और फंदा लगाकर बाघों को मार रहे हैं। बाघों का आपसी संघर्ष बताता है कि जंगलों में उनके खाने का संकट है। चंद्रा कहते हैं कि वन विभाग के अफसर नियंत्रणहीन हो गए हैं इसलिए ऐसे हालात बने हैं।

भय बिन होय न प्रीत : वन्यप्राणियों के जानकार अजय दुबे कहते हैं कि प्रदेश में बाघों की साइलेंट किलिंग हो रही है। शाकाहारी जानवरों के शिकार के लिए लोग करंट लगाते हैं और बाघ मारे जाते हैं। ऐसे मामलों में विभाग आरोपित पर दया दिखाता है। दुबे कहते हैं कि जब तक भय नहीं होगा, शिकार का सिलसिला चलता रहेगा। वन्यप्राणियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता के मामले में भी विभाग फिसड्डी है। तीन माह में चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है।

100 रूटों पर चलाई जाएंगी 150 निजी ट्रेनें : सीआरबी

प्रतीकात्मक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : रेलवे बोर्ड के चेयरमैन (सीआरबी) विनोद कुमार यादव ने कहा कि 2022 से भारतीय रेलवे के 100 रूटों पर 150 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड स्तर पर जोर-शोर से तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में आम लोगों को ट्रेनों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे मांग के अनुसार ट्रेनें और मालगाड़ियां चलाएगा।

वह शनिवार को पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल और उनकी टीम के साथ 'जीएम निरीक्षण स्पेशल ट्रेन' से वाराणसी- बलिया-छपरा रेलमार्ग का निरीक्षण करने के बाद गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर जंक्शन पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और बेहतरी के लिए ही निजी ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन आपरेशन और सेफ्टी रेलवे के हाथों में ही होगा। इधर, दिल्ली से मुंबई, कोलकाता और पटना आदि के लिए ट्रेनों की मांग बढ़ गई है, लेकिन अभी नई ट्रेनों के लिए रेललाइनों पर जगह ही नहीं है। इसके लिए हम सिर्फ मालगाड़ियों के लिए फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर दिसंबर 2021 तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सभी मालगाड़ियां फ्रेट कॉरिडोर पर ही चलेंगी। ऐसे में यात्री ट्रेनों के लिए हमारी लाइनें खाली हो जाएंगी।

ट्रेनों को मिलेगी 160 की स्पीड : रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि यात्री ट्रेनों के लिए भारतीय रेल लाइनों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 13 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिस पर ट्रेनें 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी।

रेलवे की बेहतरी के लिए हुआ है सेवाओं का एकीकरण

चेयरमैन ने कहा कि रेलवे की सेवाओं का एकीकरण बेहतरी के लिए हुआ है। आने वाले दिनों में अधिकारी अपने विभाग के बारे में ही नहीं बल्कि समग्र रेलवे और उसके विकास के बारे में सोचेंगे। अब सब रेलवे के अधिकारी होंगे, न कि विभिन्न (इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, कार्मिक, वाणिज्य, लेखा आदि) विभागों के। एकीकरण से वरिष्ठता और पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

मुसीबत मंडराएगी तो अब 'सैंडल' बचाएगी

मुहम्मद रईस, वाराणसी

- युवा श्याम चौरसिया ने बनाई स्मार्ट सैंडल, इसमें लगा स्विच दबाते पुलिस तक पहुंचेगी सूचना

आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा एवं दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो जाती हैं जो समाज को शर्मसार कर देती हैं। ऐसे में तकनीक के सहारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए नवाचार की पहल की बनारस के होनहार युवा इनोवेटर श्याम चौरसिया ने। उन्होंने सैंडल में फिट होने वाली ऐसी तकनीक ईजाद की है, जिससे मुसीबत में फंसी महिलाएं पांव के इशारे से भी पुलिस बुला सकेंगी। श्याम ने सैंडल की सोल में सेंसर डिवाइस फिट कर बना दिया 'स्मार्ट एंटी रेप सैंडल'। इसे पहनने के बाद मुसीबत के समय महिलाओं को न तो पर्स से स्मार्ट फोन निकालने की जरूरत होगी, न इमरजेंसी नंबर डायल करने की। उन्हें पांव की अंगुलियों से सैंडल में बने स्विच को लगातार दो बार दबाना होगा। ऐसा करते ही ब्लूटूथ के माध्यम से स्मार्ट फोन अनलॉक होकर खुद-ब-खुद 112 नंबर या आखिरी डायल नंबर डायल कर मदद बुला लेगा। घटनास्थल की ऑडियो रिकार्डिंग भी परिजनों के मोबाइल में होती रहेगी। स्वीकृति के लिए सेंसर डिवाइसयुक्त यह तकनीक आइआइटी-बीएचयू स्थित इंक्यूबेशन सेंटर में भी प्रस्तुत की गई है।

तीन माइक रिकॉर्ड करेंगे आवाज

सैंडल में लगे तीन माइक के माध्यम से फोन के दूसरी ओर महिला व वहां मौजूद लोगों एवं आसपास की आवाज स्पष्ट सुनी जा सकती है। 2500 एमएएच लीथियम ऑयन बैटरी लगी होने से एक बार चार्ज करने पर यह करीब चार से छह माह तक काम करेगा। श्याम के मुताबिक इसे तैयार करने में चार महीने का समय और करीब 9500 रुपये खर्च आया।

वाराणसी में स्मार्ट सैंडल का डेमो प्रस्तुत करते श्याम चौरसिया। जागरण

ऐसे काम करती स्मार्ट सैंडल : सैंडल में लगे वायरलेस (ब्लूटूथ) सेंसर डिवाइस को ब्लूटूथ के जरिए स्मार्ट फोन से जोड़ना होता है। अंगूठे के पास दिए एक छोटे से स्विच को दो बार दबाने पर जेब या पर्स में रखा मोबाइल अनलॉक होने के संग आखिरी डायल नंबर अपनेआप मिला देगा।

शुगर फ्री पेड़ा और एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे इंदौर-भोपाल दुग्ध संघ

नईदुनिया, इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल सहकारी दुग्ध संघ अब शुगर फ्री पेड़ा भी बनाएंगे। इसकी शुरआत नए साल में संक्रांति के दिन से की जाएगी। इसी तरह बच्चों और युवाओं को ध्यान में रखते हुए एनर्जी ड्रिंक की तरह विटा मिल्क पाउडर भी बनाया जाएगा। यह ड्रिंक कई तरह के विटामिंस और प्रोटीन से भरपूर होगा। इसकी शुरआत भी दो-तीन महीनों में होने की संभावना है।

दोनों नए उत्पादों को लेकर दुग्ध संघ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है। शुगर फ्री पेड़ा ट्रॉयल के दौर में है। सांची की प्रयोगशाला में इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस पेड़े में शक्कर की जगह वेजिटेबल ओरिएंटेड वैकल्पिक मिठास मिलाई जाएगी। सामान्य शक्कर में अधिक कैलोरी होती है, लेकिन शुगर फ्री पेड़ा लो कैलोरी वाला होगा, जो डायबिटीक मरीजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दुग्ध संघ के मुख्य अधिकारी एएन द्विवेदी ने बताया कि यह प्रयोग डेयरी उत्पादों में नवाचार का हिस्सा है।

अब पैदा होने से पहले तय होंगे बच्चों के संस्कार

संजय तिवारी, सुलतानपुर

बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें संस्कार दिए जाने की प्रथा अब तक पुराणों में रही है। अब विश्वविद्यालयों में इसके लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह गर्भाधान संस्कार कोर्स के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश में अवध विश्वविद्यालय पहला विवि होगा जो नौ जनवरी को इस संस्कार को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुमति देगा।

एक वर्ष का होगा डिप्लोमा कोर्स : अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. मनोज दीक्षित कहते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। अभी एक साल का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें गर्भ धारण के पूर्व व बाद में बरती जाने वाली सावधानियां, चिकित्सीय परीक्षण व सलाह, रहन-सहन, खान-पान, पहनावा के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस दौरान जीवनोपयोगी विभिन्न साहित्यों के पढ़ने की आदत डालने आदि विषय कोर्स में शामिल रहेंगे। 2020-21 से शिक्षण कार्य आरंभ हो जाएगा। इसकी सफलता के मूल्यांकन के बाद तीन व छह माह के सर्टिफिकेट कोर्स का भी संचालन शुरू कराने पर विचार होगा।

सभी कर सकेंगे अध्ययन : कुलपति डॉ. दीक्षित के अनुसार वे महिलाएं और पुरुष भी पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं, जो इस ज्ञान को समाज में साझा करना चाहते हैं या स्वयं की संतान को निरोगी व श्रेष्ठ बनाने के इच्छुक हैं।

सोलह संस्कारों में से एक है गर्भाधान संस्कार

हिंदू समाज में 16 संस्कारों की चर्चा है, जिसमें गर्भाधान पहला संस्कार है। इसके बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, कर्णवेध, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह व अंत्येष्टि संस्कार है।

प्रकृति

ऋषिकेश बैराज व सप्तऋषि के पास डेरा डाले हुए हैं हजारों प्रवासी परिंदे, मेहमान परिंदों में जल काग व रूडी शेलडक (सुर्खाब) की संख्या सर्वाधिक

प्रवासी परिंदों के कलरव से गूंजे ऋषिकेश के गंगा तट

दीपक जोशी, रायवाला (देहरादून)

वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर। ठंड बढ़ने के साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व (सीटीआर) में मेहमान परिंदों का आगमन शुरू हो गया है। ऋषिकेश बैराज व सप्तऋषि के पास गंगा नदी के तट प्रवासी परिंदों के कलवर से गुंजायमान हैं। इन स्थानों पर कई प्रजाति के हजारों प्रवासी परिंदों ने डेरा डाला हुआ है।

जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर, गौहरी और चीला रेंज के बीच गंगा तट पर प्रवासी परिंदों का जमघट लगता जा रहा है। कई स्थानों पर मौजूद इन मेहमानों को आप पूरे दिन पानी में अठखेलियां और तट पर विश्राम करते देख सकते हैं। इनमें जल काग व रूडी शेलडक (सुर्खाब) सबसे ज्यादा संख्या में हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी परिंदों की आमद से जहां पक्षी प्रेमी खुश हैं, वहीं सीटीआर के पर्यटन व्यवसाय को भी पंख लगने की उम्मीद है।

'सीटीआर की विभिन्न रेंजों में करीब 20 प्रजाति के तीन हजार से अधिक प्रवासी परिंदे आ चुके हैं। अभी इनकी संख्या और बढ़ेगी। यह मार्च तक यहां प्रवास करते हैं और इस दौरान अपना परिवार भी बढ़ाते हैं। परिंदों के आगमन को देखते हुए चौकसी बढ़ाई गई है।'

-दिनेश प्रसाद उनियाल, वन्य जीव प्रतिपालक, सीटीआर, देहरादून

मध्य एशिया से आते हैं परिंदे : शीतकाल में मध्य एशिया से हजारों किमी का सफर तय कर विभिन्न प्रजाति के परिंदे सीटीआर में प्रवास के लिए आते हैं। नंवबर से लेकर मार्च आखिर तक ये यहां रहते हैं। इनमें चकोर, वॉल क्रीपर, सैंड पाइपर, जल काग, सुर्खाब व साइबेरियन पक्षी मुख्य हैं। पार्क क्षेत्र में यह ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारों पर प्रवास करते हैं।

ऋषिकेश के गंगा तटों पर प्रवासी परिंदे पहुंच रहे हैं। गंगा में अठखेलियां करते साइबेरियन वाटर क्रो। फोटो : साभार- वन विभाग

मछलियां तो सौगात हैं, असली मिशन पानी उपलब्ध कराना है

ब्रजेश पाठक, सासाराम (रोहतास)

मिशन मछली पालन ही नहीं, बल्कि कैमूर पहाड़ी पर बसे उन हजारों वनवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, जिसके अभाव में वे असमय ही काल के गाल में समा रहे। यह मुहिम है रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के बांदू निवासी रीतेश पांडेय की। 'जागो किसान जागो' मिशन से जुड़कर उन्होंने अब तक पांच दर्जन से अधिक तालाबों का निर्माण करा भूजल स्तर को ऊपर लाने में कारगर भूमिका निभाई है।

रीतेश कहते हैं, पहाड़ी पर बसे गांवों में पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए उन्होंने किसानों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया। इलाके की महिलाएं पहले पांच कोस दूर पहाड़ की तलहटी से निकले चुआं (गड्ढानुमा सरंचना) से पानी लाती थीं। रीतेश के प्रयास से स्थिति सुधरी है। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी कंपनी में नौकरी कर रहे रीतेश को महानगरों की चकाचौंध नहीं लुभा सकी। उन्होंने नौकरी छोड़कर जल संरक्षण को जीवन का ध्येय बना लिया और जिले के नक्सल व सूखा प्रभावित नौहट्टा प्रखंड की सुदूर अमरखा पहाड़ी के पास 15 तालाबों का निर्माण करा जल संरक्षण के अग्रदूत बन गए।

रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के बांदू निवासी रीतेश पांडेय। फाइल फोटो।

सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद करें गैर-टेलीकॉम कंपनियां

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्पष्ट कहा है कि गैर-टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर से कोई भी राहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। हाल ही में विभाग ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) मद के बकाया भुगतान के लिए गैस यूटिलिटी कंपनी गेल लिमिटेड को नोटिस भेजा था। गेल ने विभाग को इसका जवाब भेज दिया है। विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम उनके जवाब का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर ही पूछना होगा कि उसके फैसले में ऐसी गैर-टेलीकॉम कंपनियों को शामिल किया गया है या नहीं। (प्रेट्र)

सीएनजी और पीएनजी नेटवर्क 400 जिलों तक पहुंच जाने के बाद गैस की खपत में तेज इजाफा होगा। हमने मांग और इन्फ्रा की जरूरत के अध्ययन के लिए आइसीएफ को नियुक्त किया है।

— डीके सर्राफ, चेयरमैन, पीएनजीआरबी

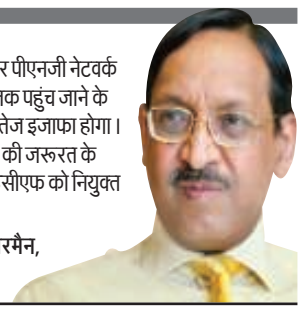

अगले वर्ष देश की इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में अहम होगा बजट

साक्षात्कार

केंद्र की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पूरे साल का अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। उद्योगों को इस बजट से बहुत आस है। अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लाने में बजट को सबसे अहम माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था से जुड़े इन सभी पहलुओं पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख **नितिन प्रधान** ने पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स के प्रेसिडेंट **डीके अग्रवाल** से लंबी बातचीत की। पेश हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश :

● अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति को कैसे देख रहे हैं?

-देखिए, सब जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन सरकार ने बीते दिनों में कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनका असर दिख रहा है। जैसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसे आमूल-चूल बदलाव कह सकते हैं। पहले लोग बैंकों से लोन लेते थे और उसका मनचाहा इस्तेमाल करते थे। बैंक से फिर लोन लेकर पहले वाले लोन का भुगतान कर देना एक आदत सी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो पाना छोटी अवधि के लिए दिक्कत पैदा जरूर कर रही है। लेकिन लंबी अवधि के लिए यह अच्छी बात है।

कारोबारियों के लिहाज से दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि अब आपको टैक्स देना ही होगा। सरकार अब फेसलैस स्क्रूटनी की शुरुआत कर रही है। जीएसटी आ गया है। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए अब चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इन्डायरेक्ट, लोगों के लिए कर चोरी करना मुश्किल होगा। ये दो ऐसे बड़े बदलाव हैं जिनका असर आ रहा है। लंबी अवधि में ये दोनों कदम देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालेंगे।

● अर्थव्यवस्था को कब तक मंदी से बाहर आने की उम्मीद कर रहे हैं?

-देखिए, हमें लगता है कि अगला वर्ष इस मायने में महत्वपूर्ण होगा। यह वर्ष 'पीरियड ऑफ रिवाइवल' यानी उबरने की अवधि साबित होगा। शॉर्ट टर्म रिवाइवल के संकेत अगली तिमाही से मिलने शुरू हो जाएंगे। यहां से हम बेहतर की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सरकार कदम उठा रही है। लेकिन इनमें फरवरी में पेश होने वाला बजट अहम भूमिका निभाएगा।

● उद्योगों के लिए क्या दिक्कते रहीं?

-एक दिक्कत बैंकों की तरफ से कर्ज की कमी की है। बैंकों में घबराहट है। फैसला गलत हो जाने की चिंता उन्हें उद्योगों को कर्ज देने से रोक रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक अधिकारियों की इस घबराहट को दूर करने की बहुत अच्छी पहल की है। वित्त मंत्री ने भी शनिवार को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक में इस चिंता को दूर करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इससे लोन देने की प्रक्रिया बेहतर होगी। एनबीएफसी की तरफ से भी लिक्विडटी की समस्या बनी हुई है। यही वजह है कि कर्ज की रफ्तार 58 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है।

● ऐसे माहौल में सरकार और उद्योग जगत को क्या करना होगा?

-सबसे पहले तो देश में खपत को बढ़ाने की जरूरत है। खपत बढ़ाने के लिए सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिससे लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़े। अभी सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण सेक्टर में है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की खरीदारी और उपभोग क्षमता कैसे बढ़े, यह सबसे अहम है। ऐसा उपाय होना चाहिए कि उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ाई जाए।

● क्या पीएचडी चैंबर ने इसके लिए सरकार को कोई सुझाव दिया है?

-जी हां हमने काफी सुझाव दिए हैं। जहां तक खपत बढ़ाने के उपायों का सवाल है, हमारा मानना है कि सरकार को पांच लाख रुपये तक की आय सबके लिए टैक्स फ्री कर देनी चाहिए। इसके अलावा हमने इनकम टैक्स स्लैब में भी परिवर्तन का सुझाव भी दिया है।

एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए हमारी मांग है कि एमएसएमई क्षेत्र में प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी और पार्टनरशिप कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए टैक्स में पांच परसेंट का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट सरकार दे। साथ ही जिस तरह रियल एस्टेट के लिए सरकार ने एक फंड बनाया है। उसी तरह दबाव झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार कम से कम 25 हजार करोड़ रुपये का एक फंड बनाए जिससे उन्हें गिरवी-मुक्त फंड मुहैया कराया जा सके।

● फंड के अतिरिक्त उद्योग के समक्ष अभी और क्या दिक्कते हैं?

-सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभियान के तहत देश में कारोबार करना काफी आसान बनाया है। लेकिन यह अभी दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। प्रदेशों में इसे लेकर काम चल रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि राज्यों में जिला स्तर पर प्रशासन के बीच स्पर्धा शुरू की जानी चाहिए कि वहां भी बिजनेस की शुरुआत करने का काम कारोबारियों के लिए आसान हो सके। दूसरी बात यह कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मकसद केवल सिंगल विंडो क्लीयरेंस मुहैया करा देने से पूरा नहीं होता। उसके तहत मंजूरी लेने के लिए समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। इसलिए हमारा सुझाव है कि सिंगल विंडो से क्लीयरेंस मिलने की समय-सीमा तीन महीने तय हो जानी चाहिए। साथ ही प्रत्येक राज्य सरकार के पास एक लैंड बैंक होना चाहिए ताकि उद्योगो को तुरंत जमीन मिल सके।

न्यूज गैलरी

कोयला आयात में हुई चार प्रतिशत बढ़ोतरी

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष में नवंबर आखिर तक कोयला आयात 4 .4 प्रतिशत बढ़कर 16 .14 करोड़ टन पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष समान अवधि में यह 15 .45 करोड़ टन रहा था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कोयला आयात 23 .5 करोड़ टन पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। टाटा ग्रुप और सेल के संयुक्त उपक्रम एमजंक्शन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में कोयला आयात में 0 .8 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। (प्रेट्र)

चालू वित्त वर्ष में ही जारी होगी ई-कॉमर्स नीति

नई दिल्ली : उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव गुरुप्रसाद मोहापात्र ने कहा है कि ई-कॉमर्स और नई औद्योगिक नीतियों पर विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, 'मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि दोनों नीतियां चालू वित्त वर्ष के अंत तक जारी कर दी जाएंगी।' मोहापात्र का कहना था कि विभाग ने इन दोनों नीतियों को लेकर साझेदारों से कई दौर की वार्ताएं की हैं। गौरतलब है कि सरकार ने इस वर्ष फरवरी में ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया था। कई विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने इसके कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। (प्रेट्र)

संकेत ▶ अगले वित्त वर्ष में बैंकों को होगी और मदद की जरूरत

सरकारी बैंकों को फिर मिलेगी बजटीय मदद

पिछले 5 वर्षों में पीएसयू बैंकों को मिली है 2 .98 लाख करोड़ रुपये की सहायता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले पांच वित्त वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 2.98 लाख करोड़ रुपय की वित्तीय मदद दे चुकी केंद्र सरकार इन पर फिर दरियादिली दिखाने को तैयार है। असल में सरकार के पास कोई रास्ता भी नहीं है। वर्तमान आर्थिक सुस्ती के चलते बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने चालू वित्त वर्ष में चार सरकारी बैंकों में छह अलग-अलग बैंकों के विलय का फैसला किया है। इस स्थिति में कई बैंक बगैर बजटीय सहायता के आरबीआइ के मानकों के मुताबिक अपनी पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बरकरार नहीं रख सकेंगे। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैंकिंग सेक्टर की हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम बजट से किए जाने की उम्मीद है।

दो दिन पहले देश के वित्तीय सेक्टर की दशा व भावी दिशा पर आरबीआइ की तरफ से जारी फाइनेंशियल सेक्टर स्टैबिलिटी रिपोर्ट इस तरह इशारा करती है कि बिना अतिरिक्त पूंजी दिए अगले वित्त वर्ष भी सरकारी बैंकों का काम नहीं चलने वाला है। रिपोर्ट ने मंदी की वजह से फंसे कर्जे (एनपीए) के स्तर के 9.3 से बढ़कर सितंबर, 2020 तक 9.9 फीसद हो जाने का खतरा बताया है। एनपीए ज्यादा बढ़ने की वजह से बैंकों को अपने मुनाफे से ज्यादा राशि का समायोजन करना पड़ेगा, इसका असर उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (सीएआर) पर पड़ेगा। सीएआर बैंकों की परिसंपत्तियों और पूंजी का अनुपात है और इसका ज्यादा होना बैंकों की मजबूती व जोखिम सहने की उनकी क्षमता को बताता है। आरबीआइ के नियम के मुताबिक सरकारी बैंकों के लिए यह 12 फीसद होनी चाहिए। आरबीआइ की पिछले शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक सभी सरकारी बैंकों को मिलाकर यह अनुपात अभी 13.5 फीसद है, जो वित्त वर्ष के शुरुआत में यह 12.2 फीसद था। लेकिन इसकी बेहतर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने इन्हें 70 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराया है।

अतरिक्त पूंजी के दिए जाने के बावजूद तीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीएआर नौ फीसद से कम है। लेकिन फंसे कर्जे की स्थिति बिगड़ने से छह बैंक ऐसी स्थिति में फंस सकते हैं। सीएआर का स्तर उचित नहीं होने से ये बैंक ज्यादा कर्ज भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए भी जरूरी है कि सरकारी बैंकों को बजट से मदद दी जाए। इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए खपत बढ़ाने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी की जरूरत है। वर्ष 2007-08 से ही हर बजट में सरकारी बैंकों के लिए रिकैपिटलाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के इस मद में 70,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 1.06 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे।

को-ऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों ने किए 14,100 करोड़ के दावे

- आरबीआइ की रिपोर्ट से सामने आइ जानकारी
- पीएमसी बैंक के ग्राहक भी इसमें शामिल

शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। प्रतीकात्मक

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने कहा है कि डिफॉल्ट कर चुके को-ऑपरेटिव बैंकों के ग्राहकों ने 14,100 करोड़ रुपये के दावे किए हैं। बड़े घोटाले का सामने करने वाले पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहक भी इसमें शामिल हैं। यह दावे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआइसीजीसी) के पास आए हैं। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी दावों की पूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डीआइसीजीसी के पास मौजूद इन दावों में स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों और जिला को-ऑपरेटिव बैंकों का हिस्सा 3,414 करोड़ रुपये है। शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों की हिस्सेदारी 10,684 करोड़ रुपये है। इसमें पीएमसी के ग्राहकों के दावे भी शामिल हैं। आरबीआइ द्वारा पीएमसी बैंक से निकासी पर रोक लगाने के बाद डीआइसीजीसी काफी चर्चा में आया था।

लंबे समय से दबाव में चल रहे को-ऑपरेटिव बैंकों के संकट को पीएमसी बैंक घोटाले ने और बढ़ा दिया था। करीब 6,500 करोड़ रुपये के पीएमसी बैंक घोटाले में इसके कुल असेट का 73 परसेंट हिस्सा शामिल है। इस मामले में पीएमसी बैंक और दिवालिया प्रक्रिया का सामना कर रही एचडीआइएल आपसी गठजोड़ करके 2008 से फंड का गबन कर रहे थे। यह मामला इसी वर्ष सितंबर में बैंक के ही एक अधिकारी द्वारा किए गए विरोध के बाद सामने आया था।

आरबीआइ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर और निर्देशों के तहत लिए गए बैंकों का लिक्विडेशन किया जाएगा। इसके अलावा कमजोर बैंकों को पुनर्जीवन भी मिल सकता है। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में 30 से अधिक को-ऑपरेटिव बैंकों को आरबीआइ की देखरेख के दायरे में लाया गया था।

पीएमसी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देना बाकी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरबीआइ ने कहा है कि घोटाले से जूझ रहे पीएमसी बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एक आरटीआइ का जवाब देते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्राथमिक जांच के दौरान पीएमसी बैंक में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थी। इसके बाद बैंक के बोर्ड को भंग करके इसे आरबीआइ के अधीन ले लिया था। हालांकि आरबीआइ ने नियमों का हवाला देते हुए बैंक की शिकायतों की प्रतियां देने से इन्कार कर दिया है।

ब्रांड कैंपेन के लिए सोशल मीडिया पर हिंदी की धूम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कई ब्रांड्स ने सोशल मीडिया पर हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं का बखूबी उपयोग किया है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की बढ़ती लोकप्रियता कंपनियों के ब्रांड इमेज के अभियानों की नई संभावना के तौर पर उभर रही है। लोगों तक अपने उत्पादों और ब्रांड को पहुंचाने के लिए कंपनियां इन मंचों का खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं। इस वर्ष कोकाकोला समेत कई ब्रांड्स ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के ऐसे मंचों का बखूबी उपयोग किया।

सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करना कोकाकोला की मार्केटिंग रणनीति का हमेशा हिस्सा रहा है। दिवाली के दौरान कंपनी ने अपने अभियान सेलिब्रेटिंग दिवाली विद कोक के लिए शेयरचैट को आधार बनाया। इसके लिए हिंदी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरह स्टार भारत के लिए स्टार इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना हिंदी वीडियो डालकर चैनल को प्रमोट किया। इन वीडियो को इस मंच पर तीन करोड़ तक व्यू मिले। इसके अतिरिक्त कई फिल्म निर्माताओं ने भी अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस मंच का इस्तेमाल किया।

कंपनियों के ब्रांड प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बढ़ती रुचि पर शेयरचैट के चीफ बिजनेस ऑफिसर सुनील कामथ का कहना था कि किसी भी गैर-अंग्रेजी प्लेटफॉर्म पर हर महीने छह करोड़ सक्रिय यूजर मिलना अपने आप में विशिष्ट है।

यह कंपनियों को अपने ब्रांड की कहानी कहने के लिए बेहतर मौका देता है। 14 भाषाओं में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सुविधा देने वाले शेयरचैट पर हिंदी भाषा का सर्वाधिक इस्तेमाल हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर शेयर होने वाले हिंदी मैसेज की संख्या इस वर्ष 1.98 अरब तक पहुंच गई।

भारत के 2026 में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने की उम्मीद

- इस वर्ष भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है
- पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी में लग सकता है अतिरिक्त समय

नई दिल्ली, प्रेट्र : जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत 2026 तक चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। ब्रिटेन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) के मुताबिक इस वर्ष में फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2034 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है।

'वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, 2020' नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, जर्मनी और जापान अगले 15 वर्षों में तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते दिखेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी के निर्धारित लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लक्ष्य को पाने में दो वर्ष का अतिरिक्त समय लग सकता है। हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि इकोनॉमी पर छाए संकट के बादल इसे लक्ष्यों से भटका सकते हैं। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा था कि मौजूदा ग्रोथ रेट के हिसाब से 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को पाना संभव नहीं है।

रिपोर्ट कहती है कि भारत ने इस वर्ष ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन धीमी पड़ती जीडीपी ग्रोथ रेट चिंताजनक है। इससे उबरने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत होगी। सीईबीआर के सीनियर इकोनॉमिस्ट पाब्लो शाह ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तेज विकास किया है। लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये देश ग्लोबल इकोनॉमी पर अमेरिका और चीन जैसे देशों की धमक को कैसे प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षो के दौरान भारत दुनिया के तेज विकास करने वाले देशों में अव्वल रहा है।

अधूरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सुधार : गाइ सोरमन

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रांस के मशहूर अर्थशास्त्री गाइ सोरमन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सुधारों की अगुआई करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन ध्यान भटक जाने की वजह से आर्थिक सुधारवादी कोशिशें अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सोरमन के मुताबिक विपरीत आर्थिक हालात के चलते घरेलू और विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से बच रहे हैं। उनका कहना था कि सुधारों की गति सुस्त पड़ने की वजह से इकोनॉमी पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।

डिन के बिना अब कोई टैक्स नोटिस नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब करदाताओं के साथ सभी तरह के संवाद के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) जरूरी होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने ई-मेल सहित हर तरह के संवाद के लिए डिन को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले नवंबर में सर्च, समन, अरेस्ट मेमो, जांच नोटिस और सीबीआइसी द्वारा जारी किए पत्रों में डिन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। अब इसमें ई-मेल जैसे दूसरे संवाद माध्यमों को भी शामिल कर लिया गया है।

डायरेक्ट टैक्स के मामलों में डिन को अक्टूबर में ही लागू किया जा चुका है। सीबीआइसी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट किए गए डिन नंबर के साथ करदाता को भेजे गए संदेश एक डिजिटल डायरेक्टरी में सुरक्षित हो जाएंगे। इससे ऑडिट प्रक्रिया में आसानी होगी और पारदर्शिता में इजाफा होगा। इस तरह से भेजे गए संदेश में प्रेषक की पहचान भी स्पष्ट हो सकेगी।

डिन का प्रयोग अनिवार्य करने का फैसला प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की ओर एक और मजबूत कदम है। सीबीआइसी ने बताया कि जिन संदेशों के साथ डिन का उल्लेख नहीं किया जाएगा, वे अवैध माने जाएंगे।

- टैक्स प्रशासन में पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
- डिन के बिना भेजे जाने वाले संदेश माने जाएंगे अवैध

क्या है डिन

करदाताओं को टैक्स अधिकारियों की प्रताड़ना और अन्य दिक्कतों से निजात दिलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि टैक्स विभाग से करदाताओं को जो भी सूचना भेजी जाएगी, उस पर एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन दिया जाएगा। करदाताओं की पहचान इसी नंबर से होगी, उनके नाम से नहीं। नोटिस पर करदाता का नाम नहीं होने से अधिकारी किसी तरह का भेदभाव नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि टैक्स संबंधी मामलों का निस्तारण और निराकरण तेजी से हो।

बेपरवाही

टमाटर, प्याज और आलू यानी 'टॉप' की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, कम पैदावार, नीतिगत फैसलों में देरी, उचित प्रबंधन का अभाव

तालमेल के अभाव में आलू-प्याज की 'टॉप' योजना विफल

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा के दो साल से अधिक होने को हैं। लेकिन इसका असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। जिंस बाजार में टमाटर, प्याज और आलू जैसी संवेदनशील फसलें इस बार उपभोक्ताओं को बुरी तरह परेशान कर रही हैं। महंगाई की वजह से रसोई घर से तीनों सब्जियां दूर होने लगी हैं। ऑपरेशन ग्रीन की टॉप योजना को लेकर सरकार न किसान के खेत तक पहुंची और न उपभोक्ताओं के रसोईघर तक। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और उपभोक्ता मंत्रालयों के बीच उचित तालमेल का अभाव भी इस योजना की सफलता में आड़े आया है।

प्याज उत्पादन और बाजार पर कड़ी नजर रखने वाले विशेषज्ञ सीबी होल्कर का कहना है कि भारत प्याज का बड़ा निर्यातक है। इसके बावजूद उपज में निरंतरता और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते साल दर साल कभी किसानों, तो कभी उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसमें सुधार के लिए

सरकार ने तब मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया, जब भाव लगभग चढ़ चुका था। प्रतीकात्मक

सरकार ने 500 करोड़ रुपये की ऑपरेशन ग्रीन टॉप योजना शुरू की, लेकिन इसका असर किसानों व उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। सालाना औसतन 20 लाख टन प्याज का निर्यात होता है जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने में सहायक साबित हो सकता है। भारतीय प्याज का निर्यात मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर और इंडोनेशिया में होता रहा है। इससे भारत को सालाना तीन हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन निर्यात पर अचानक पाबंदी से वैश्विक बाजार में घरेलू निर्यातकों की साख पर बट्टा लग रहा है। टॉप योजना के जानकार व किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया, 'योजना के तहत क्लस्टर और किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाकर टॉप फसलों का उत्पादन बढ़ाना और उपज के लिए उचित बाजार मुहैया कराने का प्रावधान है। घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखने, फसलों की उत्पादन योजना तैयार करने, खेत से खलिहान तक आने में होने वाला नुकसान घटाने, भंडारण और उपभोक्ताओं तक ढुलाई का पुख्ता बंदोबस्त करने जैसे उपाय इस योजना में शामिल हैं। इसके अलावा बाजार की चाल पर कड़ी नजर रखना ओर वास्तविक आंकड़ों का बैंक तैयार करना इस योजना का सबसे प्रमुख हिस्सा है ताकि मांग और आपूर्ति के बारे में समय से फैसला लेने में सहूलियत हो सके।

चौधरी के मुताबिक सरकार की मार्केट इंटेलीजेंस प्रणाली पूरी तरह विफल रही है। प्याज उत्पादन कमी पर सरकार तब हरकत में आई इसका भाव करीब-करीब बेकाबू हो चुका था। मानसून की बेतरतीब बारिश और खराब हो रही फसल से बाजार और व्यापारी पूरी तरह वाकिफ थे। निर्यात पर रोक और घरेलू नियमों में सख्ती जैसे कदम तो उठाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही हाल आलू का भी हुआ है। टॉप योजना के तहत इन कच्ची फसलों के लिए कोल्ड स्टोर बनाना, बाजार तक इन्हें पहुंचाना और इनके प्रसंस्करण का इंतजाम संभव नहीं हो पा रहा है। योजना को लागू करने का दायित्व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सौंपा गया है। लेकिन उपभोक्ता मामले और कृषि मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण कड़ी से समन्वय की कमी ने मुश्किलें पैदा की हैं।

475 शादियां हुई हैं मेक्सिको सिटी की जेलों में इस साल। राजधानी की पेनिटेंचरी (बंदीगृह) सिस्टम ने यह जानकारी दी। बंदीगृह के अंडरसेक्रेटरी हेजाएल रुइज ओर्तेगा ने कहा, 'इस तरह से हम उन लोगों की मदद करते हैं, जो अपना परिवार बसाना चाहते हैं।'

मिस्र में सड़क हादसा, तीन भारतीय पर्यटकों की मौत

दुर्घटना ▶ हर्गडा शहर के रिसॉर्ट की ओर जाते समय ट्रक से भिड़ी बस

घायल 13 भारतीयों का विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इलाज

मिस्र में हुई सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल की ओर ले जाते सुरक्षाकर्मी। एएफपी

काइरो, प्रेट्र : मिस्र में एक सड़क हादसे में तीन भारतीय पर्यटकों सहित आठ लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो मलेशिया और तीन मिस्र के पर्यटक हैं। इस हादसे में 13 भारतीयों समेत 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।

भारतीय दूतावास के अनुसार, शनिवार को दो बसें पर्यटकों को लेकर हर्गडा शहर के बीच रिसॉर्ट की ओर जा रही थीं। इसी दौरान ऐन सोखना शहर के पास उनकी ट्रक से टक्कर हो गई। दूतावास ने ट्वीट में कहा, 'हमें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 28 दिसंबर को ऐन सोखना के पास हुए बस हादसे में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। घायलों का मिस्र के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मृतकों और घायलों के परिजनों से संपर्क किया गया है और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है। दूतावास के अधिकारी अस्पतालों में मौजूद हैं और अस्पताल के अधिकारियों के संपर्क में हैं।' दोनों बसों में कुल 16 भारतीय पर्यटक थे। इसके अलावा एक अन्य हादसे में टेक्सटाइल का काम करने वाले लोगों को ले जा रही एक बस कार से टकरा गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं शामिल हैं।

मिस्र में सड़क हादसे मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों और खराब यातायात नियमों के कारण होते हैं। मुल्क में 2017 में 11,098 सड़क हादसे हुए जबकि 2018 में इसकी संख्या 8,480 थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्र के कुछ इलाकों में सड़कों की हालत बहुत बुरी है और वहां यातायात नियमों में और कड़ाई की जरूरत है।

तय समय सीमा खत्म होने से पहले उत्तर कोरिया की अहम बैठक

प्योंगयांग, एएनआइ: उत्तर कोरिया ने अमेरिका के लिए तय की गई समय सीमा से पहले देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन की अध्यक्षता में रविवार को एक अहम बैठक आयोजित की। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की बैठक में भावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा किम की अध्यक्षता में बैठक में राष्ट्र निर्माण व देश की रक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई।

साल के अंत में किम की अगुआई में उत्तर कोरिया की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर उत्तर कोरिया ने दबाव बनाने के मकसद से इस वर्ष की समय सीमा तय की थी। उसने कहा था कि अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंधों में छूट नहीं मिलने पर वह अगले वर्ष से अपनी रणनीति बदल लेगा। प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका को धमकी देता रहा है। उत्तर कोरिया में मानवाधिकार हनन का मामला उठाए जाने पर गत हफ्ते अमेरिका को उसने कड़ा सबक सिखाने की चेतावनी भी दी थी।

बता दें कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच रुकी हुई परमाणु वार्ता पर अमेरिका को इस साल के अंत तक अपना रुख स्पष्ट करना है। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि उ. कोरिया अमेरिका को धमकी के तौर पर एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है।

न्यूयॉर्क में यहूदी धर्मस्थल में चाकू से हमला, पांच लोग घायल

▶ मॉनसे इलाके में हुई वारदात, घटना के समय हनुका उत्सव मना रहे थे लोग

▶ अटॉर्नी जनरल लेलिता जेम्स ने दिए मामले के जांच के आदेश

न्यूयॉर्क के यहूदी बहुल मॉनस इलाके में घटनास्थल पर मौजूद लोग। रायटर

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में शनिवार रात एक व्यक्ति ने यहूदियों के पूजास्थल में पांच लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों में एक रब्बी (धार्मिक गुरु) का बेटा भी है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है।

यहूदियों से जुड़ी संस्था ने बताया कि न्यूयॉर्क के मॉनसे इलाके में स्थित पूजास्थल में इस वारदात के समय लोग हनुका (यहूदी पर्व) उत्सव मना रहे थे। इस इलाके में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेलिता जेम्स ने एक ट्विटर पोस्ट में कहा कि इस घटना से वह बहुत व्यथित हैं। उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पुलिस इलाके की छानबीन में जुट गई है।

अमेरिका में हाल के वर्षों में यहूदियों पर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क के उपनगर कोषेर में यहूदियों पर गोलीबारी की घटना सामने आई थी। जर्सी सिटी में एक अन्य हमले में छह लोग मारे गए थे। मृतकों में हमला करने वाले दो संदिग्ध भी थे।

अमेरिका में बंदूक हिंसा से 38 हजार से ज्यादा की मौत

आइएएनएस के मुताबिक, अमेरिका में इस साल में गोलीबारी के जरिये हिंसा में 38 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी एक गैर-लाभकारी संगठन ने दी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार, देशभर में बंदूक से हुई हिंसा के मामले दर्ज करने वाले संगठन गन वायलेंस आर्काइव (जीवीए) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष 38730 लोगों की मौत हुई है। 14970 मामले साजिशन हत्या और दुर्घटनावश गोली चलने से शिकार होने के हैं, जबकि साल 2018 में यह मामले 14789 थे। जीवीए के मुताबिक, इस वर्ष में 23760 मामले आत्महत्या के हैं। बंदूक की हिंसा में 11 साल से कम उम्र के कुल 207 बच्चों ने अपनी जान गवां दी, जबकि 473 बच्चे घायल हुए हैं।

न्यूज गैलरी

अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में 17 की मौत

काबुल: अफगानिस्तान के तखार प्रांत में शनिवार को तालिबान के हमले में 17 स्थानीय लड़ाकों की मौत हो गई। प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। तालिबान ने भी हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान के दूरदराज इलाके में स्थानीय लड़ाके रक्षा या गृह मंत्रालय की मदद से काम करते हैं। (एपी)

यमन में मिसाइल हमले में नौ की जान गई

सना: यमन के धाले प्रांत की राजधानी में रविवार को सैन्य परेड पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में नौ लोगों की मौत हो गई। इनमें छह सैनिकों के अलावा तीन बच्चे शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) समर्थित रेजिस्टेंस फोर्स की परेड पर किए गए इस हमले में 20 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हमले के पीछे हाउती विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। (एपी)

नेपाल के शेरपाओं ने मांगी सामाजिक सुरक्षा

काठमांडू : नेपाल के शेरपाओं ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। शेरपा इस हिमालयी देश के पर्वतारोहण उद्योग के अहम अंग हैं। नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन (एनएनएमजीए) के अध्यक्ष आंग नोरबू शेरपा ने रविवार को यहां कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी शेरपा जान जोखिम में डालकर पर्वतारोहियों की मदद करते हैं। लेकिन इसके बदले में उन्हें काफी कम मेहनताना मिलता है। इसके अलावा उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। उन्होंने कहा, खतरे से खेलने वाले शेरपाओं का मेहनताना बढ़ाने की जरूरत है। (आइएएनएस)

डेटा लीक के लिए ब्रिटिश सरकार ने मांगी माफी

लंदन : ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार ने नए साल पर सम्मानित होने वाले लोगों के घर का पता से ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए गायक एल्टन जॉन और अन्य से माफी मांगी है। एक सरकारी वेबसाइट पर यह सूची कुछ समय के लिए प्रकाशित की गई थी, जिसे डाउनलोड करने की भी अनुमति थी। इंडिपेंडेंट समाचार वेबसाइट के मुताबिक इस फाइल में सम्मानित लोगों का पोस्टल कोड और मकान संख्या लिखी हुई थी। इस सूची में टीवी शेफ नादिया हुसैन और क्रिकेटर बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। (प्रेट्र)

यूक्रेन और अलगाववादियों के बीच कैदियों की अदला-बदली शुरू

▶ इस साल पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुआ था समझौता

बीते दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (दाएं) ने अपने यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से मुलाकात की थी। फाइल

कीव, रायटर : यूक्रेन और देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच कैदियों की अदला-बदली का काम शुरू हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को यह जानकारी दी। कैदियों की अदला-बदली का समझौता दिसंबर में पेरिस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच हुआ था।

कैदियों की यह अदला-बदली दोंतेस्क क्षेत्र के औद्योगिक शहर होर्लिवाका के पास स्थित एक चेक प्वाइंट पर हुई। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरआइए ने स्वघोषित दोंतेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि जहां यूक्रेन 87 अलगाववादियों को सौंपेगा वहीं दोंतेस्क इसके बदले में 55 सैनिक यूक्रेन को वापस करेगा। यूक्रेन की सेनाएं 2014 से पूर्वी यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र में अलगाववादियों से लड़ रही हैं। अब तक इस लड़ाई में 13 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौते के बावजूद छिटपुट लड़ाई जारी है। यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच कई बार कैदियों का आदान-प्रदान हुआ है। आखिरी बार दिसंबर, 2017 में यूक्रेन ने 300 अलगाववादियों को सौंपा था जबकि बदले में उसके 70 सैनिक छोड़े गए थे। 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर किए गए हमले के बाद यूक्रेन के साथ उसके संबंध काफी खराब हो गए थे।

चीन ने पांच लाख मुस्लिम बच्चों को जबरन हॉस्टल भेजा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▶ बोर्डिंग स्कूल भेजे जा रहे हैं शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम परिवारों के बच्चे

▶ बच्चों को इस्लाम के प्रभाव से दूर करने की कवायद में चीन की कम्युनिस्ट सरकार

शिनजियांग प्रांत स्थित होटन स्कूल से निकलते बच्चे। चीन अब स्कूलों का प्रयोग उइगर मुस्लिमों के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूलों के तौर पर भी करने लगा है। साभार : एनवाईटी

बीजिंग : वह पढ़ने में होशियार है और सहपाठी उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन वह हमेशा मायूस रहती है। मां को याद कर अक्सर अकेले में रोने लगती है। आश्चर्य की बात यह भी है कि उसका मायूस रहना किसी अध्यापक को चौंकाता नहीं है।

यह कहानी है चीन के शिनजियांग प्रांत के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही उइगर मुस्लिम समुदाय की बच्ची की। उसके पिता की मौत हो चुकी है और मां को अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए बने डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। बच्ची को किसी रिश्तेदार के पास भेजने के बजाय अधिकारियों ने उसे जबरन एक बोर्डिंग स्कूल पहुंचा दिया है। यह अकेला मामला नहीं है। क्षेत्र में ऐसे करीब पांच लाख बच्चों को मां-बाप और अन्य परिजनों से दूर किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया है। शिनजियांग प्रांत में ऐसे सैकड़ों सरकारी बोर्डिंग स्कूल खोले गए हैं।

उल्लेखनीय है कि चीन ने पिछले तीन साल से करीब 10 लाख उइगर, कजाख व अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जेलों एवं डिटेंशन सेंटर में डाल रखा है। लोगों में इस्लाम के प्रति आस्था कमजोर करने के उद्देश्य से चीन सरकार ऐसे कदम उठा रही है। दुनियाभर में आलोचना के बाद भी चीन सरकार बदस्तूर इस दिशा में बढ़ रही है और अब बच्चों को भी इस कदम का हिस्सा बना लिया गया है।

सैकड़ों स्कूल खोलने की तैयारी : बच्चों को मां-बाप से अलग कर बोर्डिंग स्कूल में डालने का उद्देश्य है कि उनमें सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी एवं विचारधारा के प्रति सम्मान पैदा हो। शिनजियांग प्रांत में 800 से ज्यादा टाउनशिप हैं और सरकार अगले साल के अंत तक हर टाउनशिप में ऐसे एक से दो बोर्डिंग स्कूल खोलने की तैयारी में है। सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज में यह बात सामने आई है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों का निर्माण गरीबी से लड़ने के लिए किया जा रहा है। जिनके माता-पिता कहीं दूर काम करते हैं या उनके पालन-पोषण में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी शिक्षा सुलभ हो सकेगी। यह सच भी है कि कई ग्रामीण परिवार अपने बच्चों को यहां भेजने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन इसी की आड़ में सरकार बच्चों को उनके परिवार और मजहब के प्रभाव से दूर रखने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। बच्चों को प्रायः इसलिए यहां आना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने उनके मां-बाप को या तो डिटेंशन सेंटर भेज दिया है, उन्हें कहीं दूर नौकरी का आदेश दे दिया है या अक्षम अभिभावक घोषित कर दिया है।

कड़ी सुरक्षा में हो रहा संचालन : इन स्कूलों को बाहरी लोगों की पहुंच से दूर और कड़ी सुरक्षा में संचालित किया जा रहा है। शिनजियांग प्रांत के लोग भी इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। निर्वासन में जी रहे कुछ उइगर परिवारों के साक्षात्कार, सरकारी दस्तावेजों, नोटिस, सरकारी मीडिया की रिपोर्टों और स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों के ब्लॉग से ही यहां की कुछ तस्वीरें सामने आ पाती हैं। सरकारी मीडिया और आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, शिनजियांग प्रांत में चरमपंथी हिंसा रोकने के लिए सरकार शिक्षा को अहम घटक मानती है। इन स्कूलों का संचालन इसी उद्देश्य से किया जा रहा है।

इराक में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

इराक के पवित्र शहर नजफ में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान रविवार को नारेबाजी करते विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। युवा 2003 के बाद के राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि तानाशाह सद्दाम हुसैन के बाद यहां सभी राजनीतिक दल अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। एएफपी

'अमेरिका में पाक के खिलाफ काम कर रही है भारतीय लॉबी'

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका में भारतीय लॉबी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को लेकर वॉशिंगटन की नीतियों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत घरेलू मुद्दों से ध्यान बंटाने के लिए बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी कार्रवाई को दोहरा सकता है।

यहां एसोसिएशन ऑफ फीजिशंस ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका (एपीपीएनए) की एक बैठक में इमरान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की धारणा को मजबूत बनाने में भारतीय लॉबी की मुख्य भूमिका है। इमरान ने कहा कि भारतीय लॉबी पाकिस्तान की लॉबी से बहुत मजबूत है।

इस दृष्टिकोण की वजह से पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की नीतियां भी प्रभावित होती हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एपीपीएनए से कहा कि वह अमेरिका में भारतीय लॉबी को मात देने के लिए काम करे। उन्होंने एपीपीएनए को विदेश में सक्रिय सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पाकिस्तानी समूह बताया।

ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने गर्लफ्रेंड संग इकोनॉमी क्लास में किया सफर

लंदन, आइएएनएस : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी गर्लफ्रेंड कैरी सायमंड्स कैरिबियाई देश सेंट लूसिया में नए साल की छुट्टियां मना रहे हैं। दोनों ने सेंट लूसिया जाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज की इकोनॉमी क्लास में यात्रा का विकल्प चुना। विमान की इस श्रेणी में लंदन से सेंट लूसिया की यात्रा में प्रति व्यक्ति 1,730 डॉलर (करीब सवा लाख रुपये) का खर्च आता है। जबकि जॉनसन ने अगर यही यात्रा ब्रिटिश वायुसेना के प्राइवेट जेट से की होती तो लगभग एक लाख पौंड (93 लाख रुपये) से ज्यादा का खर्च आता।

डेली मेल के अनुसार, बीते गुरुवार को एक सहयात्री द्वारा खींची गई तस्वीर में प्रधानमंत्री जॉनसन को खिड़की की तरफ वाली सीट पर किताब पढ़ते देखा जा सकता है। जबकि उनकी गर्लफ्रेंड सायमंड्स उनके बगल में बैठी हैं। दोनों विमान के पीछे की ओर इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। पीएम जॉनसन की यह यात्रा तामझाम से दूर थी और उनके साथ नाममात्र की सुरक्षा व्यवस्था थी। सेंट लूसिया में जॉनसन और सायमंड्स का स्वागत वहां के प्रधानमंत्री एलेन चेस्टरनेट ने किया।

अपनी गर्लफ्रेंड कैरी सायमंड्स के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। फाइल/रायटर

बचाए 90 लाख रुपये

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एयरफोर्स के प्राइवेट जेट में सफर कर सकते थे जिस पर करीब 93 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता था। लेकिन इकोनॉमी क्लास में सफर करके उन्होंने आम लोगों के टैक्स के 90 लाख रुपये बचा लिए हैं। फ्लाइट में खींची गई उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। यात्रा के दौरान पीएम के साथ सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। वे फ्लाइट के पिछले हिस्से में बैठे थे।

पानी और पहाड़ से टकराने वाला थाई नौसैनिक जिंदगी की जंग हारा

▶ पानी से भरी पहाड़ी गुफा से फुटबॉल खिलाड़ियों और कोच को बचाया था

▶ बचाव कार्य के दौरान खून में संक्रमण हो गया था, शुक्रवार को हुआ निधन

बैंकाक, एएफपी: थाइलैंड में पिछले साल पानी से भरी गुफा से युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम को बचाने वाले नौसैनिक की खून में संक्रमण के चलते निधन हो गया है। बचाव अभियान के दौरान ही नेवी सील का खून संक्रमित हो गया था और एक साल से उनका इलाज चल रहा था।

थाइलैंड की नौसेना ने शुक्रवार को अपने फेसबुक पर जारी बयान में कहा है कि पेटी अफसर बेरुत पकबारा पिछले साल गुफा से 12 युवा खिलाड़ियों और उनके कोच को बाहर निकालने के दौरान ही खून में संक्रमण के चलते बीमार पड़ गए थे। पिछले एक साल से डॉक्टरों की सघन निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई और शुक्रवार को उनका निधन हो गया। नौसेना ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

बेरुत के गृह प्रांत सैटन के एक अधिकारी ने बताया कि इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक शुक्रवार को ही उन्हें दफना दिया गया। बता दें कि थाइलैंड की नौसेना के एक अन्य नौसैनिक समन गुनान की भी बचाव कार्य के दौरान ही मौत हो गई थी। गुफा में फंसे खिलाड़ियों तक एयर पाइपलाइन बिछाने के दौरान उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। गुफा के सामने शहीद समन गुनान की प्रतिमा लगाई गई है। उन्हें नमन करने घटना केबाद से अब तक वहां 13 लाख लोग गए हैं।

बता दें कि पिछले साल जून में 'वाइल्ड बोअर्स' टीम के खिलाड़ी और कोच बारिश से बचने के लिए उत्तरी थाइलैंड में थाम लुआंग गुफा में छिपे थे। लेकिन तेज बारिश के बाद पहाड़ी गुफा में पानी भर गया था। खिलाड़ियों के गुफा में फंसे होने की जानकारी मिली तो थाइलैंड समेत पूरी दुनिया में हाहाकर मच गया।

खिलाड़ियों को सुरक्षित निकालने के लिए देश विदेश से बचाव दल के सदस्य और गोताखोर पहुंचे थे। 18 दिनों तक चले अभियान में सभी 12 खिलाड़ियों और उनके कोच को सही सलामत गुफा से निकाल लिया गया था। बाद में इस घटना पर फिल्म भी बनी थी।

यूएई में मशहूर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता नजर नंदी का निधन

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने सामुदायिक कार्यों के लिए मशहूर भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता नजर नंदी का रविवार को यहां निधन हो गया। केरल के रहने वाले नंदी को छाती में दर्द की शिकायत के बाद दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सकों ने करीब 55 वर्ष के नंदी की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया है।

नजर नंदी। फाइल

सामाजिक कार्यों में स्वेच्छा से भाग लेते हुए उन्होंने यूएई में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों की मदद की। इनमें गंभीर बीमारियों से घिरे मरीजों से लेकर वे भारतीय भी शामिल थे, जो वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण यूएई में कानूनी पचड़े में फंस गए थे।

बांग्लादेश में सर्दी का सितम, अब तक 50 लोगों की मौत, चेतावनी जारी

ढाका, रायटर : भारत की तरह बांग्लादेश में भी ठंड का कहर जारी है। अब तक इसकी चपेट में आकर 50 लोगों की मौत हो चुकी है। घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट को डाइवर्ट करने के साथ ही कुछ को निरस्त करना पड़ा है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है।

इस साल देश का सबसे कम तापमान रविवार तड़के बांग्लादेश के उत्तर में स्थित सीमावर्ती शहर तेतुलिया में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्वास्थ्य निदेशालय की वरिष्ठ अधिकारी आयशा अख्तर ने बताया कि एक नवंबर से 28 दिसंबर के बीच सांस संबंधी संक्रमण के कारण 17 लोगों की मौत हो गई। जबकि रोटावायरस और अन्य बीमारियों से होने वाले दस्ते के चलते 33 लोगों की जान गई। अस्पतालों में ठंड से संबंधित बीमारियों जैसे इंफ्लूएंजा, डिहाइड्रेशन और निमोनिया से पीड़ित लोगों की भीड़ लगी है। मौसम के इस कहर का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों सहित गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ा है।

बांग्लादेश में एक ओर जहां सर्दी का सितम जारी है, वहीं दूसरी ओर यहां ढाका के पास झुग्गियों में आग लगने से लोग सड़कों पर आ गए हैं। हाड़ कंपा देने वाली ठंड में कई लोग बेघर हो गए हैं। रायटर

अगर इंग्लैंड ने अपने खेलने के तरीके में सुधार नहीं किया, तो वह आगे भी टेस्ट हारेंगे।
— माइकल वॉन, पूर्व कप्तान इंग्लैंड

संन्यास के बाद फिल्मों में अभिनय करना चाहते हैं रोनाल्डो

दुबई, आइएएनएस : इटालियन क्लब जुवेंटस के लिए खेलने वाले पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि वह फुटबॉल से संन्यास लेने के बाद अभिनय की दुनिया में हाथ आजमाना चाहते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कांफ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे रोनाल्डो ने कहा, 'मैंने अपने लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं और उनमें से एक है, फिल्मों में काम करना।'

एक नजर में

उदयवीर ने जीते तीन स्वर्ण

भोपाल : चंडीगढ़ के विजयवीर सिद्धू ने रविवार को यहां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विजयवीर ने 580 अंक से शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि गुरप्रीत सिंह (578) और उदयवीर सिद्धू (574) उनसे पीछे रहे। विजयवीर (580) जूनियर वर्ग में भी उदयवीर (574) और हर्ष गुप्ता (572) से आगे रहे। उन्होंने उदयवीर और उनीश होलिंदर (1699) के साथ मिलकर जूनियर वर्ग का टीम स्वर्ण पदक भी हासिल किया। गुरप्रीत, नीरज कुमार और गुरमीत की सेना निशानेबाजी इकाई (एएमयू) ने सीनियर 25 मीटर स्टैंडर्डर्स पिस्टल स्पर्धा में 1707 अंक से पहला स्थान हासिल किया। विजयवीर, उदयवीर और होलिंदर कुमार ने 1693 अंक से दूसरा, जबकि हरियाणा के आदर्श सिंह, मंदीप सिंह और अनीश ने 1689 अंक से तीसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में बीएसएफ के शिब कुमार घोष ने स्वर्ण, जबकि विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जीतू राय ने टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। (प्रेट्र)

ऐश्वर्य ने स्वर्ण पदक जीता

न्यू पनवेल (महाराष्ट्र) : 18 वर्षीय ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने रविवार को यहां अखिल भारतीय आमंत्रण एयर राइफल टूर्नामेंट आरआर लक्ष्य कप की 10 मीटर सीनियर वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के निशानेबाज ने 2019 के शुरू में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ओलंपिक कोटा हासिल किया था। वह पहले 10 शॉट में राजस्थान के यशवर्धन से पिछड़ रहे थे। लेकिन 10.7, 10.8 और एक 10.9 अंक के स्कोर से तोमर 252.3 अंक बनाकर जीत हासिल करने में सफल रहे। 16 साल के यशवर्धन 250.7 अंक से दूसरे, जबकि हृदय हजारिका तीसरे स्थान पर रहे। इस टूर्नामेंट का आयोजन ओलंपियन सुमा शिरूर ने शुरू किया था। पिछले साल तोमर ने जूनियर वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। (प्रेट्र)

बॉक्सिंग डे टेस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज

ब्लंडेल के शतक के बावजूद न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट 247 रन से हारा कंगारू टीम ने ली 2-0 से अजेय बढ़त, लियोन ने झटके चार विकेट

मेलबर्न, एएफपी : नाथन लियोन और जेम्स पैटिनसन की धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने कामचलाऊ सलामी बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल के शतक के बावजूद न्यूजीलैंड को दूसरे टेस्ट के चौथे ही दिन रविवार को यहां 247 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलिया के 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दिन के अंतिम सत्र में 240 रन पर सिमट गई। लियोन ने 81 रन देकर चार, जबकि पैटिनसन ने 35 रन देकर तीन विकेट चटकाए। ब्लंडेल आउट होने वाले अंतिम बल्लेबाज रहे। उन्होंने 210 गेंद में 15 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली। यह ब्लंडेल के करियर का दूसरा और दो साल में पहला टेस्ट शतक है। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल होने के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की गेंद पर उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। वह सिडनी में तीन जनवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरे टेस्ट में चार दिन के भीतर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम ने पर्थ में पहला टेस्ट भी चार दिन के अंदर 296 रन से गंवाया था।

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई टीम 418 रन से अधिक के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन यह रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही है। वेस्टइंडीज ने 2003 में एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह लक्ष्य हासिल किया था। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पैटिनसन की गेंदबाजी के सामने भोजनकाल तक 38 रन तक तीन विकेट गंवाने के बाद संकट में थी, लेकिन ब्लंडेल ने एक छोर संभाले रखा।

दूसरे सत्र में लियोन ने एक विकेट चटकाया, लेकिन तीसरे सत्र में इस ऑफ स्पिनर ने तीन विकेट हासिल करके ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। आम तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका निभाने वाले ब्लंडेल को सलामी बल्लेबाज जीत रावल को बाहर किए जाने के बाद पारी का आगाज करने का मौका मिला। न्यूजीलैंड ने सतर्क शुरुआत की और एक समय उसका स्कोर बिना विकेट खोए 32 रन था, लेकिन चोटिल जोश हेजलवुड की जगह खेल रहे पैटिनसन ने टॉम लाथम (08), कप्तान केन विलियमसन (00) और अनुभवी रॉस टेलर (02) को तीन रन के भीतर पवेलियन भेज दिया। पहली पारी में अर्धशतक जड़ने वाले लाथम ने पैटिनसन की गेंद पर विकेटकीपर पेन को कैच थमाया, जबकि इस तेज गेंदबाज ने विलियमसन को एलबीडब्ल्यू किया। टेलर भी इसके बाद पैटिनसन की गेंद को विकेटों पर खेल गए। दूसरे सत्र में न्यूजीलैंड ने सिर्फ हेनरी निकोल्स का विकेट गंवाया, जिन्हें 33 रन बनाने के बाद लियोन की गेंद पर विकेटकीपर टिम पेन ने स्टंप किया। तीसरा टेस्ट खेल रहे ब्लंडेल ने इसके बाद बीजे वाटलिंग (22) के साथ पांचवें विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। लियोन ने वाटलिंग को स्लिप में डेविड वार्नर के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। कोलिन डि ग्रैंडहोम भी नौ रन बनाने के बाद लियोन की गेंद पर वार्नर को कैच दे बैठे, जबकि मिशेल सेंटनर (27) भी इस ऑफ स्पिनर की गेंद पर विकेटकीपर पेन को कैच दे बैठे। ब्लंडेल ने इससे पहले पैट कमिंस की गेंद पर एक रन के साथ 185 गेंद में शतक पूरा किया। टिम साउथी दो रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि मार्नस लाबुशाने ने ब्लंडेल को लियोन के हाथों कैच कराके ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया सुबह चार विकेट पर 137 रन से आगे खेलने उतरा। पेन ने पांच विकेट पर 168 रन के स्कोर पर दूसरी पारी घोषित की, जब ट्रेविस हेड (28) को नील वैगनर ने बोल्ड किया। वैगनर ने 50 रन देकर तीन विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 467 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 148 रन पर ढेर हो गई थी।

हेनरी निकोलस को आउट करने के बाद जश्न मनाते (बायें से) ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नाथन लियोन, जो बर्न्स और टिम पेन ● एएफपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : ट्रेविस हेड

ऑस्ट्रेलिया (पहली पारी) : 467 (155.1 ओवर), न्यूजीलैंड (पहली पारी) : 148 (54.5 ओवर)

ऑस्ट्रेलिया (दूसरी पारी) 168/5 (54.2 ओवर) (137/4 से आगे)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मैथ्यू वेड नाबाद	30	54	01	00
ट्रेविस हेड बो. वैगनर	28	64	02	00
अतिरिक्त : (बा-4, लेबा-4, नोबा-1, वा-2) 11				
कुल : 54.2 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन				
विकेट पतन : 5-168 (हेड, 54.2)				

गेंदबाजी :
ट्रेंट बोल्ट 9-0-30-0
टिम साउथी 15-3-44-0
कोलिन डि ग्रैंडहोम 5-0-14-0
नील वैगनर 17.2-1-50-3
मिशेल सेंटनर 8-0-22-1

न्यूजीलैंड (दूसरी पारी) 240 (71 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
टॉम लाथम का. पेन बो. पैटिनसन	08	21	01	00
टॉम ब्लंडेल का. लियोन बो. लाबुशाने	121	210	15	00
विलियमसन एलबीडब्ल्यू बो. पैटिनसन	00	09	00	00
रॉस टेलर बो. पैटिनसन	02	04	00	00
हेनरी निकोलस स्टं. पेन बो. लियोन	33	52	03	01
बीजे वाटलिंग का. वार्नर बो. लियोन	22	63	03	00
डि ग्रैंडहोम का. वार्नर बो. लियोन	09	12	01	00
मिशेल सेंटनर का. पेन बो. लियोन	27	46	05	00
टिम साउथी रन आउट (पैटिनसन/पेन)	02	03	00	00
नील वैगनर नाबाद	06	07	01	00
ट्रेंट बोल्ट एबसेंट हर्ट				
अतिरिक्त : (लेबा-7, नोबॉ-1, वा-2) 10				
कुल : 71 ओवर में 240 रनों पर सभी आउट				

विकेट पतन : 1-32 (लाथम, 8.4), 2-33 (विलियमसन, 11.2), 3-35 (टेलर, 11.6), 4-89 (हेनरी, 29.2), 5-161 (वाटलिंग, 49.2), 6-172 (ग्रैंडहोम, 51.4), 7-212 (सेंटनर, 65.5), 8-214 (साउथी, 67.2), 9-240 (ब्लंडेल, 70.6)

गेंदबाजी :
मिशेल स्टार्क 15-3-59-0
पैट कमिंस 18-4-47-0
जेम्स पैटिनसन 12-3-35-3
नाथन लियोन 23-4-81-4
मार्नस लाबुशाने 3-1-11-1

परिणाम : ऑस्ट्रेलिया 247 रन से जीता

बायें हाथ के गेंदबाजों के सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट

पारी	गेंदबाज	देश
44	रवींद्र जडेजा	भारत
46	नील वैगनर	न्यूजीलैंड
47	रंगना हेराथ	श्रीलंका
49	मिशेल जॉनसन	ऑस्ट्रेलिया
50	मिशेल स्टार्क	ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज सिडल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया

मेलबर्न, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज पीटर सिडल ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। सिडल ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने अपने इस फैसले का एलान किया। सिडल बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 13 सदस्यीय टीम में शामिल थे, लेकिन वह अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके। ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेल चुके सिडल ने कहा कि संन्यास के लिए सही समय का चयन करना हमेशा कठिन रहा है। एशेज मेरा लक्ष्य था और मैंने टीम के साथ बने रहने के लिए खूब मेहनत की। सिडल ने कहा है कि वह विक्टोरिया के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। सिडल ने कहा कि मैं विक्टोरिया के लिए खेलना जारी रखूंगा। साथ ही मैं एसेक्स के लिए काउंटी भी खेलना जारी रखूंगा। मुझे क्रिकेट से प्यार है। सिडल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और 221 विकेट हासिल किए। इस अनुभवी तेज गेंदबाज का अंतिम टेस्ट मैच इस साल के एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच था।

इस वर्ष सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट

विकेट	मैच	गेंदबाज	देश
99	35	कमिंस	ऑस्ट्रेलिया
77	30	शमी	भारत
77	23	स्टार्क	ऑस्ट्रेलिया
63	28	बोल्ट	न्यूजीलैंड
57	29	रबादा	द. अफ्रीका

इंग्लैंड को पहले टेस्ट में 107 रन से हराया, रबादा ने चटकाए चार अहम विकेट

विश्व चैंपियनशिप में खुला द. अफ्रीका का खाता

बॉक्सिंग डे टेस्ट

सेंचुरियन, प्रेट्र : दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को आखिर में अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया और रविवार को यहां विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का अपना पहला टेस्ट मैच 107 रन से जीता। इससे उसे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 30 अंक मिले।

इंग्लैंड को जीत के लिए 376 रन की जरूरत थी, लेकिन कुछ बल्लेबाजों की प्रतिबद्धता के बावजूद उसकी टीम चौथे दिन ही 268 रन पर आउट हो गई। इस रोमांचक मुकाबले का पलड़ा तब दक्षिण अफ्रीका की तरफ पलटा जब केशव महाराज ने बेन स्टोक्स को बोल्ड किया। इससे पहले स्टोक्स (14) और कप्तान जो रूट (48) ने दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। दक्षिण अफ्रीका ने तुरंत ही नई गेंद ली, जिसके बाद कैगिसो रबादा और एनरिक नोर्त्जे ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल कीं। रबादा ने नई गेंद से पहले ओवर में ही जॉनी बेयरस्टो (09) को गली में कैच कराया, जबकि नोर्त्जे ने रूट का महत्वपूर्ण विकेट लिया। दिन में यह दूसरा अवसर था, जबकि नोर्त्जे ने नए स्पैल में दूसरी गेंद पर विकेट लिया।

बॉक्सिंग-डे टेस्ट के दौरान इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट को आउट करने के बाद दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोर्त्जे (बायें) को बधाई देते साथी खिलाड़ी ● एएफपी

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

दक्षिण अफ्रीका (पहली पारी) : 284 (84.3 ओवर), **इंग्लैंड (पहली पारी) :** 181 (53.2 ओवर), **दक्षिण अफ्रीका, (दूसरी पारी) :** 272 (61.4 ओवर), **इंग्लैंड (दूसरी पारी) :** 268 (93ओवर), **रॉरी बर्न्स :** 84 रन (254 गेंद, 11 चौके), **कैगिसो रबादा :** 24-3-103-4

इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक 84 रन बनाने वाले रॉरी बर्न्स को आउट किया था। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज संघर्ष नहीं कर पाए। रबादा ने 103 रन देकर चार और नोर्त्जे ने 56 रन देकर तीन विकेट लिए। शनिवार को डॉक सिबली (29) को आउट करके इंग्लैंड की पहले विकेट की 92 रन की साझेदारी को तोड़ने वाले महाराज ने 37 रन देकर दो विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीका ने अनुशासित गेंदबाजी की, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहा। पहले सत्र में बर्न्स और जो डेनली (31) पवेलियन लौटे। बर्न्स सुबह एक घंटे क्रीज पर बिताने के बावजूद अपने एक दिन पहले के स्कोर में केवल सात रन जोड़ पाए। वर्नोन फिलेंडर और रबादा ने उन्हें और डेनली को लगातार दबाव में रखा, जिसका नतीजा यह रहा कि नोर्त्जे ने आक्रमण पर आने के बाद अपनी दूसरी गेंद पर विकेट ले लिया।

दबाव दूर करने के लिए बेताब बर्न्स ने गलत टाइमिंग से हुक किया और मिड ऑन पर रबादा को कैच थमाया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बदलाव के रूप में आए दूसरे गेंदबाज ड्वेन प्रिटोरियस ने डेनली को एलबीडब्ल्यू किया। इस जीत से दक्षिण अफ्रीकी टीम ने चार टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड पर 1-0 की शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है।

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका

देश	मैच	जीत	हार	ड्रॉ	अंक
भारत	7	7	0	0	360
ऑस्ट्रेलिया	9	6	2	1	256
पाकिस्तान	4	1	2	1	80
श्रीलंका	4	1	2	1	80
न्यूजीलैंड	4	1	3	0	60
इंग्लैंड	6	2	3	1	56
द. अफ्रीका	4	1	3	0	30
वेस्टइंडीज	2	0	2	0	00
बांग्लादेश	2	0	2	0	00

एजीएम में सभी प्रस्ताव हुए पारित

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की रविवार को हुई वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। डीडीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों को पारित किया। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा को सदस्यों ने नया लोकपाल नियुक्त किया। कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद सदस्य बड़ी संख्या में एजीएम के लिए पहुंचे, जिसमें पूर्व अध्यक्ष एसपी बंसल भी शामिल हैं। बैठक के पांच एजेंडे थे जिसमें वार्षिक खातों को पारित कराना, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, जिन निदेशकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनकी पुनः नियुक्ति, नए नियमों को स्वीकार करना और लोकपाल की नियुक्ति है। इसे पास कर दिया गया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि वे इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

अध्यक्ष पद के चुनाव के आसार नहीं : अधिकारी ने आगे कहा कि डीडीसीए के अध्यक्ष पद पर चुनाव कराने के आसार नहीं हैं। लोकपाल ने 13 जनवरी को इस पद के चुनाव कराने के आदेश दिए थे, लेकिन सत्ता में बैठा गुट फिलहाल अभी चुनाव नहीं करना चाहता है। उपाध्यक्ष राकेश बंसल ही कार्यकारी अध्यक्ष का काम तब तक संभालते रहेंगे। डीडीसीए निदेशक संजय भारद्वाज ने कहा, 'हमारे पास पांच बिंदु थे। हमने सभी को लागू कर दिया। हां, कुछ मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन कोई विशेष चर्चा योग्य नहीं है।'

समिति गठित : कोलकाता के होटल में अंडर-23 टीम के दो खिलाड़ियों द्वारा एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार करने के मामले की जांच के लिए डीडीसीए ने चार सदस्यीय अनुशासन समिति गठित की। यह घटना सीके नायडू टूर्नामेंट में दिल्ली अंडर-23 टीम के बंगाल के खिलाफ मैच से पहले घटी। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के पूर्व अधीक्षक शिव नंदन शर्मा समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति में आलोक मित्तल, अपूर्व जैन और सुधीर अग्रवाल शामिल हैं। मित्तल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इस मामले में शामिल दोनों खिलाड़ी कुलदीप सिंह यादव और लक्ष्य थरेजा को शुक्रवार को घटना के बाद ही कोलकाता से घर भेज दिया गया था।

एजीएम के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में हाथापाई करते डीडीसीए के सचिव तिहारा के समर्थक और कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश ● जागरण

'देखिए, किस तरह से कुछ लोग अपनी करतूतों से एक संस्थान का मजाक बना रहे हैं। मैं बीसीसीआइ, सौरव गांगुली और जय शाह से इसमें शामिल सभी को आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए निवेदन करता हूं।'

-गौतम गंभीर, पूर्व भारतीय क्रिकेटर

गौरव ने कांस्य पदक पर निशाना साधा

नई दिल्ली, आइएएनएस : पॉवरलिफ्टर से निशानेबाज बने गौरव शर्मा ने गाजियाबाद में आयोजित खेलो मास्टर्स गेम्स 2019-20 में 10 मीटर एआरएम निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक पर निशाना साधा है। गौरव विश्व चैंपियन पॉवरलिफ्टर रह चुके हैं। इंदिरापुरम के सेंट टेरेसा स्कूल में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में राज्य भर से निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। कांस्य पदक जीतने के बाद गौरव ने कहा कि वह अपने नए खेल पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। गौरव ने कहा, यह अभी शुरूआत है और अगली बार मैं स्वर्ण पदक जीतने की पूरी कोशिश करूं गा। मेरा सपना ओलम्पिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए मैं रोजाना अभ्यास कर रहा हूं।

भारत के अंतर्राष्ट्रीय कोच फलक शेर आलम से ट्रेनिंग ले रहे गौरव ने कहा कि उन्होंने पॉवरलिफ्टिंग में कई पदक जीते हैं और यही उपलब्धि वह निशानेबाजी में हासिल करना चाहते हैं। गौरव को हाल में दुबई में इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्डस में सम्मानित किया गया था।

ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए एंडी मरे

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे चोट की वजह से अगले महीने होने वाले साल के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से हट गए हैं। 32 वर्षीय मरे को पिछले महीने डेविस कप में ब्रिटेन की ओर से खेलते हुए चोट लगी थी। अगले साल 20 जनवरी से ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो रही है।

मरे ने कहा, 'शीर्ष स्तर पर खेलने के लिए खुद को तैयार करने में मैंने काफी मेहनत की थी और जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेल पाना बेहद निराशाजनक है। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद मुझे यहां दोबारा खेलने का यकीन नहीं था। यही कारण है कि मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को लेकर रोमांचित था। यही वजह है कि मैं और अधिक निराश हूं।' मरे ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से फिर से हाल ही में मुझे चोट लगी।

शतरंज कोनेरू ने चीन की टिंगजी को हराया, मौजूदा प्रारूप में रैपिड स्वर्ण जीतने वालीं दूसरी भारतीय बनीं

ग्रैंडमास्टर हंपी बनीं महिलाओं की विश्व रैपिड चैंपियन

मास्को, प्रेट्र : भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हंपी ने यहां महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में चीन की लेई टिंगजी को टाईब्रेक की सीरीज में हराकर खिताब अपने नाम किया। हंपी विश्व महिला रैपिड चैंपियन बनीं तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम कर किया।

32 वर्षीय हंपी ने शानदार वापसी की और 12वें और अंतिम दौर में एक अन्य चीनी खिलाड़ी टांग झोंगई को हराकर टाइब्रेकर में जगह बनाई। उन्होंने प्रत्येक दौर में नौ अंक जुटाए, जिससे वह टिंगजी के साथ बराबरी पर थीं। दोनों के बीच फिर आर्मेगेडोन गेम से विजेता का फैसला हुआ। हंपी ने पहला गेम गंवाने के बाद दूसरे गेम में वापसी की और फिर निर्णायक गेम में खिताब अपने नाम किया।

हंपी ने फिडे से बातचीत में कहा, 'जब मैंने तीसरे दिन अपना पहला गेम शुरू किया तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं शीर्ष पर पहूंगी। मैं शीर्ष-3 में रहने की उम्मीद कर रही थी। मैंने टाईब्रेक गेम खेलने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने पहला गेम गंवा दिया, लेकिन दूसरे गेम में वापसी की। यह गेम बहुत जोखिम भरा रहा, लेकिन मैंने इसमें जीत हासिल की। अंतिम गेम में मैं बेहतर स्थिति में थी और फिर मैंने आसानी से जीत हासिल की।'

कोनेरू हंपी ● फाइल फोटो, ट्विटर

हंपी टिंगजी और तुर्की की एकेटरिना अटालिक के बराबर पहुंच गईं। उन्होंने पहले पांच दौर में 4.5 अंक बनाकर अच्छी शुरुआत की और इसके बाद वह रूस की इरिना बुलमागा के खिलाफ मिली हार से थोड़ा पिछड़ गईं। यहां से हंपी को मजबूत वापसी की जरूरत थी और उन्होंने अंतिम दो दौर में जीत हासिल की। हालांकि, भारत की इस दिग्गज खिलाड़ी को थोड़े भाग्य की भी जरूरत थी जिसमें टिंगजी को अटालिक से हारना था और ऐसा हो गया। यह नाटकीय मुकाबला यहीं खत्म नहीं हुआ और हंपी पहला टाईब्रेक गेम गंवा बैठीं। इसके बाद वह दूसरे में जीत से आर्मेगेडन में पहुंच गईं। हंपी ने काले मोहरों से खेलते हुए तीसरा गेम ड्रॉ कराया, जो उन्हें स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी था। टिंगजी को रजत, जबकि अटालिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

दो साल तक रहीं शतरंज से दूर : भारत की सबसे युवा महिला ग्रैंडमास्टर रह चुकीं हंपी ने साल 2016 में शतरंज से विराम लेने का फैसला किया था। इसके बाद हंपी मां बन गईं और शतरंज से दो साल तक दूर रहीं। इसके बाद 2018 में उन्होंने वापसी की और जल्द ही उन्होंने अपनी वापसी को शानदार बनाया। उन्होंने स्कोलोवो महिला जीपी जीती और अब विश्व रैपिड चैंपियन बनी हैं।

आनंद ने दी बधाई : भारत के दिग्गज शतरंज स्टार विश्वनाथन आनंद ने 2017 में यह खिताब ओपन वर्ग में जीता था और हंपी मौजूदा प्रारूप में रैपिड स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय हैं।

हार के बाद वेस्टहम ने मैनेजर को हटाया

लंदन, एएफपी : लीसेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में शनिवार को वेस्टहम को 2-1 से हराकर जीत की राह फिर से पकड़ ली। उधर, इस हार की वजह से वेस्टहम के मैनेजर मैनुअल पेलेग्रिनी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और क्लब ने 2018 से चले आ रहे उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया।

बॉक्सिंग डे पर लिवरपूल के हाथों करारी शिकस्त झेलने के बाद लीसेस्टर की टीम वेस्टहम के खिलाफ मुकाबले में नौ बदलाव के साथ उतरी। जैमी वार्डी अपनी बच्ची के जन्म के कारण नहीं खेलने उतरे, लेकिन केलेची इहेनाचो (40वें मिनट) और डेमाराइ ग्रे (56वें मिनट) ने दोनों हाफ में एक-एक गोल करके लीसेस्टर को शानदार जीत दिलाई। अंक तालिका में लीसेस्टर 42 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, वेस्टहम के लिए पाब्लो फर्नांल्स (45वें मिनट) ने स्कोर किए। इस हार के तुरंत बाद ही वेस्टहम ने पेलेग्रिनी को मैनेजर के पद से हटा दिया। 66 वर्षीय पेलेग्रिनी वेस्टहम मैनचेस्टर सिटी और रीयल मैड्रिड जैसे नामी क्लबों के मैनेजर रह चुके हैं।

फुटबॉल डायरी

- ईपीएल में लीसेस्टर से 1-2 से हारी वेस्टहम की टीम
- हार के तुरंत बाद मैनेजर मैनुअल को किया गया बर्खास्त

शीर्ष चार के करीब पहुंचा युनाइटेड : ईपीएल में शनिवार को देर रात खेले गए मुकाबले में मैनचेस्टर युनाइटेड ने बर्नले को 2-0 से हरा दिया। युनाइटेड के लिए एंथनी मार्शल और मार्कस रशफोर्ड ने दोनों हाफ में स्कोर किए और अपनी टीम को अंक तालिका में शीर्ष चार के करीब पहुंच दिया।

उधर, टॉटनहम को नॉर्विक सिटी के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मारियो व्रानसिक (18वें मिनट) ने गोल करके नॉर्विक को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे हाफ में क्रिस्टियन एरिक्सन (55वें मिनट) ने फ्री किक के जरिये शानदार गोल करके टॉटनहम को बराबरी दिलाई। हालांकि, टॉटनहम के सर्जी ऑरियर (61वें मिनट) आत्मघाती गोल कर बैठे, जिससे नॉर्विक ने एकबार फिर बढ़त बना ली। हालांकि, निर्धारित समय से आठ मिनट पहले हैरी केन ने पेनाल्टी किक के जरिये गोल दागा।

मेरे लिए आराम का कोई दिन नहीं होता : अजिंक्य रहाणे

मुंबई, आइएएनएस : विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम अपने कप्तान की तरह खुद को फिट रखना चाहती है। इसी से प्रेरित होकर हर खिलाड़ी बिना किसी ब्रेक के अपने स्तर पर जमकर मेहनत कर रहा है। टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अभी-अभी मुंबई के लिए रणजी मैच खेला है और अब वह जिम में पसीना बहा रहे हैं। रहाणे ने रविवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कई तरह की एक्सरसाइज करते दिखाई दे रहे हैं।

केन विलियमसन को मैदान पर वही भूख दिखानी चाहिए, जो उन्होंने युवा के तौर पर दिखाई थी।
– ब्रेंडन मैक्कुलम, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान

क्रिकेट डायरी ▶ कहा, टीम में चुना जाना मेरे ऊपर नहीं, प्रदर्शन पर रहता है पूरा ध्यान

नहीं बता सकता कब तक वापसी करूंगा : भुवी

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में दोबारा चोटिल हो गए थे भारतीय तेज गेंदबाज

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को अभी नहीं पता कि वह कब प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करेंगे, क्योंकि अब तक यह तय नहीं किया जा सकता है कि उनकी स्पोर्ट्स हर्निया के उपचार के लिए सर्जरी की जरूरत है या नहीं। यह अनुभवी तेज गेंदबाज कथित तौर पर अपने रिहैबिलिटेशन में खामी के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। वह हालांकि हैरान हैं कि उनके हर्निया का पता पहले क्यों नहीं चला।

भुवनेश्वर ने कहा, 'टी-20 विश्व कप में अब भी नौ महीने का समय है। मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। सबसे पहले मुझे फिट होना है और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक फिट हो पाऊंगा।' एनसीए की भूमिका पर 29 साल के इस तेज गेंदबाज ने कहा, 'यह बीसीसीआइ पर निर्भर करता है कि वे इसे कैसे लेते हैं। उन्हें एनसीए से बात करनी चाहिए।

एनसीए ने निश्चित तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ और वे इसका पता क्यों नहीं लगा पाए। फिर भी इस बारे में टिप्पणी करने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं क्योंकि शायद मैं कुछ और कहूं और बीसीसीआइ किसी और निष्कर्ष पर पहुंचे।'

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत के लिए 21 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी-20 खेल चुके मेरठ के भुवनेश्वर से पूछा गया कि क्या खिलाड़ी एनसीए में जाने से डरते हैं तो उन्होंने कहा, 'यह किसी भी खिलाड़ी की व्यक्तिगत इच्छा है कि वह एनसीए जाना चाहता है या नहीं।' भुवनेश्वर ने कहा, 'सर्जरी को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स हर्निया के मामले में आम तौर पर सर्जरी ही की जाती है। लेकिन, इसके बावजूद डॉक्टर से मिलना होगा। मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन हम जितना जल्दी संभव को इसका उपचार कराने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक मैं डॉक्टर से सलाह नहीं ले लेता तब तक नहीं बता सकता कि कब वापसी करूंगा, क्योंकि यह उपचार पर निर्भर करेगा।'

वेस्टइंडीज दौरे के बाद मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हुए भुवनेश्वर ने इसी टीम के खिलाफ इस महीने टी-20 सीरीज में वापसी की थी, लेकिन एक बार फिर चोटिल हो गए। भुवनेश्वर से पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिए क्या उनके और एक अन्य चोटिल तेज गेंदबाज दीपक चाहर के बीच सीधी टक्कर है तो उन्होंने कहा, 'जब मैं फिट हो जाऊंगा तो यह प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं इस बारे में नहीं सोच रहा कि कौन मौजूद है। चयन मेरे हाथ में नहीं है और ना ही यह मेरा काम है। मेरा काम प्रदर्शन करना है और मैं ऐसा करूंगा।'

रंगास्वामी, गायकवाड़ के खिलाफ हितों के टकराव की शिकायत अप्रासंगिक करार

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीसीसीआइ के आचरण अधिकारी डीके जैन ने पूर्व क्रिकेटरों और क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्य शांता रंगास्वामी और अंशुमन गायकवाड़ के खिलाफ दायर हितों के टकराव की शिकायत को अप्रासंगिक करार दिया, जबकि कपिल देव के मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जैन ने रंगास्वामी, गायकवाड़ और कपिल को 27 और 28 दिसंबर को उनके समक्ष पेश होने का नोटिस दिया था। तीनों हालांकि पहले ही सीएसी से इस्तीफा दे चुके है। जैन ने यह नोटिस मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता की शिकायत पर जारी किया गया था। गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि सीएसी सदस्य एक साथ कई भूमिकाएं निभा रहे हैं, जबकि बीसीसीआइ संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक बार में एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। जैन ने रविवार को कहा, 'चूंकि वे (गायकवाड़ और रंगास्वामी) अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं इसलिए शिकायत को निरस्त कर दिया गया है। कपिल के मामले में शिकायतकर्ता को आवेदन देने के लिए और अधिक समय चाहिए, मैंने उन्हें समय दे दिया है।' रंगास्वामी और गायकवाड़ अब भारतीय क्रिकेटर संघ के प्रतिनिधि के रूप में शीर्ष परिषद का हिस्सा हैं। रंगास्वामी ने भारतीय क्रिकेटर संघ (आइसीए) में निदेशक का पद छोड़ दिया है। कपिल और रंगास्वामी जैन के समक्ष पेश नहीं हुए, जबकि गयकवाड़ यहां पहुंचे। हितों के टकराव के मामले का सामना कर रहे बीसीसीआइ अधिकारी मयंक पारिख पर भी कोई फैसला नहीं हुआ।

इंग्लिश काउंटी विवाद में शामिल सट्टेबाज को जानते थे पाक खिलाड़ी : कनेरिया

कराची, प्रेट्र : पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने रविवार को दावा किया कि 2012 में इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में शामिल सट्टेबाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के आमंत्रण पर लगातार पाकिस्तान का दौरा करता था। उन्होंने साथ ही कहा कि उस सट्टेबाज को राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी जानते थे। कनेरिया 2012 में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग में दोषी पाए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सट्टेबाज पीसीबी के अधिकारियों को जानता था।

कनेरिया ने अपने यू ट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे हमेशा गलत तरह से पेश किया गया। जब लोगों के पास सच्चाई बयां करने का मौका होता है तो वे ऐसा नहीं करते। वे तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करते हैं। मैं आज आपको वास्तविकता बता रहा हूं। मेरे मामले में जिन लोगों ने मेरा उससे परिचय कराया, वे कौन थे। मेरा मामला सभी के सामने खुला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पूरी टीम उस व्यक्ति (सट्टेबाज) को जानती थी और अधिकारी भी। वह व्यक्ति आधिकारिक दौरों पर पाकिस्तान आता रहता था। उसे पीसीबी आमंत्रित करता था। मैं कभी उसे निजी तौर पर नहीं जानता था। मेरा उससे यह कहकर परिचय कराया गया था क्योंकि हम दोनों एक ही धर्म से जुड़े थे। इस विवाद में कनेरिया के एसेक्स के साथी मर्विन वेस्टफील्ड को दो महीने की जेल की सजा हुई थी। उन्होंने सट्टेबाज अनु भटट् से एक ओवर में 12 रन देने के लिए पैसे लेने की बात स्वीकार की थी। कनेरिया को इस मामले में बिचौलिया करार दिया गया था जिन्होंने मर्विन का परिचय भटट् से कराया था। कनेरिया ने कहा कि कोई भी इस बारे में क्यों बात नहीं करता। वे सच्चाई क्यों बयां नहीं करते।

दानिश कनेरिया। फाइल फोटो, एएफपी

विवाद

- यू ट्यूब चैनल पर पूर्व पाक क्रिकेट ने किया नया रहस्योद्घाटन
- कहा, मुझे हमेशा से ही गलत तरीके से पेश किया गया

मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया : अख्तर

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साफ किया है कि दानिश कनेरिया के संबंध में दिए गए उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अख्तर के मुताबिक उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि हिंदू होने के नाते पाकिस्तानी टीम में कनेरिया के साथ गलत व्यवहार होता था। अख्तर ने कहा कि पाकिस्तानी टीम में कभी भी इस तरह की संस्कृति नहीं रही है और खासतौर पर धर्म के आधार पर कभी भी किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अख्तर ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी टीम में कुछ खिलाड़ी थे जो उन्हें टीम में नहीं चाहते थे क्योंकि वह हिंदू धर्म के थे। इसके बाद स्पॉट फिक्सिंग के कारण प्रतिबंध झेल रहे कनेरिया ने कहा था कि कुछ खिलाड़ी थे, जिन्होंने उन्हें निशाने पर लिया था लेकिन उन पर कभी भी धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं था। शनिवार को पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भी कहा कि कनेरिया उनकी कप्तानी में खेले और इस दौरान उनके साथ किसी भी तरह के गलत व्यवहार की उन्हें कोई जानकारी नहीं। अख्तर ने इन तमाम बातों को लेकर जारी विवाद पर सफाई पेश करने के लिए अपने यू ट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में अख्तर ने कहा कि मैंने इस पूरे मामले को देखा है। मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अख्तर ने कहा कि हमें हर खिलाड़ी का सम्मान करना था।

हॉकी इंडिया का कोचिंग शिक्षा कार्यक्रम फरवरी-मार्च में

नई दिल्ली, प्रेट्र : हॉकी इंडिया के कोचिंग शिक्षा कार्यक्रम का दूसरा सत्र अगले साल फरवरी-मार्च में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) अकादमी का अहम हिस्सा है और इसके तहत फरवरी 2020 में चार क्षेत्रों दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में लेवल 'बेसिक' और लेवल 'एक' स्तर के कोचिंग कोर्स आयोजित होंगे, जबकि हॉकी इंडिया का लेवल 'दो' का कोचिंग कोर्स मार्च में होगा। हॉकी इंडिया के इस कोचिंग शिक्षा कार्यक्रम में वेब सामग्री के अलावा आमने-सामने बैठकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कोचों का आकलन किया जाएगा, जिससे कोच को आगे के स्तर पर बढ़ने मे मदद मिलेगी। कोचिंग शिक्षा कार्यक्रम को सात स्तर में बांटा गया है- हॉकी इंडिया लेवल बेसिक, हॉकी इंडिया लेवल एक, हॉकी इंडिया लेवल दो, एफआइएच लेवल एक, एफआइएच लेवल दो, लेवल तीन और हाई परफॉर्मेंस। लेवल को पूरा करने के बाद उम्मीदवार एफआइएच का अकादमी लेवल एक कोर्स करने का पात्र बन जाता है।

पिता का सपना पूरा कर रहा हूं : जेरेमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेरेमी लालरिनुंगा ने रविवार को कहा कि वह सीनियर स्तर के विभिन्न भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करके अपने पिता के सपने को पूरा कर रहे हैं।

17 वर्षीय इस खिलाड़ी के पिता जूनियर मुक्केबाज चैंपियन थे, लेकिन कभी देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा, 'मेरे पिता मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। मैंने जब से भरोत्तोलन में हाथ आजमाने का फैसला किया, उन्होंने तभी से मेरा पूरा साथ दिया। वह मुक्केबाज थे, उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर अपने अनुभव मुझ से साझा किए हैं। वह जूनियर चैंपियन थे, लेकिन दुर्भाग्य से देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उनके सपने को साकार कर रहा हूं।'

आइजोल का यह खिलाड़ी 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस साल 67 किग्रा में दो रजत पदक जीते है। इस खिलाडी ने कहा, 'मैं 2020 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की तैयारी कर रहा हूं। ओलंपिक क्वालीफिकेशन के लिए आखिरी टूर्नामेंट इस साल अप्रैल में होगा। मैं उस प्रतियोगिता कि तैयारी कर रहा हूं।

मैंने थाइलैंड में ईजीएटी कप अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप और छठे कतर अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।' उन्होंने कहा, 'युवा खिलाड़ियों को खेलों इंडिया यूथ गेम्स में अच्छा अनुभव मिलता है। यह प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय स्तर की है।'

नजरिया

- युवा भारोत्तोलक ने कहा, मेरी निगाह टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने पर
- कहा, युवा खिलाड़ियों को खेलों इंडिया यूथ गेम्स में अच्छा अनुभव

विविध

गोविंदा को पुस्तक भेंट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सिने स्टार गोविंदा(ब्लैक कोट में) को प्रयागराज कुंभ पर पुस्तिका भेंट की। दोनों के बीच प्रदेश के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जागरण

एक साथ गूंजा तीन पीढ़ियों का संगीत

श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन

संवाद सहयोगी, जालंधर

श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में वायलिन पर पहली बार तीन पीढ़ियों की एक साथ परफार्मेंस पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नानी, मां और बेटी ने एक साथ वायलिन पर संगीत की सरिता से कड़ाके की ठंड में श्रोताओं में जोश व जुनून की लहर दौड़ा दी। 81 साल की उम्र और वायलिन की तारों से खेलतीं डॉ. एन राजम को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उम्र उन पर भारी है।

प्रस्तुति देने के बाद दैनिक जागरण से खास बातचीत में डॉ. एन राजम ने कहा कि हरिवल्लभ सम्मेलन में मुझे प्रस्तुति देकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आज भी संगीत सीख रही हूं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी समेत तमाम देशों के संगीत के छात्र-छात्राओं को संगीन सिखा रही हूं। इन्हीं में मेरी बेटी व नातिन भी शामिल हैं। चेन्नई में जन्मी डॉ. एन राजम बताती हैं, 'जब वह वायलिन बजाती हैं तो भूल जाती हैं कि 81 साल की हो चुकी हैं। पद्म श्री और पदम भूषण जैसे कई सर्वोच्च सम्मान से नवाजी जा चुकी राजम कहती हैं कि संगीत ही ऐसी विधा है, जिसमें कोई भी डूब कर अपनी उम्र, अपने गम और अपने आप को भूल सकता है। तमाम बीमारियों का इलाज संगीत है। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगली पीढ़ी संगीत को आगे लेकर जा रही है।

जालंधर में श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के दौरान डॉ. एम राजम (बाएं), उनकी बेटी संगीता शंकर (मध्य) तथा नातिन नंदनी शंकर (दाएं) वायलिन पर एक साथ प्रस्तुति देती हुईं। जागरण

मां व बेटी के साथ प्रस्तुति देने का आनंद ही अद्भुत : संगीता

डॉ. एन राजम की बेटी संगीता शंकर ने कहा कि मैं श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में पहले भी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हूं, लेकिन इस बार मां और अपनी बेटी के साथ प्रस्तुति देने में अद्भुत आनंद मिला है। हम तीनों जब एक साथ पेशकश करते हैं, तो जो खुशी मिलती है वह बयान नहीं की जा सकती। मैंने अपनी मां डॉ. एन राजम जी से ही वायलिन बजाना सीखा है। उनसे ही इस संगीत की शिक्षा भी ली है।

संगीत की शिक्षा दो गुरुओं से ली : नंदिनी

डॉ. एन राजम की नातिन नंदिनी शंकर ने कहा कि मैं बचपन से ही संगीत सीख रही हूं। मेरे दो गुरु (मां और नानी) हमेशा मेरा साथ देते रहे हैं। कभी-कभी रियाज करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी रियाज करती हूं।

अब उत्तराखंड में भी एक होगा सहकारी बैंक

केदार दत, देहरादून

जिला सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंक में विलय की तैयारी

झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी एक ही सहकारी बैंक रहेगा। जिला सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंक में विलय की तैयारी है। इसके लिए सरकार प्रदेश में सहकारिता में टू-टायर सिस्टम लागू करने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। इस व्यवस्था के अमल में आने से प्रदेश में जहां सहकारी बैंक सशक्त होगा, वहीं प्रतिस्पर्धा के मौजूदा दौर में वह सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो सकेगा।

बदली परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्र सरकार का जोर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सशक्त बनाने के मद्देनजर उनका एकीकरण हो रहा है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार भी कदम बढ़ाने जा रही है। इसके तहत राज्य का एक ही सहकारी बैंक बनाने की योजना है। वर्तमान में जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक अपनी 274 शाखाओं के माध्यम से कार्यरत हैं, जबकि प्रदेश स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक 15 शाखाओं के साथ। प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंकों के प्रशासनिक व्यय में बड़ी रकम खर्च होने से चिंता बढ़ी है। इससे पार पाने के साथ ही सहकारी बैंक को अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा को तैयार करने के मद्देनजर एक ही राज्य सहकारी बैंक बनाने को लेकर गंभीरता से मंथन चल रहा है। इसके लिए सहकारिता का टू-टायर सिस्टम लागू किया जाएगा। वर्तमान में सहकारिता में थ्री-टायर (सहकारी समितियां, जिला सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंक) सिस्टम लागू है। टू-टायर में सहकारी समितियां और राज्य का एक सहकारी बैंक होता है। नई व्यवस्था में सभी जिला सहकारी बैंकों का राज्य सहकारी बैंक में विलय किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे जहां मितव्ययता आएगी, वहीं प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर हो सकेगा। हाल में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में भी इसे लेकर मंथन हुआ।

सहकारिता में टू-टायर सिस्टम लागू कर राज्य का एक ही सहकारी बैंक हो, इस पर मंथन चल रहा है। सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
-डॉ. धन सिंह रावत, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

छत्तीसगढ़ में हर साल होगा तीन दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव

नईदुनिया, रायपुर

- राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन पर सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ी में दिया भाषण

छत्तीसगढ़ में तीन दिन तक चले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की। कहा कि अब राज्योत्सव के साथ तीन दिन तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव भी होगा। मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा कि हर साल इस तरह का आयोजन होना चाहिए या नहीं। जब भीड़ ने हां कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल एक नवंबर को राज्योत्सव पहले दो दिन मनाया जाएगा। बाकी तीन दिन देश-विदेश के आदिवासियों के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में पूछा-कइसे लागिस, जवाब आया, मजा अइस। बघेल ने समापन समारोह का पूरा भाषण भी छत्तीसगढ़ी में ही दिया।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जब इस आयोजन के बारे में सोचा तो मन में शंकाएं थीं। डर था कि कैसे होगा। सबका साथ मिला और हमने आयोजन किया। उसका परिणाम यह है कि 25 राज्य, तीन केंद्र शासित प्रदेश और छह देश के लोग आए। ठंड होने के बावजूद सुबह नौ बजे से भीड़ रहती है। आयोजन का पहला साल था। कहीं कुछ कमी रही होगी तो उसे आने वाले साल में पूरा करेंगे। इस आयोजन से हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला है। हमें दुनिया भर की आदिम संस्कृति को जानने का अवसर मिला है। निश्चित तौर पर आदिवासियों की कला और संस्कृति बेहद समृद्ध है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति कितनी प्राचीन है, यह आज इस मंच से दुनिया ने भी देख लिया है।

एक साल में बदल गई छत्तीसगढ़ की पहचान : बघेल ने कहा कि पिछले 15 साल से हमने देखा कि जब नक्सली घटना होने थी, तब छत्तीसगढ़ का नाम आता था। लेकिन एक साल में छत्तीसगढ़ को कर्ज माफ करने, 2500 पये में धान खरीदने के नाम पर जाना जाता है। पुरखों ने समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी, जिसे एक साल में पूरा करने का काम किया गया। आज न केवल देश, बल्कि शरहद पार भी लोग छत्तीसगढ़ का नाम जान रहें है। यही एक साल का बदलाव है।

कारपेंटर का चेहरा चीनी मांझे से कटा, 12 टांके लगे

जागरण संवाददाता, लुधियाना

पंजाब के लुधियाना में रविवार शाम जगराओं पुल से गुजरते हुए चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार बुजुर्ग कुलदीप सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुलदीप शिमलापुरी में रहते हैं और कारपेंटर का काम करते हैं। वह बेटी के लिए बाजार से सूट खरीदने जा रहे थे। बाइक पर जाते समय चीनी मांझे ने उनके चेहरे को बुरी तरह चीर दिया। लहूलुहान हुए कुलदीप को राहगीरों ने इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनके चेहरे पर करीब 12 टांके लगाए है।

घटना की जानकारी मिलते ही एक्शन अगेंस्ट करप्शन के प्रमुख चंद्रकांत चड्ढा और महासचिव गौतम सूद सिविल अस्पताल पहुंचे। चड्ढा ने कहा कि उनकी संस्था चीनी मांझे पर प्रतिबंध लगाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। कई बार प्रशासन को मांगपत्र दिए गए पर न तो सुनवाई हुई और न ही ठोस कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि वह मंगलवार को चीनी मांझे बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग के लिए डीसी प्रदीप अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को ज्ञापन सौंपेंगे।

पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि चीनी मांझा बेचने वालों के खिलाफ पिछले काफी दिनों से सख्ती बरती जा रही है। शनिवार को ही पुलिस ने अलग-अलग जगह छापेमारी की। चार दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित चीनी मांझे को बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस साल 65 लोग हुए घायल : वर्ष 2019 में अब तक 65 लोग चीनी मांझे की चपेट में आने से जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा वर्ष 2017 में दो लोगों की जान चली गई थी।

मौसम विशेष

पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा, परंतु तापमानों में वृद्धि होगी। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह में शीतलहर रहेगी। रात में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कश्मीर के उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/22/आंबा	अहमदाबाद	27/13/आंबा
कोलकाता	24/12/आंबा	बड़ौदा	28/13/सा
चेन्नई	32/23/व	नागपुर	25/06/आंबा
हैदराबाद	28/15/आंबा	इन्दौर	25/11/आंबा
बंगलूरू	28/16/आंबा	रांची	22/13/व
त्रिवेन्द्रम	33/24/आंबा	पटना	23/13/आंबा
गुवाहाटी	20/14/व	जमशेदपुर	23/15/व
गंगटोक	03/-3/ आंबा	पुणे	28/19/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 30 दिसंबर 2019
आजकल
16
www.jagran.com

भारत ने आज ही चीन को दी थी मान्यता

भारत ने आज ही के दिन 1949 में चीन को मान्यता दी थी। ऐसा करने वाला भारत, बर्मा (अब म्यांमार) के बाद दूसरा गैर साम्यवादी देश था। इसके बाद एक अप्रैल 1950 को भारत ने चीन में अपना राजदूत भी नियुक्त किया। हालांकि, चीन का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है।

ईराक के शासक रहे सद्दाम हुसैन को दी गई फांसी

आज ही के दिन 2006 में ईराक के दो दशक तक शासक रहे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। ईराक की एक अदालत ने उन्हें 1982 के दुजैल नरसंहार का दोषी पाया था। सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमले के बाद दुजैल में 148 लोगों को मार गिराया गया था।

भारत की माटी में जन्मे साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग

आज ही के दिन प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि व पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग का जन्म 1865 में बंबई (अब मुंबई) में हुआ। शिक्षा के लिए 1871 में इंग्लैंड चले गए। 1882 में भारत लौटे और अखबार में नौकरी शुरू की। 1886 में पहला कविता संग्रह व 1888 में लघु कथाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। 1894 में जंगल बुक ने ख्याति दिलाई। 1901 में उनका उपन्यास किम छपा। 1907 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 18 जनवरी 1936 को उनका लंदन में निधन हो गया।

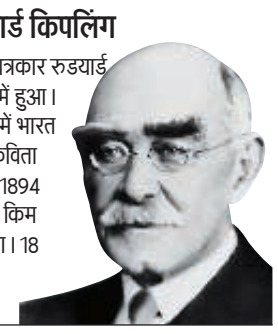

इधर-उधर की

यहां कविताओं से हो रहा मरीजों का इलाज

लंदन, एजेंसी : दुनिया में कविता के जरिये लोगों का इलाज करने वाले पहले अस्पताल को देखने और इलाज कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहां आने वाले ज्यादातर लोग रोजमर्रा के तनाव से परेशान होकर मदद की तलाश में यहां आते हैं। इसके पीछे देबोराह अल्मा का दिमाग है, जो कि यहां आने वालों को कविताओं की डोज देती हैं, न कि दवाइयों की। अल्मा खुद एक कवि हैं और अपनी दुकान में किताबें भी रखती हैं। उनका मानना है कि कविता थकावट और तनाव से टूटे दिलों की बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकती है। वह कविता कार्यशालाएं भी चलाती हैं। अपने 'रोगियों' को एक परामर्श कक्ष में आमंत्रित करती है, उनसे कुछ प्रश्न पूछती हैं और उनके लिए कविताओं का निर्धारण करती है। अल्मा वर्षों से डिमेंशिया के रोगियों के लिए काम कर रही हैं।

शोध अनुसंधान

सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है वायु प्रदूषण से बचना

वायु प्रदूषण से सेहत पर पड़ने वाले कई दुष्प्रभाव सामने आ चुके हैं। हालिया शोध में पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण से बचा रहे, तो उसकी सेहत पर कई सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। शोधकर्ता डॉ. डीन श्रॉफनेगल ने कहा, 'हम जानते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से लाभ होता है, लेकिन यह जानना वाकई आश्चर्यजनक है कि इससे कितना लाभ होता है। शोध में हमने पाया है कि प्रदूषण कम होने का सेहत पर तत्काल सकारात्मक प्रभाव होता है।' कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व शरीर के साथ-साथ दिमाग की सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। आसपास के वातावरण में जैसे ही इनकी मात्रा कम होती है, सेहत पर अच्छे असर दिखते हैं। - एएनआइ

अलग होते हैं ऑटिज्म वाले जुड़वां बच्चों के लक्षण

ऑटिज्म के शिकार जुड़वां बच्चों के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। यहां तक कि एक जैसे जीन होने पर भी उनके लक्षणों में फर्क दिखता है। ऑटिज्म के शिकार बच्चों को लोगों से घुलने-मिलने और बातचीत करने में समस्या होती है। हाल के अध्ययनों में सामने आया है कि जुड़वां बच्चों में अगर एक ऑटिज्म का शिकार हो, तो इस बात की 96 फीसद तक आशंका रहती है कि दूसरा बच्चा भी इसका शिकार हो। हालांकि दोनों बच्चों के लक्षणों में खासा फर्क देखने को मिला है। अगर दोनों बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित नहीं हों, तो उनमें अन्य लक्षण भी काफी हद तक एक जैसे ही रहते हैं। वैज्ञानिक अभी यह नहीं जान पाए हैं कि ऑटिज्म पीड़ित जुड़वां बच्चों में लक्षण अलग क्यों रहते हैं। इसे जानकर इसके इलाज में अहम कदम उठाए जा सकते हैं। - प्रेट्र

गिरगिट की तरह रंग बदलेगी नई स्मार्ट त्वचा

- एसीएस नैनो जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने किया दावा
- कहा- गर्मी और सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के अनुरूप बदलेगी रंग

स्मार्ट त्वचा। साभार : इमोरी यूनिवर्सिटी

वाशिंगटन, प्रेट्र: कुछ जीव-जंतु अपना रंग बदलने की खूबियों की वजह से जाने जाते हैं। इन्हीं जीवों में गिरगिट और टेट्रा मछली भी शुमार हैं, जो खुद को छिपाने, अपने साथी को आकर्षित करने या परभक्षी जीवों को भयभीत करने के लिए रंग बदलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने कृत्रिम 'स्मार्ट त्वचा' बनाने के लिए इन्हीं क्षमताओं की प्रतिकृति (नकल) बनाने की कोशिश की है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए शोधकर्ताओं ने गिरगिट की खूबियों के आधार पर एक लचीली स्मार्ट स्किन (त्वचा) विकसित की है। यह ऐसी त्वचा होगी, जो गर्मी और सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के अनुरूप अपना रंग बदलेगी।

यह अध्ययन एसीएस नैनो जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गिरगिट की त्वचा का रंग डाई के साथ-साथ फोटोनिक क्रिस्टल नामक एक छोटी संरचना पर भी निर्भर करता है। इसकी माइक्रोस्कोपिक सतहों से प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। फिर, प्रतिबिंबित प्रकाश के अन्य प्रकाशपुंज मिलकर उसे रोकते हैं, जिससे एक रंग उत्पन्न होता है। फोटोनिक क्रिस्टल के बीच दूरी में अंतर के आधार पर इसके रंग में अंतर आता है। इसीलिए जब भी हम किसी गिरगिट को प्रकाश में देखते हैं तो उसके रंग में बदलाव आते रहता है।

ऐसे तैयार की त्वचा : इन प्राकृतिक क्षमताओं का नकल करके वैज्ञानिकों ने लचीली सामग्रियों जैसे हाइड्रोजेल्स के साथ फोटोनिक क्रिस्टल को मिलाया और एक्रॉर्डिन नामक सामग्री को कम करके या उसे बढ़ाकर उनका रंग बदला। हालांकि, आकार में व्यापक लचीलापन पदार्थों में अधिक खिंचाव ला सकता है और उनमें तनाव की वजह बन सकता है।

कोशिका में ही होता है फोटोनिक क्रिस्टल : शोधकर्ता खालिद सलातिया और उनके सहयोगियों ने गिरगिट की त्वचा का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने जो पाया उसका प्रयोग बिना खिंचाव वाली स्मार्ट त्वचा के लिए किया।

शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि त्वचा कोशिका के महज छोटे से हिस्से में ही असल में फोटोनिक क्रिस्टल होता है, जबकि बाकी हिस्सा रंगहीन होता है। शोधकर्ताओं की टीम का कहना है कि यह मुमकिन है कि जब फोटोनिक क्रिस्टल सिकुड़ता और फैलता है, तो रंगहीन कोशिकाएं खिंचाव से सामंजस्य बिठाने में मदद करती हैं।

जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद : स्मार्ट त्वचा प्राकृतिक रोशनी पड़ने पर प्रतिक्रिया के तौर पर अपने रंग में भी बदलाव करती है। ठीक उसी तरह जैसे टेट्रा मछली अपने रंग बदलती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि नया शोध छद्मावरण, सिग्नल देने और जालसाजी रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

बायोसेंसर से होगी मधुमेह की जांच

तकनीक ▶ भारतीय शोधकर्ताओं ने विकसित किया स्वचालित उपकरण

शरीर में किया जा सकेगा प्रत्यारोपित, सुई चुभोने से होने वाले दर्द से भी मिलेगी निजात

डॉ. पी तमीलरासन। आइएसडब्ल्यू

फ्यूल सेल से संचालित होंगी मशीनें

यह उपकरण एक ऑर्गेनिक विद्युत रसायन ट्रांजिस्टर टाइप ग्लूकोज सेंसर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि एंजाइम आधारित फ्यूल सेल ग्लूकोज का उपयोग करके प्रत्यारोपण किए जाने वाले अन्य विद्युत उपकरणों को भी संचालित कर सकता है। उपकरण के डिजाइन, जैव-संरचना और जैविक परीक्षणों के आधार पर यह प्रौद्योगिकी व्यावहारिक अनुप्रयोग की ओर अग्रसर हो सकती है। यह अध्ययन शोध पत्रिका नेचर मैटेरियल्स में प्रकाशित किया गया है।

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : मधुमेह के स्तर का पता लगाने के लिए मरीजों को बार-बार रक्त का परीक्षण करता पड़ता है। शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा का पता लगाने के लिए अंगुली में सुई चुभोकर रक्त के नमूने प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं समेत अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने ग्लूकोज बायोसेंसर आधारित एक ऐसा स्वचालित उपकरण विकसित किया है जो लार के नमूनों से भी मधुमेह के स्तर का पता लगा सकता है।

इस ग्लूकोज बायोसेंसर से जुड़ी एक अहम बात यह है कि इसे शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। शरीर के भीतर यह बायोसेंसर बाहरी विद्युत ऊर्जा के बिना भी चल सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर में इस ग्लूकोज बायोसेंसर के प्रत्यारोपण के बाद बार-बार रक्त शर्करा के स्तर का परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी और मधुमेह की नियमित निगरानी की जा सकेगी। मधुमेह के स्तर का पता लगाने के लिए नए ग्लूकोज बायोसेंसर आधारित इस उपकरण के उपयोग से सुई चुभोने से होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिल सकेगा।

शोधकर्ताओं में शामिल सीएसआइआर-केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीइसीआरआइ) के वैज्ञानिक डॉ. पी. तमीलरासन ने बताया कि इस बायोसेंसर में गैर-मधुमेह और मधुमेह ग्रस्त रोगियों की लार के नमूनों की एक निर्धारित मात्रा पर ग्लूकोज की रैखिक प्रतिक्रिया देखने मिली है। इसका अर्थ है कि उपकरण से मिलने वाले परिणाम इनपुट के समानुपाती पाए गए हैं। इस उपकरण की मदद से चयापचय असामान्यताओं का शुरुआत में ही त्वरित एवं सटीक रूप से पता लगाया जा सकता है। मधुमेह सहित अन्य चयापचय रोगों की निगरानी, नियंत्रण और रोकथाम में यह उपकरण उपयोगी हो सकता है।

ऐसे तैयार किया उपकरण : शरीर के भीतर प्रत्यारोपित किए जाने वाले किसी भी उपकरण को संचालित होने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। लेकिन, मानव शरीर के भीतर विद्युतीय ऊर्जा उत्पन्न करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ग्लूकोज बायोसेंसर के निर्माण के साथ भी कुछ इसी तरह की समस्या जुड़ी थी, जिसके कारण ग्लूकोज बायोसेंसर का प्रत्यारोपण काफी जटिल कार्य था। इस बायोसेंसर को विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉन के वाहक एन-टाइप अर्धचालक पॉलिमर और एक खास एंजाइम का उपयोग किया है। एन-टाइप अर्धचालक पॉलिमर एवं एंजाइम का उपयोग शरीर के लार जैसे द्रव में ग्लूकोज स्तर के आनुपातिक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए किया गया है।

ऐस करता है काम : शोधकर्ताओं का कहना है कि पॉलिमर आधारित इलेक्ट्रोड का उपयोग ग्लूकोज सेंसिंग के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसी सामग्री से एंजाइम आधारित फ्यूल सेल विकसित किया गया है, जो शरीर के लार जैसे पदार्थों में मौजूद ग्लूकोज का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह ऊर्जा बायोसेंसर के संचालन में उपयोगी हो सकती है। पॉलिमर से बना एक ट्रांजिस्टर ग्लूकोज के स्तर का पता लगाता है, जो एंजाइम आधारित फ्यूल सेल से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह फ्यूल सेल भी उसी पॉलिमर इलेक्ट्रॉड से बना है, जिसे ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है।

क्रिस्टीना बनीं अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला

288 दिनों तक आइएसएस में रहने वाली पेगी व्हिट्सन का रिकॉर्ड किया अपने नाम

340 दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड स्कॉट केली के नाम है, जो 2015-16 के दौरान अंतरिक्ष में थे

अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच। फाइल/एपी

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना ने बीते शनिवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) में 288 दिनों तक रहने का नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिट्सन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।

पेशे से इंजीनियर क्रिस्टिना इस साल अक्टूबर में आइएसएस से बाहर आकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिलाओं की टीम में भी शामिल थीं।

स्पेक्ट्रम

आइएसएस में सबसे लंबे समय (340 दिन) रहने का रिकॉर्ड स्कॉट केली के नाम है, जो 2015-16 के दौरान अंतरिक्ष में थे। क्रिस्टीना ने बीते गुरुवार को अंतरिक्ष में लंबे समय तक सफलतापूर्वक रुकने में मदद के लिए पेगी का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने कहा, पेगी मेरी आदर्श रही हैं। आइएसएस में रहने के दौरान उन्होंने मेरा काफी मार्गदर्शन किया। धरती पर लौटने के बाद मैं भी अंतरिक्ष यात्रियों को मार्गदर्शन दूंगी।

खानपान ही नहीं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से भी बढ़ता है मोटापा

- यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेहेगन के शोधकर्ता ने किया दावा
- कहा-वजन बढ़ने के लिए यह 20 फीसद है जिम्मेदार

लंदन, आइएएनएस : अनियमित दिनचर्या और खानपान से मोटापा की संभावना बनी रहती है। अब एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि से भी मोटापे का जोखिम बना रहता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया की बढ़ती आबादी के अलावा पृथ्वी पर लोगों के शरीर के औसत आकार में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को चुनौती दे सकती है। ओबेसिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मोटापे के लिए 20 फीसद अधिक जिम्मेदार है।

डेनमार्क की यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेहेगन के शोधकर्ता फैदोन मैगकोस ने कहा, 'हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि रुग्णता, मृत्यु दर और स्वास्थ्य देखभाल की लागतों पर प्रभावों के अलावा मोटापे का प्रबंधन पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता है।'

शोधकर्ताओं के अनुसार, मोटापे से पीड़ित लोगों में सामान्य वजन वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म (चयापचय) से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। एक अनुमान के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर मोटापे के कारण प्रति वर्ष 700 मेगावॉट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जो सभी मानव निर्मित उत्सर्जनों का लगभग 1.6 फीसद है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है और ग्लोबल वार्मिंग खतरों से बचे रहना है तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने की सख्त जरूरत है।

कॉफी कप से बनाया तूतेनखामने का मुखौटा

मिस्र के गीजा स्थित संग्रहालय परिसर में कॉफी कप की मदद से प्राचीन मिस्र के राजा तूतेनखामेन के मुखौटे की कलाकृति तैयार की गई है। इसमें दस हजार से अधिक कपों का उपयोग किया गया। मिस्र के पिरामिड और ममी हमेशा से ही दुनियाभर में दिलचस्पी का विषय रहे हैं। राजा तूतेनखामेन का मुखौटा भी इसी का हिस्सा है। तूतेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के ग्यारहवें राजा थे। उनकी मृत्यु महज 17 साल की उम्र में हो गई थी। वर्ष 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद होवार्ड कार्टन ने सर्वप्रथम उनके मकबरे की खोज की थी। एपी

थ्रीडी आर्ट से जगमगाया पैलेस ऑफ जस्टिस

मलेशिया के शहर पुत्रज्या में आयोजित उत्सव के दौरान थ्रीडी आर्ट शो 'लाइट एंड मोशन' के जरिये रंग-बिरंगी लाइट्स से जगमगाता पैलेस ऑफ जस्टिस। इस उत्सव को लैंपू पुत्रज्या नाम से जाना जाता है। पैलेस ऑफ जस्टिस को वर्ष 2000 में सुल्तान अब्दुल समद ने क्वालालंपुर से पुत्राज्या में स्थानांतरित किया था। पिछले करीब सात साल से वर्ष के अंत में यह उत्सव मनाया जाता है। इसमें कई देशों के विश्व ख्याति के थ्रीडी आर्टिस्ट कला का प्रदर्शन करते हैं। रायटर

स्क्रीन शॉट

प्यार में पड़ना चाहती हूं : जाह्नवी कपूर

सात सवाल

फिल्म 'धड़क' से अभिनय की शुरुआत करने वाली जाह्नवी कपूर के पास पीरियड फिल्म 'तख्त', भारतीय लड़ाकू पायलट गुंजन सक्सेना की बायोपिक, हॉरर कॉमेडी फिल्म 'रूही अफ्जा' और 'दोस्ताना 2' जैसी फिल्में हैं। वह फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' के जरिए डिजिटल पर भी कदम रख रही हैं। उनसे बातचीत...

'धड़क' के बाद शुरुआती करियर में ही डिजिटल पर कदम रखने के बारे में क्यों सोचा?

- मुझे जोया अख्तर के साथ काम करने और उनसे सीखने का मौका मिल रहा था। ऐसे में वेब, टीवी या फीचर फिल्म जैसे माध्यम मायने नहीं रखते थे।

डिजिटल का स्पेस कैसा लग रहा है। चार शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर बनी फिल्मों के ट्रेंड को कैसे देख रही हैं?

- वेब भविष्य है। यहां अच्छे कंटेंट के लिए जगह है। यहां कलाकार, निर्देशक, लेखक, निर्माता हर कोई कमर्शियल दबाव के बिना काम करता है। 'घोस्ट स्टोरीज' को कमर्शियल फीचर फिल्म नहीं बनाया जा सकता था। कलाकारों को प्रयोग करने का मौका मिल रहा है।

हॉरर कॉमेडी 'रूही अफ्जा' में आप डबल रोल कर रही हैं?

- मैं जब 'रूही अफ्जा' और 'गुंजन सक्सेना' फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उसी बीच मुझे एक हफ्ते का वक्त मिला था। उस हफ्ते में मैंने 'घोस्ट स्टोरीज' की शूटिंग की थी। इसकी शूटिंग के बाद अगले दिन मैं 'रूही अफ्जा' के सेट पर पहुंच गई थी। मैं चार किरदार एक साथ निभा रही थी। 'रूही अफ्जा' में रूही और अफ्जा दोनों में ही निभा रही हूं।

आपकी मम्मी श्रीदेवी ने कभी हॉरर फिल्म नहीं की। आप पर किस तरह की हॉरर फिल्मों का प्रभाव रहा है?

- मम्मी ने हॉरर फिल्म भले ही न की हो, लेकिन उन्हें हॉरर फिल्में देखना पसंद था। मेरी सबसे पसंदीदा हॉरर फिल्म 'मधुमती' है। इसके अलावा 'स्त्री', 'भूल भुलैया' हॉलीवुड की 'सिक्स्थ सेंस', 'द शाइनिंग' जैसी फिल्मों का प्रभाव रहा है। हॉरर फिल्मों के परफॉर्मेंस प्रभावशाली होते हैं। जिन परिस्थितियों से किरदार गुजरते हैं, वे अजीब और मुश्किल होती हैं।

'रूही अफ्जा' के अलावा आपकी हर फिल्म से करण जौहर जुड़े रहे हैं। उनसे किस तरह की बॉन्डिंग है?

- मुझे जब खुद पर यकीन नहीं था, तब करण जौहर का यकीन मुझ पर कायम था। मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। उनके यकीन की वजह से मुझे खुद पर यकीन हो पाया है। मैं चाहती हूं कि मैं जो भी काम करूं, उस पर उन्हें गर्व हो।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना की जिंदगी पर फिल्म करने के बाद खुद में क्या बदलाव महसूस कर रही हैं?

- आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ देखा और जीया है। मैं उनसे कई बार मिली हूं। वह हीरो हैं। फिर भी कहती हैं कि उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया है। वह देश के लिए कुछ करना चाह रही थीं। उनकी कहानी से लड़कियां भी प्रेरित होंगी।

इतने जॉनर करने के बाद अब आप किस जॉनर की फिल्म करने की ख्वाहिश रखती हैं?

- एक लव स्टोरी फिल्म करना चाहती हूं। मुझे लव स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूं कि प्यार में पड़ जाऊं।

प्रियंका सिंह

अध्ययन

पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा- युवाओं से जुड़ी हिंसा की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बनाने की है जरूरत

समान प्रवृत्ति वाले किशोर होते हैं कम हिंसक

प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : युवाओं का व्यवहार काफी हद तक उनके आसपास के माहौल और वातावरण पर निर्भर करता है। इसी से जुड़ा एक शोध सामने आया है। इसमें बताया गया है कि ऐसे किशोर जो मानते हैं कि लड़के और लड़िकयां समान अवसर और सम्मान के हकदार हैं, उनके हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बहुत कम होती है।

अमेरिका की पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन में 13 और 19 साल के 866 लड़कों का सर्वे किया। यौन हिंसा रोकथाम संबंधी निवारण कार्यक्रम के प्रभाव को समझने के लिए यह अध्ययन अगस्त 2015 से जून 2017 के बीच किया गया। शोधकर्ताओं ने बताया कि इनमें लगभग 70 फीसदी किशोरों की पहचान अफ्रीकी अमेरिकी और पांचवां हिस्सा हिस्पैनिक, बहुजातीय या अन्य के रूप में की गई। इस हालिया अध्ययन के निष्कर्षों को अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में दावा किया गया है कि ऐसे किशोर, जिन्होंने हमउम्र के लड़कों से महिलाओं और युवतियों को गाली देते देखा या सुना वे दूसरों को अधिक तंग या परेशान करते हैं। वहीं, इस तरह के व्यवहार से दूर रहने वाले किशोर में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बहुत कम होती है।

...तो पांच गुना तक अधिक संभावना : ध्ययन में कहा गया है कि जिन 620 लड़कों ने कभी डेट किया, उनमें एक तिहाई में महिलाओं के प्रति अभद्र व्यवहार देखा गया। वह भी उनके साथ, जिनसे पिछले नौ महीने से डेट कर रहे थे। वहीं, सर्वे में भाग लेने वाले 56 फीसदी का कहना था कि वे यौन हिंसा में शामिल रहे। भले ही वे किसी के साथ डेट कर रहे थे या नहीं। 587 या 68 फीसदी शारीरिक हिंसा या धमकी देने या किसी हथियार से चोट पहुंचाने की गतिविधि में शामिल थे। ऐसे किशोर जिन्होंने अपनी बराबरी वालों को महिलाओं और युवतियों के साथ दो या अधिक बार अभद्र या बुरा व्यवहार करते देखा, उनमें अलग-अलग तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका दो से पांच गुना अधिक पाई गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि इनमें से कुछ व्यवहार का महिलाओं या डेटिंग से कुछ लेना-देना नहीं था।

मामलों का हल निकालना जरूरी : पीट्सबर्ग यूनिवर्सिटी और अध्ययन की सह-लेखिका एलिजाबेथ मिलर ने बताया, 'यह उस दावे को मजबूत करता है, जिससे महिलाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार जारी रहता है। साथ ही, युवतियां भी दूसरे लड़कों के साथ झगड़े में शामिल होती हैं। इस तरह के व्यवहार किसी बंद जगह में नहीं हो रहे हैं। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें अन्य मसलों का भी हल निकालना होगा।' शोध की सह-लेखिका एलिसन सिलबा ने बताया, 'यह अध्ययन बतलाता है कि युवाओं से जुड़ी हिंसा की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है।'

विशाल भारद्वाज की फिल्म में नजर आएंगी सारा अली खान

'केदारनाथ' और 'सिंबा' जैसी फिल्मों में अभिनेत्री सारा अली खान की परफॉर्मेंस को सराहा गया था। बतौर न्यूकमर उन्होंने दर्शकों को खुश किया, तभी तो कम समय में ही उनकी फैन फॉलोइंग काफी अधिक हो गई। अब सारा का ध्यान अपने दो प्रोजेक्ट्स पर है, जिनमें एक है इम्तियाज अली की फिल्म, जिसमें उनके अपोजिट कार्तिक आर्यन हैं तो दूसरी तरफ वरुण धवन के साथ 'कुली नं. 1' फिल्म है। अब खबर है कि वह बॉलीवुड के गंभीर माने जाने वाले निर्देशक विशाल भारद्वाज की फिल्म में भी दिखाई देंगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, 'विशाल ने सारा को अपनी नई स्क्रिप्ट सुना दी है और सारा ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए हां कर दी है। अब यह डील ऑन पेपर होने के इंतजार में है।' फिलहाल सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ केरल में छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं।

मां के लिए कवयित्री भी बन गई सारा

सारा का अपनी मां अमृता सिंह से काफी गहरा नाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अभिनेत्री ने यह बताया है कि वह अपनी मां से कितनी जुड़ी हुई हैं। असल में सारा ने सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी मां के लिए अंग्रेजी में एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है, 'मिरर मिरर'। इस कविता में सारा ने अपनी मां की खूब तारीफ की है।